सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

08 मार्च, 2018

षोडश विधान सभा 08 मार्च, 2018 ई0

------------- सोमवार, तिथि ----------------

नवम् सत्र 17 फाल्गुन,1939 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण,

आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है । महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्ष 1977 से संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा पारित संकल्प के अनुसार प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है । हर साल एक थीम होता है महिला दिवस का । इस वर्ष इसका थीम है प्रेस फॉर प्रोग्रेस । इसलिए आप सबों को खासकर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ संपूर्ण विश्व, देश एवं खास तौर से समस्त बिहार की महिलाओं को आप सबों की तरफ से, इस सदन की तरफ से हम शुभकामना देते हैं । इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है महिलाओं के लिये प्रेस फॉर प्रोग्रेस मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये हमलोगों को प्रेस करना चाहिये, दबाव बनाना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में आज अगर आप सभी माननीय सदस्यों की, अगर सदन की सहमति हो तो हमने देखा है कि आज के लिये सूचिबद्ध प्रश्नों में मात्र 10-11 हमारे माननीय महिला सदस्यों का प्रश्न है । सदन की सहमति हो तो हमलोग प्रेस फॉर प्रोगेस एडवांस उनको आगे करने के लिये हम सारे महिलाओं के प्रश्नों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू में ही ले लेते हैं । सदन की सहमति है ?

(सदन की सहमति हुई)

अब प्रश्नोत्तरकाल । आप ही लोगों के लिये है ।

(इस अवसर पर सभी महिला माननीय सदस्य वेल में आ गयीं और एक साथ बोलने लगीं ।)

अब लीजिये ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ।

अध्यक्ष : आसन और सदन को प्रसन्नता है कि कम-से-कम महिलाओं के मामले में सभी महिलायें और सदन एक जुट है, एक मत है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस सदन में आपके द्वारा विशेष अवसर प्रदान करने की कृपा की गयी है । इसके लिये हम आसन के प्रति आभार प्रकट करते हैं । महोदय, महिला दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हुये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सभी महिला माननीय

सदस्यागण अपनी-अपनी जगह पर जाय और विशेष अवसर का लाभ उठावें माननीय सदस्यागण।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग ऐसा मत बता दीजिये कि आप सशक्त हो चुकीं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यागण, आप सबों ने देखा है कि आपको अधिकार मिले, बढ़े हुये अधिकार मिले, इसके लिये यह सदन एक मत है । दूसरी बात, जो आप मांग कर रही हैं, वह इस सदन का विषय नहीं है । इसलिये इस मामले को यहां इस सदन में उठाने से कोई फायदा नहीं होगा । यह तो मामला संसद का है । चलिये, अब आप ही लोगों का प्रश्न है ।

(व्यवधान जारी)

श्री अवधेश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि जो महिला विधेयक लोक सभा से पारित है और इसमें सारे दल की महिलायें हैं । हम समझते हैं कि अगर आपके तरफ से यहां से एक रीकोमेंडेशन जैसाकि आपने कहा महिलाओं को प्राथमिकता देने का, एक अनुशंसा बिहार विधान सभा लोक सभा को भेजे कि महिलाओं का जो अधिकार है, जो आरक्षण है, उनको भारत सरकार लागू करे ।

(व्यवधान जारी)

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है, महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है, विधान सभा के अंदर भी और लोक सभा के अंदर भी । लेकिन महोदय, आर0जे0डी0 की महिलायें भी वेल में खड़ी हैं । मैं तो इनसे आग्रह करूंगा कि जब पार्लियामेंट में महिलाओं के अधिकार का बिल आया था, आरक्षण का बिल आया था, आर0जे0डी0 के लोगों ने विरोध किया था, आर0जे0डी0 के महिलाओं को अपने नेताओं पर दबाव बनाना चाहिए। यहां खड़ा हाने का क्या मतलब है ? उनको दबाव बनाना चाहिए अपने पार्टी के नेताओं पर । भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है इस पर । हम चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिले ।

(व्यवधान जारी)

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में इनकी सरकार है । इस राज्य में भी इनकी सरकार है । दोनों जगह महिलाओं पर राजनीति न करें । यदि महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं तो उनको खुली छूट है, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा समर्थन रहेगा । महिलाओं के लिये राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही बहुत काम किया है ।

(व्यवधान जारी)

पहली महिला मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल ने ही दिया है । मैं एन0डी0ए0 के माननीय लोगों से मांग करता हूं कि यदि वे केन्द्र में लागू करना चाहते हैं, राज्य में लागू करना चाहाते हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो राष्ट्रीय जनता दल इसका समर्थन करता है ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, हमने तो बात किया है, जो अबतक आर0जे0डी0 के लोगों ने किया है । महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने तो भारत का विदेश मंत्री महिला को बनाया है, रक्षा मंत्री भारत का महिला को बनाया है महोदय । राज्यों के मुख्यमंत्री महिलाओं को बनाया है । लेकिन भोला बाबू की बात का आर0जे0डी0 में क्या वजन है महोदय । जो आर0जे0डी0 के कर्ता-धर्ता हैं, वे बयान दें कि वह आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे । क्या वजन है इनलोगों का महोदय ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : एक मिनट । देखिये, पूरे सदन ने आपके प्रश्नों को प्राथमिकता से करने का निर्णय लिया है और देख रहे हैं कि आपके मामले को पुरूष लोग छिन रहे हैं । इसलिए आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाय।

(व्यवधान जारी)

हो गया, हो गया । चलिये । आपलोगों का ही प्रश्न है । प्रश्न संख्या-738(श्रीमती लेशी सिंह)

(इस अवसर पर सभी महिला माननीय सदस्या वेल से अपने-अपने स्थान पर चली गयीं ।

श्रीमती ऐज्या यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देती हूं कि आज वूमेन डे है और हमारी पार्टी जो आर0जे0डी0 है, एक मिसाल कायम की थी, वूमेन मुख्यमंत्री बनायी थी बिहार में और अभी चूंकि डबल इंजन की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी को काफी सुविधा हो गयी है डबल इंजन की वजह है तो इसमें हम एक मांग करते हैं कि कम-से-कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक वूमेन को बना दें ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/8-3-18

तारांकित प्रश्न संख्या-738(श्रीमती लेशी सिंह)

अध्यक्ष: आज सूचिबद्ध प्रश्नों में से हम सरकार और माननीय सदस्या जो हैं, उन सभी को भी सूचित कर देना चाहते हैं कि आज सदन की सहमति से जितने महिलाओं का प्रश्न है प्राथमिकता से हमलोग पहले लेंगे और फिर बाकी बाद में लिये जायेंगे क्योंकि इस बार अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है- प्रेस फॉर प्रोग्रेस, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए दवाब डालिये तो हमलोग, सदन पूरा इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ।

माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ट्रांसफर किया गया है गन्ना उद्योग विभाग को ।

अध्यक्ष: गन्ना उद्योग विभाग को स्थानांतरित ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 749(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय (1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी द्वारा वर्णित योजना की तकनीकी अनुमोदन दिनांक 24-6-2017 को प्रदान किया जा चुका है । अब इस पर हम काम करवा देंगे ।

श्री सुनीता सिंह चौहान: महोदय, माननीय मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि जिन पदाधिकारी ने यह जवाब दिया है, वे सरकार को गुमराह कर रहे हैं । जब सड़क का निर्माण कार्य सात निश्चय के तहत था तो कार्यपालक पदाधिकारी, बेलसंड द्वारा 1 नवम्बर, 2016 को जिला शहरी विकास अभियंत्रण को प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के लिए किस योजना के तहत भेजा गया था ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पूछ रही है माननीय सदस्या कि किस योजना से इसका क्रियान्वयन होगा।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: ये हमारा जो है नगर विकास और जो सात निश्चय है उसके तहत था और ये बाद में हुआ है, इसको हमलोग दे दिये हैं, इसका काम हम बहुत जल्दी शुरू करवा देंगे।

अध्यक्ष: ठीक है।

श्री सुनीता सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: आपका और है? ठीक है एक और पूरक पूछ लिजिये आज तो आपहीं लोगों का दिन है कौन रोकेगा ।

अध्यक्ष: जी धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूॅं, जितना जल्दी हो सके, उसे करवा दें।

तारांकित प्रश्न संख्या-755(श्रीमती अरूणा देवी)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न अस्वीकारात्मक है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पंचायत, वारसलिगंज की कुल जनसंख्या 34 हजार 56 है । बिहार नगरपालिका अधनियम, 2007 की धारा (3)के प्रावधानानुसार मध्यम शहरी क्षेत्र के गठन की दशा में कुल जनसंख्या 40 हजार या उससे अधिक 2 लाख के अन्दर होना चाहिए परन्तु दर्शाये गये गैर कृषि जनसंख्या 75 प्रतिशत है जबकि इससे अधिक होना आवश्यक है । अत: उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार पंचायत वारसलिगंज को नगर परिषद का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 756(श्रीमती प्रेमा चौधरी)

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री: महोदय, समाहर्त्ता, वैशाली के प्रतिवेदनानुसार वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर अंचल के तीसिऔता पंचायत के पिण्डौता ग्राम में बास कर रहे हैं महादलित एवं अत्यंत पिछड़े वर्गो के परिवारों को बास हेतु भूमि का पर्चा दिया जा चुका है, शेष बचे हुए परिवार को बासगीत पर्चा निर्गत करने हेत संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन के माध्यम से अंचल अधिकारी, पातेपुर के समक्ष प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । बासगीत पर्चा निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी: महोदय, लगभग 2-3 महीना पहले मैं वहां गयी थी तो वहां लोगों ने बताया कि एक भी बासगीत पर्चा वहां नहीं मिला है और सारे अंचल में और जहां तक मुझे पता है और सर्वे के मुताविक भी हम घुम घुमकर देखें हैं, जहां जहां दलित लोग बसे हुए हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है लेकिन उनको रहने का कोई व्यवस्था नहीं है और जहां का यह क्वेश्चन है मेरा पिण्डौता ग्राम का, वहां किसी को नहीं मिला बासगीत पर्चा और हमने कहा भी था सी0ओ0 को कि आप स्वयं देखकर के उसका स्थल निरीक्षण करके उनको बासगीत पर्चा देने को कहा था लेकिन अभी तक मुझे सूचना है कि उनको पर्चा नहीं मिला है इसलिए हम चाहेंगे विधान-सभा के माध्यम से कि उसका सर्वे कराया जाय और पिण्डौता ग्राम ही नहीं हम चाहेंगे कि पूरे प्रखंड का उसका सर्वे कराकर के जो बाकी है उसको पर्चा मिले और कबतक कराया जायेगा, यह बतलाया जाय।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इनका कहना है कि ये स्वयं गयी थी और वहां पर लोगों ने शिकायत की है कि उनको पर्चा नहीं मिला है । आप कर्मचारी का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो इसको एस0डी0ओ0 से दिखवा लीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री: जी हम वहां के एस0डी0ओ0 से दिखवा लेंगे ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी: कबतक दिखवाया जायेगा ? हमको बतला दिया जाय तो हम भी..

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री: महोदय, तुरंत दिखवा लेंगे और माननीय सदस्य को भी उनके साथ लगा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 780(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री प्रेम कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड में ई-किसान भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक 652 दिनांक 30-8-17 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से अनुरोध किया गया है । जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 285 दिनांक 1-3-2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचलाधिकारी, परसौनी के पत्रांक 83 दिनांक 28-2-18 द्वारा सूचित किया गया है कि परसौनी प्रखंड में ई-किसान भवन हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि वर्त्तमान में उपलब्ध नहीं है । सरकार द्वारा परसौनी अंचल एवं प्रखंड परिसर हेतु 4 एकड़ 64 डी0 भूमि के अधिग्रहण हेतु राशि जिला को उपलब्ध करा दी गयी है । भूमि अधिग्रहण के उपरांत ई-किसान भवन का निर्माण कराया जायेगा ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूॅ कि यह सरकार कृषि पर विशेष ध्यान देती है और प्रतिवर्ष कृषि के बजट में चार पांच गुणा वृद्धि भी हुई है । बजट में ई-किसान भवन के लिए प्रावधान भी किया गया है लेकिन वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में भूमि उपलब्ध रहने के वाबजूद भी ई-किसान भवन के निर्माण हेतु जिले को राशि क्यों नहीं आवंटित की गयी है? महोदय, कल ही कृषि बजट पर घोषणा की गयी कि अब साल में तीन वार किसान चौपाल का आयोजन किया जायेगा तो माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि परसौनी में ई-किसान भवन ही नहीं बना है तो चौपाल कहां लगेगा ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: महोदय, किसान चौपाला लगाने का जो हमारा प्रोग्राम है वह पंचायत स्तर पर है और ई-किसान भवन का कंसेप्ट जो सरकार का महोदय है वह प्रखंड लेबल पर है । जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है, हम निश्चित तौर पर जैसा कि उन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध था तो इसकी जांच हम करवा देते है और हमार प्रयास होगा, जल्द से जल्द राशि उपलब्ध करवाकर ई-किसान भवन का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री सुनीता सिंह चौहान: कबतक जांच करवाकर के बनवा देंगे, समय सीमा निर्धारित कर दें ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: हम जांच तो महोदय एक सप्ताह के अन्दर करवा देते हैं यदि जमीन था और रिपोर्ट गलत आया है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी और जैसे ही जिलाधिकारी के द्वारा जमीन उपलब्ध करा दिया जायेगा महोदय तो एक महीने के अन्दर जमीन उपलब्ध होने के बाद हमलोग काम शुरू करा देंगे ।

श्री सुनीता सिंह चौहान: महोदय, पंचायती राज एवं नगर विकास के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आभार प्रकट करती हूॅ ।

टर्न-3/मधुप/08.03.2018

श्री मो0 इलियास हुसैन : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अभी तो पुरूष माननीय सदस्य की गुंजाइश नहीं है ! बोलिये इलियास साहब ।

श्री मो0 इलियास हुसैन : महोदय, राज्य का नीतिगत मामला उठाया गया है । हमारे रोहतास जिले के कृषि मंत्री प्रभारी मंत्री भी हैं, वहॉ अकोढ़ीगोला प्रखंड स्थित तेतराढ़ में एक साल पूर्व से किसान भवन बना हुआ है, लापरवाही चाहे जिसकी हो सरकार या पदाधिकारी की, उसके सारे चौकट उखाड़ लिये गये हैं, शीशा तोड़ दिये गये हैं, अब दीवाल बाकी है उसमें भी हाथ लग गया है, उद्घाटन नहीं हो सका है ।

अध्यक्ष : वह सूचना दे दीजियेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपने अनुमति दिया है केवल महिला को, इलियास साहब को क्या माना जाय ? इनका कुछ बदल गया है क्या ?

तारांकित प्रश्न संख्या-782 (श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, यह क्षेत्र जो है, बोचहाँ में पड़ता है, मतलब नगर निगम के अन्तर्गत नहीं है, पंचायत में आता है । इसलिये इसको स्थांतरित किया जाय ।

अध्यक्ष : इस प्रश्न को ग्रामीण विकास विभाग को स्थांतरित किया जाता है ।

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे अपने भी माध्यम से यह काम जल्दी करवा दें, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ।

अध्यक्ष : मंत्री जी को आप कह रही हैं कि एक ही जिला से आते हैं इसलिये यह काम जल्दी करा दें और आप एक ही जिला से आते हैं इसलिये मंत्री जी अपने दायरे से ही काम को बाहर बता रहे हैं ।

श्रीमती बेबी कुमारी : लेकिन मुसहरी अंचल इन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, उसमें लाईटिंग एरेंजमेंट जो है, वह हम करवा देंगे ।

श्रीमती बेबी कुमारी : धन्यवाद ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : महोदय, माननीय सदस्या का जो क्वेश्चन था, नगर विकास विभाग से ट्रांसफर होकर नगर विकास विभाग में गया, हम चाहेंगे कि आज महिला दिवस है, महिलाओं के लिये विशेष छूट है और महिलाओं का जो भी क्वेश्चन है, हमें लगता है कि क्वेश्चन का जवाब मिल जायेगा, उनके क्षेत्र का उद्धार हो जायेगा । हम चाहेंगे कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी से उनका जवाब दिलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : पूनम जी, आपने तो देखा कि महिला दिवस होने के कारण जिला की नजदीकी होने के कारण एक बार बता देने के बाद भी कि यह माननीय मंत्री के विभाग से संबंधित नहीं है, फिर भी इन्होंने कहा कि हम इसको देखवा करके करवा देंगे । अब इससे अधिक क्या चाहिये ?

तारांकित प्रश्न संख्या- 785 (श्रीमती लेशी सिंह)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ, 2017 मौसम में कुल 19 जिलों यथा कटिहार, मधुबनी, सहरसा, सीवान, गोपालगंज, मधेपुरा, सारण, पश्चिमी चम्पारण, अररिया, पूर्वी चम्पारण, पूर्णिया, शिवहर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, खगड़िया एवं सुपौल के लिए कार्यभारित तीन बीमा कम्पनी यथा

भारती एक्सा, ए0आई0सी0 एवं चोला मंडलम द्वारा कुल 4,88,098 किसानों का फसल बीमा की गई है ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं0 5837 दिनांक 24.07.2017 की कंडिका 7 में फसल अवधि में हुये नुकसान, फसल कटनी के उपरांत नुकसान तथा स्थानीय आपदा की स्थिति में व्यक्तिगत फसल क्षति के आकलन हेतु अलग-अलग संयुक्त समिति गठित है । योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार फसल अवधि में बाढ़, दीर्घकालिक शुष्क मौसम आदि जिसमें वास्तविक उपज थ्रेशहोल्ड उपज के 50 प्रतिशत से कम होने की संभावना निश्चित हो तो बीमित किसानों को तत्काल 25 प्रतिशत तक की अधिसीमा में क्षतिपूर्त्ति अनुमान्य हो सकता है जो फसल कटनी प्रयोग पर आधारित अंतिम अनुमान्य क्षतिपूर्त्ति राशि के विरूद्ध समायोजन योग्य हो ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.01.2018 को खरीफ, 2017 मौसम हेतु अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा फसल कटनी प्रतिवेदन संबंधित बीमा कम्पनी को प्राप्त कराया जा चुका है तथा बीमा कम्पनी के द्वारा क्षतिपूर्त्ति की गणना की जा रही है । इस प्रकार गणना की गई सम्पूर्ण क्षतिपूर्त्ति का भुगतान एकमुश्त किया जा सकेगा ।

श्रीमती लेशी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है, अगस्त में बाढ़ आई लेकिन अभी तक आकलन नहीं हुआ है । क्या औचित्य है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जबकि सरकार किसानों के प्रति सजग है, फिर भी आकलन नहीं किया गया है ताकि किसानों को समुचित लाभ मिल सके ।

अध्यक्ष : आंकड़े उपलब्ध कराकर किसानों को सहायता मुहैया कराने की बात कह रही हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा आकलन करके दिया गया है और जनवरी में ही यह प्रतिवेदन बीमा कम्पनी को प्राप्त हो गया है । कुछ विलम्ब हुआ है, अब इसको जल्द से जल्द कराने के लिये पुनः विभाग के द्वारा निदेशित किया गया है कि जितने फसल की क्षति हुई है, उसका आकलन करके किसानों को जल्द से जल्द भुगतान कम्पनी करावे, यह निर्देश विभाग के द्वारा जारी किया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्यों अभी पुरूष लोग बीच में खड़े हो जा रहे हैं ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 789 (श्रीमती एज्या यादव)</u>

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । राजस्व अधिकारियों की कमी के कारण समस्तीपुर जिला के मोहनपुर अंचल में अंचलाधिकारी का रिक्त पद है जिसके कारण इन्द्रदेव पंडित प्रभारी अंचलाधिकारी, शाहपुर पटोरी मोहनपुर अंचल के अतिरिक्त प्रभार में

हैं । श्री पंडित के द्वारा मोहनपुर अंचल के राजस्व से संबंधित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है ।

राजस्व अधिकारी के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग के स्तर से दो अधियाचना क्रमशः विभागीय पत्रांक 173(3)रा0 दिनांक 28.04.2016 से कुल 175 अभ्यर्थियों एवं विभागीय पत्रांक 291(3)रा0 दिनांक 20.06.2017 द्वारा 19 अभ्यर्थियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है । अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त होने पर रिक्त अंचलों के अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन किया जायेगा । बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रियाधीन है ।

श्रीमती एज्या यादव : सर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि यह कबतक हो पायेगा क्योंकि पटोरी प्रखंड के जो अंचलाधिकारी हैं, वे बिल्कुल भी कांपीटेंट नहीं हैं । मोहनपुर का प्रभार दिया हुआ है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ के लोग गरीब हैं, आने-जाने में काफी पैसा और समय बर्बाद हो जाता है, दिनभर की मजदूरी चली जाती है तो थोड़ा शीघ्र किया जाय और कबतक यह कर दिया जायेगा ? यह बता दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : शीघ्र ही हो जायेगा ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ । जब आज महिला दिवस है तो आसन पर महिला पीठासीन पदाधिकारी बैठतीं तो अच्छा रहता और सदन की गरिमा बढ़ती ।

अध्यक्ष : हम माननीय सदस्य भोला जी के साथ पूरे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि जिस चीज के प्रति भोला जी ने चिन्ता प्रकट की है, आसन ने उसका पूर्व से ही पूरा ख्याल रखा है और जो हमारे पैनल में अध्यासी सदस्य हैं, उसमें एक महिला डॉ0 रंजु गीता जी हैं, मैंने उनको कह दिया है कि आज मेरे बाद सदन का पूरा संचालन उन्हीं को करना है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 809 (श्रीमती प्रेमा चौधरी)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग को यह प्रश्न स्थांतरित किया गया है । मैं माननीय सदस्या को महिला दिवस के अवसर पर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ग्रामीण कार्य विभाग से दिखवा कर शीघ्र इस काम को करवा दूँगा ।

अध्यक्ष : काफी संवेदनशीलता है !

टर्न-4/आजाद/08.03.2018

श्रीमती प्रेमा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि इसमें मामला यह भी बनता है, यह सड़क का ही नहीं है, इसको जमीन खरीद करके रास्ता निकालने का मामला है और यह

वर्षों-वर्षों से पड़ा हुआ है और लोग वहां बरसात के दिनों में कपड़ा उठाकर पार करते हैं और महिलायें तो आ ही नहीं सकती है बिना नाव के तो हम चाहेंगे कि इसको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी अपने स्तर से जॉंच करवा ले और ग्रामीण कार्य को कहा जाय कि यह सड़क जैसे भी बने, बना दिया जाय क्योंकि वहां पर बिन्द जाति के लोग रहते हैं और बहुत ही मतलबी इंसान रहते हुए भी जानवर से बदतर स्थिति में वहां लोग जीवन गुजार रहे हैं । इसलिए हम चाहेंगे कि इसपर अलग से ध्यान दिया जाय ।

अध्यक्ष : वैसे भी प्रेमा जी, आपका यह प्रश्न अब आगत हो गया और अगर यह ग्रामीण कार्य विभाग में भी स्थानान्तरित हुआ है तो जिस दिन वर्ग में ग्रामीण कार्य विभाग रहेगा, आपका यह प्रश्न उस दिन प्राथमिकता से फिर आयेगा ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : धन्यवाद ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय अध्यक्ष महादेय, जिन माननीय महिला सदस्या का क्वेश्चन नहीं है तो हमलोगों को भी मौका दिया जाय ।

अध्यक्ष : अभी आप ठहरिये न । आपका क्वेश्चन नहीं है । माननीय सदस्या श्रीमती अमिता भूषण ।

तारांकित प्रश्न सं0-811 (श्रीमती अमिता भूषण)

श्री पशुपति कुमार पारस,मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय में 136 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र में से 13 जगह कार्यरत है । शेष कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को चालू करने हेतु कर्मचारियों की कमी है । नियुक्ति होते ही उसपर भी कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-818 (श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह भी प्रश्न भवन निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किया गया है, चूँकि चहारदिवारी से जुड़ा हुआ है और आज महिला दिवस पर माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसे दिखवा कर हम करवा देंगे ।

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है तो माननीय मंत्री जी, एक समय सीमा तय करा दें कि कब तक करवायेंगे ?

अध्यक्ष : यह तो अभी दूसरे विभाग में जा रहा है, आपका यह प्रश्न अगले दिन भी आयेगा, तब उस दिन सब पूरक आप पूछ लीजियेगा ।

श्रीमती बेबी कुमारी : ठीक है सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-826 (श्रीमती गायत्री देवी)

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : यह स्थगित हुआ ।

श्री भोला यादव : हुजूर, माननीय पथ निर्माण विभाग मंत्री जी को, महिला दिवस पर तैयार होकर आना चाहिए , क्या ये महिला का सम्मान नहीं करते हैं ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, कौन कितना महिला का सम्मान करता है, भोला जी ज्यादा जानते हैं महोदय ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोग दो-चार महिला सदस्य बच गये हैं, जिनका क्वेश्चन नहीं है तो महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमलोगों का भी क्वेश्चन सुन लिया जाय और उत्तर दिलवा दिया जाय ।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है........

अध्यक्ष : अभी आप क्वेश्चन पूछ दीजियेगा, अभी कौन जवाब देगा । आप बैठिए, अब पुरूषों की बारी है ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : महोदय, एक मिनट मेरा सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : बोलिये एक मिनट ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : महोदय, महिला दिवस के मौके पर हम चाहेंगे सदन के माध्यम से कि महिलाओं को आपके तरफ से कुछ तोहफा सदन में मिलनी चाहिए ।

अध्यक्ष : असल में सारे पुरूष सदस्य बता चुके हैं कि ये लोग अपने घर में गिफ्ट देकर आये हैं ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : लेकिन हमलोग आपसे मांग रहे हैं अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : यह तो आपके घर में पता करना होगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-737(श्री नौशाद आलम)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुजाहिद आलम पूछेंगे । माननीय मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, खंड-1 स्वीकारात्मक है ।

खंड-2 समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-150रा0 दिनांक 15.02.2018 से प्राप्त निर्देश की कंडिका-4(1) के आलोक में भू-अर्जन परियोजना के लिए भूमि का वर्गीकरण सामान्यत: भू-अर्जन हेतु अधिसूचना प्रकाशन के समय उसके स्वरूप उपयोग के आधार पर किये जाने का निर्देश प्राप्त है । अररिया-गलगलिया, न्यूबिजी रेल लाईन निर्माण परियोजना की प्रारंभ अधिसूचना दिनांक 11.06.2017 को, अधिघोषणा 13.06.2017 को किया गया । तदनुसार ही प्रश्नगत परियोजना में भूमि वर्गीकरण का कार्य किया जा रहा है । प्रश्न में वर्णित पत्र मद्य निषेध,उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा दिनांक 18.12.2017 को निर्गत किया गया है । जो प्रारंभिक अधिसूचना एवं अधिघोषणा निर्गत की तिथि के बाद की तिथि का है । प्रश्नगत परियोजना में धारा-121 के अन्तर्गत हितबद्ध

व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किया जा चुका है । प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई विभागीय पत्रांक-150रा0 दिनांक 15.02.2018 के कंडिका 4 (1) द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में किया जा रहा है ।

खंड-3 कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री मुजाहिद आलम : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं पूछना चाहूँगा कि जो किसानों के हित का मामला है, जिसमें ठाकुरगंज प्रखंड के दल्लेगांव मौजा में नूरजहां बेगम, गुलाम हसनैन, मो0 इदरीश, नसीमा बेगम, इकबाल, जमील अख्तर, इसी ठाकुरगंज प्रखंड के ततपौआ मौजा में शहादत हुसैन, मुजफ्फर आलम, सैफुन निशा, इनकी जमीन को अधिग्रहण के लिए जो नोटिश दिया गया है, जो सरकारी अधिसूचना है, उसके विपरीत इन लोगों को दो फसला मुआवजा की बात कही गयी है, जिसके कारण सारे किसान आन्दोलनरत हैं, यह किसानों के हित का मामला है । इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूँगा कि आप माननीय मंत्री महोदय को, विभाग को निर्देशित करें कि निबंधन विभाग का जो सरकुलर जारी हुआ है कि कोई भी गांव के अंतिम जो व्यक्ति है, अंतिम घर है, उसके चारों तरफ 200 मीटर के परिधि की जमीन है, भूमि है, वह आवासीय होगा, उस आधार पर मुआवजा दिलवाने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : ये जो सरकुलर कह रहे हैं ....

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसी सरकुलर के आधार पर समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा भूमि का अर्जन करके यह प्रतिवेदन दिया गया है । यही जो निर्देश है ....

अध्यक्ष : मुजाहिद जी, आप अपनी आपत्ति सब लिखकर दे दीजयेगा, ये उसकी जॉच करवा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : ये दे देंगे, हम उसकी जॉच करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-739 (श्री शकील अहमद खॉ)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज जी पूछेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, खंड-1 अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत प्रश्नाधीन प्रखंड में डंडखोरा में ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजना अन्तर्गत 50हजार गैलन क्षमता का जल मिनार का निर्माण 2011-12 में कराया गया है । जल मिनार के माध्यम से जलापूर्त्ति की जा रही है ।

खंड-2 आंशिक स्वीकारात्मक है । प्रेमनगर टोला एवं अल्पसंख्यक टोला में योजना से जलापूर्त्ति विद्युत आपूर्त्ति की उपलब्धता के अनुरूप की जाती है । पूर्व में पाईप लाईन में लीकेज के कारण जलापूर्त्ति बाधित थी, जिसे मरम्मत कराकर जलापूर्त्ति चालू कर दिया गया है ।

उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महादेय, मंत्री जी को गलत जानकारी दी गई है । अभी तक न खराब फिल्टर को ठीक किया गया है और न जलापूर्त्ति शुरू की गई है । माननीय मंत्री जी, इसकी जॉच करवा लीजिए और जो गलत बयानी या गलत उत्तर भेजने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजियेगा ?

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य के उपस्थिति में जॉच करवा लेंगे और जो भी दोषी अधिकारी होंगे, उनके विरूद्ध कार्रवाई करेंगे ।

टर्न-5/अंजनी/दि0 08.03.2018

तारांकित प्रश्न संख्या-740(श्री शमीम अहमद)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को स्थांतरित किया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-741(श्री विनय बिहारी)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-742(श्री रत्नेश सादा)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, यह भी प्रश्न स्थांतरित किया गया है ।

अध्यक्ष : यह शिक्षा विभाग को जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, यह शिक्षा विभाग को ही स्थांतरित किया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-743(श्री विजय कुमार खेमका)

अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिए सचीन्द्र जी प्राधिकृत हैं ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के नगर निकायों में शवदाह गृह निर्माण हेतु नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए अलग-अलग मॉडल प्राक्कलन तैयार कराया गया है, जिसमें नगर निगमों में दो फरनेश का विद्युत शवदाह गृह और 6 पेरीवाला परम्परागत शवदाह गृह, नगर पर्षदों में एक फरनेश का विद्युत शवदाह गृह और 4 पेरीवाला परम्परागत शवदाह गृह तथा नगर पंचायतों के लिए दो पेरीवाला परम्परागत शवदाह गृह का प्राक्कलन तैयार किया गया है । विद्युत शवदाह गृह के विद्युत विपत्र के भुगतान में नगर निकायों की भविष्य में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए तत्काल पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में विद्युत शवदाह गृह निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, जिसपर अगले वित्तीय वर्ष में कार्रवाई की जायेगी । परम्परागत शवदाह गृह निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा गोरखपुर में शवदाह गृह के लिए प्रयुक्त

किये जा रहे कम ईंधन, कम लागत और कम प्रदूषण वाले शवदाह यंत्र का अध्ययन करने हेतु अध्ययन दल गठित कर भेजा जा रहा है । यह शवदाह यंत्र परम्परागत तरीकों से बिना बिजली, कम लागत, कम ईंधन और कम प्रदूषणयुक्त होगा । अगर अध्ययन दल इस यंत्र के संबंध में सकारात्मक प्रतिवेदन दिया जाता है तो इसके व्यापक इस्तेमाल के लिए नीतिगत निर्णय लिया जायेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गोरखपुर जिस किस्म के शवदाह गृह बनाने के तरीकों के खोज के लिए अपने अध्ययन दल को भेज रहे हैं, जब तक वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आता है, तबतक क्या शवदाह गृह बिहार में बनाने का कोई निर्णय नहीं है ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, शवदाह गृह परम्परागत ढंग से बनाने का निर्णय लिया गया है और जो गोरखपुर का है, उसका भी हमलोग अध्ययन करा लिये हैं, उसमें 100 किलो लकड़ी से ही दाह संस्कार परम्परागत ढंग से हो सकता है, इसलिए उसको हमलोग लागू बहुत जल्दी करने जा रहे हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो लकड़ी से शवदाह गृह बनाने की बात मंत्री जी कर रहे हैं, गोरखपुर का जो मॉडल है, वह बिहार में आयेगा तो यहां जो विद्युत शवदाह गृह बनाये जा रहे हैं या बनाने का प्रोवीजन नगर विकास विभाग के पास है, क्या उसको बंद कर दिया जायेगा ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, उसको बंद करने का नहीं है लेकिन यह चैम्बर बना हुआ है, जिसके अन्दर उसको दाह संस्कार के लिए कराया जायेगा, वह इम्प्रुव्ड क्वालिटी है, उसमें पैसा भी कम लगेगा, इसलिए वह ज्यादा उपयुक्त है लेकिन परम्परागत ढंग का जो शवदाह गृह है, उसको बनाने का जहां से भी आ रहा है, हम वहां के लिए फंड दे रहे हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय,.....

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, एक मिनट । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में उस योजना को लागू की जायेगी तो क्या उससे कम आबादी वाले जो नगर निगम हैं या नगर निकाय हैं, नगर पंचायत हैं, वहां यह योजना लागू नहीं की जायेगी ?

अध्यक्ष : फर्स्ट फेज में वह होता है न ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि पांच लाख से उपर वाले में अगले साल से किया जायेगा और पूरे बिहार में पांच लाख से उपर वाले में केवल पटना है और पटना में ऑलरेडी विद्युत शवदाह गृह है तो अगले साल माननीय मंत्री जी कौन से शहरों में, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि

अगले वित्तीय वर्ष में हम विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करायेंगे लेकिन पांच लाख से उपर वाले शहर में तो पांच लाख से उपर वाले शहर पटना के बाद कोई शहर बचता ही नहीं है तो मेरा यह कहना है कि पटना के बाद जो 7-8 नगर निगम बिहार में हैं, उसमें कम-से-कम प्राथमिकता के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में करा दें क्योंकि एक भी शहर बचता नहीं है ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति जिस नगर निगम की सुदृढ़ होगी, वही बिजली का भुगतान कर सकेगा । अगर उस तरह का रिपोर्ट आयेगा तो वहां भी हम देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-744(श्री मो0 नवाज आलम)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

सम्प्रति योजना का संचालन के साथ मरम्मती एवं सम्पोषण का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा चार नये जल मीनारों से जलापूर्त्ति चालू है । प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिये गये पत्रांक के अनुसार नगर विकास विभाग के अब तक प्रभार नहीं लेने एवं तकनीकी बल अनुपलब्धता के कारण आरा शहर में विभाग द्वारा ही जलापूर्त्ति एवं मरम्मती की जा रही है ।

श्री(मो0) नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ठीक इन्होंने कहा कि नगर विकास ने अभी तक प्रभार नहीं लिया । जिस जिले का नगर आयुक्त शराब पीते हुए मिटिंग में पकड़ा जाता हो और तमाम चीजें संज्ञान में आयी है, डी0एम0 ने उसको इस तरह की बात लेने का काम किया। वहां आपके विभाग की हालत यह है कि लगातार दो सालों से उस जल मीनार से जलापूर्त्ति के मेन्टेनेंस के संबंध में सदन में और मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में भी रखने का काम किया, इसलिए माननीय मंत्री जी गंभीरता से लें, हो सकता है कि विभाग ने इनको लापरवाही से कहीं बताने का काम नहीं किया है और नगर निगम की नारकीय स्थिति बनी हुई है, इसलिए आपका संरक्षण लेते हुए माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या आप विधान सभा की कमिटी बनाकर उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं और रखते हैं तो कबतक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको देखवा लीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, इसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-745(श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, शिकायत के आलोक में मामले की जांच जिला कृषि पदाधिकारी के पत्रांक 383 दिनांक 15.02.18 द्वारा गठित कमिटी द्वारा दिनांक 27.02.2018 को

किया गया । कमिटी द्वारा शिकायत प्राप्त किसानों के खेत में जाकर वस्तुस्थिति की जांच की गयी । जांच में पाया गया कि जिन किसानों द्वारा अक्टूबर माह में मक्का की बुआई की गयी थी, उसमें 50 परसेंट दाना नही है परन्तु जिन किसानों के द्वारा नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में बुआई की गयी थी, उसमें शतप्रतिशत दाना है । कमिटी द्वारा जांच प्रतिवेदन में निष्कर्ष दिया गया है कि लम्बी अवधि के हाईब्रीड मक्के में 80 एवं 100 दिन के बीज परागण का समय होता है, उस समय न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए । संबंधित सभी किसानों द्वारा 18.10.17 से 22.10.17 तक मक्के की बुआई की गयी थी । मक्के के फसल का परागण का समय बोआई के अनुसार 7. 17 से 27.10.17 के बीच का था, जिस समय तापमान 8 डिग्री सेंटिग्रेड से कम था । कमिटी मक्के में दाना नहीं बनने के कारण तापमान में आयी गिरावट को मानती है । कमिटी द्वारा मक्के की बुआई नवम्बर के प्रथम सप्ताह में करने का उपयुक्त समय बताया गया है एवं प्रधानमंत्री फसल योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक तौर पर करने का सुझाव दिया गया है ताकि किसानों के हानि को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाया जा सके । विभाग ने इसकी अवहेलना करने वाले बीज कम्पनी पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी एवं किसानों को मुआवजा के संबंध में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो नुकसान हुआ है किसानों का, सरकार उसकी भरपाई करेगी ।

टर्न-6/शंभु/08.03.18

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न था कोढ़ा प्रखंड के भटवारा पंचायत का तो स्पेशफिक इस पंचायत में जो किसानों का फसल बर्बाद हुआ और यह जो मक्का के बीज का मामला है । मैं जानकारी देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को कि पूरे बिहार में इस बार स्थिति गड़बड़ हुई है इस मामले में - दरभंगा की भी मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है यह केवल कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड का मामला है । दरभंगा जिला में बिरौल प्रखंड, बेनीपुर प्रखंड, हायाघाट प्रखंड, हनुमान नगर प्रखंड, कुशेश्वर पूर्वी और कुशेश्वर पश्चिमी, बहेड़ी इन स्थानों से भी व्यापक रूप से हमलोगों को फोन आ रहा है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कल कहा भी है अपने जवाब में कि हम सभी जगह जॉच करायेंगे । महोदय, विशेषकर यह जो भटवारा पंचायत का मामला है इसका मैं जानना चाहता हूँ कि इस पंचायत में किसानों को क्या मुआवजा देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी?

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हमने वैज्ञानिक अधिकारियों का टीम बनाया है और सीमांचल और कोशी के जिलों में और राज्य के अन्य जिलों में भी बेगुसराय में पाया गया है । इसके बारे में टीम जॉच कर रही है और जॉच के बाद जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार क्षतिपूर्ति भरपाई करेगी । साथ ही साथ जहां तक प्रश्न

कटिहार का है । हम जॉच रिपोर्ट पढ़ देते हैं- दिनांक 27.02.18 को जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-383-कृषि कटिहार दिनांक-15.02.18 के आलोक में गठित कमिटी में वर्णित किसान श्री सम्बिका महतो, भटवारा पंचायत, वार्ड नंबर-6, बान टोला नंबर दो किसान श्री कपिल मेहता पिता बीरबल दास, ग्राम सिकटिया, पंचायत मखदुमपुर, तीन अवधेश कुमार, पिता स्व0 चंद्रिका प्रसाद, ग्राम बासगाढ़ा, प्रखंड कोढ़ा के द्वारा की गयी शिकायत के आलोक में उनके खेतों का निरीक्षण कमिटी के सदस्यों द्वारा की गयी । श्री सम्बिका महतो ने पी0-3522 मक्का का बीज श्री उपेन्द्र सिंह खेरिया के दूकान से खरीदकर 22 नवम्बर, 2017 को मक्का की बुआई की गयी थी । उनके 2.5 बीघा खेत में 50 परसेंट दाना नहीं है । उनके बगल के खेत में जो कि तीनपनिया के किसान का हैं, जो कि नवम्बर माह में प्रथम सप्ताह में बुआई की गयी थी । उसमें 100 परसेंट दाना है । जॉच टीम के सामने अन्य किसानों ने भी अपने फसल की चर्चा की और बताया कि इस वर्ष ज्यादा पराग नहीं था और नवम्बर में लगायी गयी मक्के की फसल अच्छी है एवं 5 से 30 अक्टूबर तक लगायी गयी मक्के की फसल में दाना नहीं लगने की समस्या है । श्री अवधेश कुमार किसान ने 19 अक्टूबर को डेढ़ बीघा एवं 23 अक्टूबर को डेढ़ बीघा में मक्के की किस्म............

अध्यक्ष : ये पूरा प्रतिवेदन पढ़ने की आवश्यकता है क्या ?

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय........

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री ने पूरे प्रदेश के लिए कहा है कि जहां कहीं भी बीज की शिकायत के कारण मक्का के बाली में दाना नहीं आया है उसकी जॉच कराकर किसान को मुआवजा भरपाई देंगे । अब क्या पूछना है ? बोलिये इलियास साहब ।

श्री मो0 इलियास हुसैन : महोदय, प्रश्नकर्त्ता सदस्य का सीधा सवाल है और बिहार के आम किसानों से संबंधित यह मामला है । सरकार की शिथिलता परिलक्षित है । मैं आपसे आग्रह करता हूँ किसान के हित में कि यहां महाराष्ट्रा रीपीट नहीं हो । एक दाने के उपर आप हाऊस की कमिटी बनाकर इस चीज की जॉच कराइये । कृषि विभाग में महान शिथिलता है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ हुजूर ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में मौसम के तापमान का हवाला दिया है कम होने का और ज्यादा होने का । महोदय, यह हमको बताइये कि पूरे बिहार में जो किसान हैं, जो बुआई करते हैं किसी फसल का, मक्के का तो मक्के के पहले कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चला नंबर एक । नंबर दो मौसम के तापमान के चलते........व्यवधान......गजब हाल है ? हम क्या कह रहे हैं और आप कमिटी बनाने की बात कह रहे हैं आप ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इसमें एक मिनट । आपका प्रश्न आने की व्यवस्था हो रही है । माननीय सदस्यगण, जब सरकार ने खुले तौर पर कहा है कि हम सबकी जॉंच कराकर किसानों....अब सुन लीजिए न, अब सुन तो लीजिए । हाऊस की कमिटी बना देने से मुआवजा मिल जायेगा कि जॉंच कराकर- अभी आसन की समझ से जितने भी माननीय सदस्य को अपने-अपने इलाके की जानकारी है वह सरकार को दे दीजिए, उन सब जगह पर सरकार जॉंच करायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-746(श्री ललन पासवान)</u>

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास, सासाराम एवं कैमूर(भभुआ) जिले में सात निश्चय योजना अन्तर्गत फ्लोराइड प्रभावित वार्डों में फ्लोराइड मुक्त जलापूर्ति हेतु मे0 हाईटेक वाटर्स सोल्युशन को क्रमश : 38.38 करोड़ एवं 18.10 करोड़ का कार्य आवंटित किया गया है ।

2- अस्वीकारात्मक है । आमंत्रित निविदा के प्रावधानों के अनुसार निविदा में केन्द्र सरकार या कोई राज्य सरकार या कोई लोक उपक्रम के अन्तर्गत समुचित श्रेणी में निबंधित अथवा अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाएं भाग ले सकती है, परन्तु एल0ओ0ए0 निर्गत होने के पश्चात् उन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत समुचित श्रेणी में निबंधन अनिवार्य होगा । प्रासंगिक निविदा में भाग लिये निविदाकार मे0 हाइटेक वाटर सोल्युशन के तकनीकी बीड के मूल्यांकन के सफल पाये जाने तथा वित्तीय बीड में दर न्यूनतम होने के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन उपरांत फर्म का एल0ओ0ए0 निर्गत किया गया है तथा एजेंसी ने निविदा की शर्त्त के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में श्रेणी-1 के तहत निबंधन करा लिया है । जिसका निबंधन सं0-32218 है ।

3-उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट है ।

श्री ललन पासवान : महोदय, यह सूरत की कंपनी है और मेरे यहां पूरा पहाड़ी इलाका है । इसके पास एक भी मशीन नहीं है गाड़नेवाला । दूसरी बात माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि यह पूरा एल0ओ0ए0 सिस्टम की सात सदस्सीय कमिटी है । महोदय, डी0पी0 सिंह, मुख्य अभियंता, विशेष सचिव, शशिकान्त तिवारी, निखलेन्द्र कुमार, सतीशचन्द्र मिश्रा, अरविन्द कुमार, सुधीर कुमार सिन्हा । महोदय, जो निविदा डाले हुए लोग हैं जितने संवेदक हैं- सिर्फ यह जॉंच करा दें, दूध का दूध, पानी का पानी फैसला हो जायेगा कि वाटर हाईटेक जो कंपनी है, वह कौन-कौन कागज लेकर आई है । जितने लोग उसमें इन्वोल्व हैं सबलोगों ने मैनेज करके उसमें टेंडर दिया है । बिहार की कई कंपनियां जिसके पास दर्जनों मशीन है उसको छांट दिया और इसको दे दिया गया है । इसलिए जो निविदा समिति है, इसकी जॉंच पटना आयुक्त से करा दें ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, इस निविदा का एक सरकुलर है कि कोई भी कंपनी चाहे वह देश स्तर के किसी रजिस्ट्रेशन के लिये हो या राज्य के किसी भी संस्थान में चाहे वह

पी0डब्लू0डी0, चाहे आर0डब्लू0डी0 किसी भी संस्थान में उसका रजिस्ट्रेशन है तो वह निविदा में भाग ले सकता है......क्रमशः।

टर्न-7/ज्योति/08-03-2018

क्रमशः

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : तो वह निविदा में भाग ले सकता है और जब उसको काम देने की स्थिति आयेगी, उसका फायनेन्शियल बीड और उसका टेक्नीकल बीड दोनों बीड जब अनुकूल होगा और जब उसको काम का जब एग्रीमेंट होगा, तब वह उसका रजिस्ट्रेशन लेगा तो महोदय, यह कंपनी का जो फायनेन्शियल बीड था, वह सबसे लोएस्ट था और टेक्नीकल बीड - इसका ठीक था, तब विचारोपरान्त इसको काम दिया गया है और अब यह काम रहा है ।

अध्यक्ष : वह तो उससे आगे की बात कह रहे है, वह कह रहे हैं कि जो विचारोपरान्त दिया गया है, जो इस कंपनी के कागजात हें वह सही नहीं हैं, ये माननीय सदस्य का कहना है और इसी की जॉच...........

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं यह कह रहा हूॅ कि पहला काम तो यह है कि यह कंपनी आज तक कभी वाटर के सवाल पर काम नहीं की है । नलकूप का काम कभी नहीं की है और किस आधार पर सरकार ने इस कंपनी को काम आवंटित किया है, कौन सा मामला है , हाईटेक के साथ उन सात सदस्यीय कमिटी ....

अध्यक्ष : इसकी जॉच आप विभागीय सचिव से करा दें ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : जी, महोदय, करा देंगे ।

अध्यक्ष : सेक्रेट्री लेवेल से जॉच होगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या 747 (श्री मो0 जावेद)

अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिए सिद्धार्थ जी अधिकृत हैं ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, पटेल नगर पथ संख्या 10 स्थित कमला एपार्टमेंट के सचिव एवं अन्य फ्लैटधारियों द्वारा दिए गए शिकायत पत्र में फ्लैट संख्या 42 के धारक के परिवारिक सदस्य के द्वारा उक्त एपार्टमेंट में किए जा रहे, अनधिकृत निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं अभियंत्रणा जॉचोपरान्त उक्त एपार्टमेंट के फ्लैट नं0 42 के धारक द्वारा अनधिकृत निर्माण के कारण नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के न्यायालय में निगरानी वाद संख्या 49बी/2017 आधारित है, जो सुनवाई पर है । बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत नगर आयुक्त पटना, पटना नगर निगम के द्वारा सुनवायी की जा रही है । उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सिद्धार्थ : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूॅ कि यह इरेगुलर कंस्ट्रक्शन का मैटर था । 26-12-17 को एक पक्ष को शो-कॉज किया गया, इस

इरेगुलर कंसट्रक्शन के कारण और 22-12-17 को ही नगर आयुक्त ने इसके विरुद्ध जजमेंट दे दिया । मतलब, समय जो निर्धारित किया गया जवाब देने का, उससे 19 दिन पहले ही प्रीज्यूडिश होकर इस मैटर का निष्पादन कर दिया गया, इसलिए यह दो दिन की तिथि है 26-12-17 जिस दिन यह उनके पास शो-कॉज गया है और 22-12-17 -जिस दिन पहले ही जजमेंट दिया गया है इसकी कृपया करके जॉंच करवा लें, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसकी जॉंच करवा लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य बता रहे हैं कि डेट प्रीपौंड करके देख लिया गया है, इसकी जॉंच करा दें ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : जॉंच करा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नो के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जांय ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनॉंक 08 मार्च, 2018 को माननीय सदस्य श्री शक्ति सिंह यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है, अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172 (3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है । अब शून्य काल । शून्य काल में भी आपका है । क्या
है ?

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आज जो कार्य स्थगन आया है, वह सिर्फ किसी राजद और जदयू और भा.ज.पा. का सवाल नहीं है । यह सवाल है बिहार के अस्मिता का, बिहार के विकास का ।

अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं..

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर हमने कार्य स्थगन इसलिए लाया कि आप जानते हैं कि इसी बिहार विधान सभा में जिस समय बिहार विभाजन का दंश झेलने के लिए विवश था, उस समय तत्कालीन मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश की सरकारें थी और इसी सदन से पारित होकर पैकेज के लिए विशेष राज्य के दर्जे के लिए गया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने भी विशेष राज्य के दर्जे पर एक राग छेड़ा । इसको बहस का मुद्दा बनाया महोदय, डबल इंजन की सरकार है । हम चाहते हैं कि इसपर, पूरे सदन की सहमति होकर और विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर और विशेष पैकेज के सवाल पर पूरा सदन एक मुश्त हो करके डबल इंजन की ताकत लगा कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलायेगा ।

अध्यक्ष : शक्ति जी, आप सही कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए या पैकेज दिलाने के लिए या सहायता दिलाने के लिए तो इस सदन में सर्व सम्मत प्रस्ताव भेजा हुआ है, तो जिस सदन में सर्व सम्मत प्रस्ताव भेजा है उसी का कार्य स्थगित क्यों करना चाहते हैं ?

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, आपने ठीक कहा । हमने कहा महोदय, सवा लाख करोड़ पैकेज का ....

शून्य काल

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के ग्राम पंचायत बसुआड़ा में अवस्थित दारुल उलूम मदरसा जर्जर कच्चे मकान में है । इसमें निर्धनतम बच्चे पढ़ रहे थे परन्तु जर्जर हो जाने के कारण पठन पाठन बंद कर दिया गया है । अतः उक्त मदरसा का पक्का निर्माण कराकर पठन पाठन चालू कराया जाय ।

श्री अमित कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड की स्थापना हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं लेकिन दिनाँक 26-02-2018 तक प्रखंड कार्यालय का निर्माण नहीं किया जा सका है । निजी भवन में कार्यालय चलने के कारण गोपनीयता बनाये रखने हेतु कार्यालय भवन निर्माण शीघ्र करावें ।

श्री सुबोध राय : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज शहर स्थित महिला चिकित्सालय में महिला रोगियों को 24 घंटा चिकित्सा सेवा और महिला चिकित्सक की तत्काल नियुक्ति हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा नूरसराय पी.डब्लू.डी. पथ लालसे बिगहा मोड़ से मिल्कीपर भदौल, भड़रा घूरगांव के रास्ते एन.एच. 110 एकंगरसराय बिहारशरीफ को जोड़ने वाली आर.डब्लू.डी. को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करने हेतु हम सरकार से मांग करता हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड के प्रभासरी सी.डी.पी.ओ. के मनोनोकूल कार्य नहीं करने पर प्रभारी सी.डी.पी.ओ. के द्वारा कर्मचारी को गलत आरोपों से परेशान किय जाता है । अत: उक्त प्रभारी सी.डी.पी.ओ. का प्रभार किसी अन्य को देते हुए उचित कार्रवाई की मांग करती हूँ ।

श्री ललन पासवान: महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत धरौली के असम राईफल जवान, शशिकान्त मिश्रा एवं पीरो के सी.आर.पी.एफ. जवान मुजाहिद खान देश सेवा में शहीद हो गए। सरकार से मांग करते हैं कि दनों शहीद जवान के आश्रितों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा एवं सरकारी नौकरी दिलावे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा प्रखंड अन्तर्गत जसौलीपट्टी निवासी राम निवास सिंह, रवीन्द्र सिंह के घर में 20-02-18 को आकस्मिक आग लगने से 1 दुधारु भैस, 1 गाय , सैकड़ों की संख्या में मुर्गी जल कर राख हो गई। शीघ्र आपदा राशि से सहायता हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री हरिशंकर यादव - अनुपस्थित

डा0 राजेश कुमार : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला में भारत सुगर मील सिधवलिया एवं विष्णु सुगर मिल हरखुआ, गोपालगंज द्वारा सर्वे किया गया क्षेत्र से उचित मात्रा में न तो क्रय किया जा रहा है न तो अधिक गन्ना खेती करने वाले किसानों को चालान मिल रहा है । सरकार इस समस्या का समाधान करे ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, छात्रा चंदा कुमारी (13) पिता श्री विजेन्द्र सिंह, ग्राम-सेदहाँ, थाना-तरारी जिला -भोजपुर के साथ आए दिन छेड़खानी करने वाले नामजद अभियुक्त शिव कुमार पिता श्री दीना नाथ यादव, ग्राम-सेदहाँ को तत्काल गिरफ्तार किया जाय ।

टर्न-8/08.3.2018/बिपिन

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत खुटौना प्रखंड, थाना- ललमनिया के धनूषी सर्वसीमा गॉव में महादलित परिवार रामवती देवी पति लखीराम के दुकान में स्थानीय दवंगों द्वारा मारपीट कर दूकान को पुरी तरह से जला दिया जिसमें रामवती देवी बुरी तरह घायल हैं ।

अत: मैं उक्त घटना की विस्तृत जांच स्पीडी ट्रायल के तहत कराने की मांग करता हूं ।

श्री रामदेव राय : महोदय, बेगुसराय जिला के बछवाड़ा, भगवानपुर एवं मंसूरचक आदि प्रखंडों में मकई के बाल में एक भी दाना नहीं उगा है जिससे किसानों में त्रहिमाम मचा हआ है । युद्धस्तर पर टीम भेजकर इसकी सही जानकारी लेते हुए बेसहारा किसानों को राहत देने के लिए में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

ध्यानाकर्षण सूचना

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री सुधांशु शेखर, रामप्रीत पासवान एवं श्री राजू तिवारी, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुधांशु शेखर ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री रामप्रीत पासवान सूचना पढ़ें ।

श्री रामप्रीत पासवान: अध्यक्ष महोदय, ''राज्य सरकार द्वारा राज्य के पंचायत भवनों को सुदृढ़ करने के लिये पंचायत भवनों के निर्माण पर करोड़ों रूपये खर्च किए गए । कई जगहों पर तो निर्माण पूर्ण हो गया पर बहुत से भवनों का निर्माण अधूरा ही छोड़ दिया गया । जो पंचायत भवन बन गए वो भी उचित रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गए हैं । बिना कोई कर्मी के भवन महीनों तक बंद रहता है जिस कारण कई भवनों पर या तो जानवरों को बांधने का उपयोग होता है या फिर किसी के द्वारा भवनों पर कब्जा कर लिया गया है । पंचायत सचिव भी पंचायत भवनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं ।

अत: उक्त विषय पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री: समय चाहिए महोदय । अगले दिन रखा जाए ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-09/ कृष्ण/08.03.2018 (अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा :-

राष्ट्रीय जनता दल - 59 मिनट

जनता दल(युनाइटेड) - 52 मिनट

भारतीय जनता पार्टी - 39 मिनट

इंडियन नेशनल कांग्रेस - 20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0) - 02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी - 02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा - 01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी - 02 मिनट
निर्दलीय - 03 मिनट

वैसे कारगर तौर पर विभिन्न दलों को सरकार के उत्तर के पश्चात् समय बचता है, उस हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल को 50 मिनट, जनता दल(युनाइटेड) को 43 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 33 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 17 मिनट, सी0पी0आई0(एम0एल0)को 01 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी को 01 मिनट, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा को 01 मिनट, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 01 मिनट और निर्दलीय को 03 मिनट का समय बचता है । तो सभी पार्टी के नेताओं या सचेतक, मुख्य सचेतक से अनुरोध है कि कृपया इसी हिसाब से समय का आवंटन करके सदस्यों का नाम भेजेंगे, जिससे कि आसन को समय प्रबंधन में सुविधा हो । माननीय मंत्री,जल संसाधन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री **:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

''जल संसाधन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 34,97,38,14,000/- (चौंतीस अरब संतसानवे करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार) रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर श्री भोला यादव, श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजेन्द्र कुमार, श्रीमती ऐज्या यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री ललित कुमार यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं एवं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री भोला यादव का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मॉग 10/- रूपये से घटाई जाए ।''

महोदय, जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग दोनों किसान से जुड़ा हुआ विभाग है और हमारे राज्य के कृषक खास करके सिंचाई के मामले में इसी दो विभाग पर निर्भर करते हैं । लेकिन राज्य का दुर्भाग्य है कि एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखाड़ और उसमें जल संसाधन विभाग का जो रोल है वह उचित नहीं है । हमारे यहां उत्तर बिहार में जब बाढ़ आई तो कहा गया कि चूहों ने बांध को कुतर दिया, जिसके चलते बाढ़ आ गयी । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूहों के कुतरने से यदि बाढ़ आती तो हर साल बाढ़ आती रहती, चूहे तो हर साल बांध कुतरते हैं । लेकिन ऐसी बात नहीं है । हरेक साल बाढ़ नहीं आती है । कहीं न कहीं जो बांध का मरम्मत का काम है, हर साल केवल कागजी खानापुरी होती है, दुब्भी को छिल दिया जाता है और हल्का-फुल्का मिट्टी डाल दिया जाता है और कागजी खानापुरी करके बिल को भुना लिया जाता है । महोदय, मैं कटौती का प्रस्ताव इसीलिये लाया हूं कि इस विभाग का बजट महागठबंधन के समय में जो बजट था, उस बजट से खास करके हम यह बताना चाहते हैं योजना मद में स्थापना खर्च को छोड़ करके 446 करोड़ रूपया कम कर दिया गया । लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे माननीय ललन भईया पर कृपा कम हो गयी है और लगता है कि उनसे आजकल खुश नहीं रहते हैं । महोदय, दुसरी तरफ हमें यह भी शंका होती है कि जब हमलोगों का साथ छोड़ कर जब ललन भईया उस पार गये हैं तो लगता है कि बीजेपी को यह पच नहीं रहा है जिसके चलते बीजेपी के वित्त मंत्री दबाव देकर इनका बजट घटा दिया है । क्या काम करेंगे ? इसलिए हम कहते है कि जब बजट घट ही रहा है तो उस हिसाब से कटौती होनी चाहिए । इसलिए हम कटौती प्रस्ताव लाये हैं । महोदय, इनके विभाग की जो सक्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से विभाग काम नहीं कर रहा है । कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो बरसों-बरस से चली आ रही है जिसका क्रियान्वयन किसी सर्टेन वित्तीय वर्ष में कर दें । अभी बटेश्वर वाला घटना को ले लीजिये । आज सदानन्द बाबू बता रहे थे कि जब से वे विधायक बने हैं तब से वह योजना चला आ रहा है और 40 साल बाद उस योजना का उद्घाटन भी करने गये तो पहले ही वह ध्वस्त हो गया । पता नहीं किस हिसाब से इन्जीनियर ने जल को छोड़ा और वह पूरा ध्वस्त हो गया । खैर जैसे तैसे तो इन्होंने उद्घाटन तो कर दिया लेकिन उद्घाटन में जो जल छोडें हैं कि वह इतना कम छोडें हैं कि बांध कहीं टूट न जाय । किसी तरह ये कागजी खानापुरी कर दिये हैं । उससे कितना पटवन होगा ? ईश्वर ही जानते होंगे । महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर बिहार का सारण जिला का सिताब-दियारा है जो हम लोगों के नेता जय प्रकाश नारायण जी का जन्मस्थली है । महोदय, वहां की स्थिति यह है कि हर साल कटाव होता है, हरेक साल कटाव हो रहा है लेकिन हर साल इनका रीवाईज्ड एस्टीमेट बनता है लेकिन कटाव निरोधक जो काम होने चाहिए, वह थोड़ा बहुत

करके, कागजी खानापुरी करके अगल साल उसी जगह पर कटाव हो रहा है । यह इनके विभाग का फितरत है जो हरेक बार द्वितीय, तृतीय, पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करते हैं । हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मांझी जी इस सदन के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि कई विभागों में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है । यदि इनके विभाग का भी जांच करवाया जाय तो इसमें भी एस्टीमेट घोटाल बडे पैमाने पर मिलेगा ।

(इस अवसर पर सभापति महोदया, श्रीमती रंजू गीता ने आसन ग्रहण किया।)

महोदय, हमारे इलाके में कोसी नहर प्रणाली है । कोसी नहर प्रणाली की स्थिति यह है कि वह पुरी तरह से ध्वस्त है । कहीं पर भी पटवन का कोई प्रोपर बंदोवस्त नहीं है । नहर बना हुआ है लेकिन पता नहीं कब उसको चालू किया जायेगा और कैसे चालू किया जायेगा, उसका कोई पता नहीं है । हमारे गांव के बगल से एक नहर गयी है, नहर बने हुये दस साल से ऊपर हो गया लेकिन महोदय, उसमें पानी एक बार भी नहीं छोड़ा गया है ।

क्रमश :

टर्न-10/सत्येन्द्र/8-3-18

श्री भोला यादव (क्रमशः): लघु सिंचाई विभाग की स्थिति यह है कि पूरे राज्य में स्टेट ट्यूबवेल हजारों की संख्या में लगा हुआ है लेकिन गिने चुने को छोड़कर प्रायः जितने भी स्टेट ट्यूबवेल हैं, सब बंद है और कुल मिलाकर के देखिये तो हमारे क्षेत्र में करीब 50 से ऊपर स्टेट ट्यूबवेल है उसमें से दो तीन को छोड़कर सब बंद है, कोई बड़ा उसमें खर्च नहीं है, छोटा छोटा खर्च है, किसी का फ्यूज उड़ा हुआ है किसी पर ऑपरेटर नहीं है, किसी में बिजली कनेक्शन नहीं है, किसी में मोटर खराब है लेकिन विभाग को इसकी कोई चिन्ता नहीं है कि उस सब पर ध्यान दे, उस सब का सुधार करायें ताकि लोगों को राहत मिल सके । महोदय, आज किसान भगवान के भरोसे अपना किसी तरह से पटवन का उपाय कर रहे हैं और जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं । महोदय, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता चूंकि हमारा समय निर्धारित है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने समय शौर्ट कर दिया है इसलिए मैं अपने क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ मामले को माननीय मंत्री जी के नजदीक रखना चाहता हूँ । महोदया, मेरे क्षेत्र में बागमती नदी है, माननीय मंत्री जी जानते हैं, वहां एक न्याम गांव है जो बहुत बड़ा बस्ती है, उस गांव की स्थिति यह है कि वहां कटाव का स्थिति लगातार बद से बदतर होते जा रहा है और नदी की धारा जिस तरह से मुड़ रही है लगता है आने वाले कुछ वर्षों में जिस तरह से कटाव हो रहा है वह गांव विलीन हो जायेगा, गांव होकर धारा निकल जायेगी नदी की लेकिन इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी को हम कई बार स्मारित किये, कई बार लिखे, कई बार क्वेश्चन भी हाउस में किये लेकिन अभी तक उस पर कार्य नहीं हो रहा है सिर्फ कार्य

तब होता है जब बाढ़ आती है, नदी में पानी आती है तो रक्षात्मक कार्य में पैसे की लूट होती है । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि अभी सूखाड़ के समय में तटबंध को बोल्डर पीचिंग करवा दीजिये जिससे गांव बच जाय । उसी के बगल में गोरहारी गांव है उसकी भी स्थिति यह है कि पूरा का पूरा कटाव होकर गांव के तरफ बढ़ा चला आ रहा है । भवानीपुर, उचौली सब गांव का स्थिति इसी तरह का है महोदय, उसी नदी के किनारे एक सैदपुर गांव है, उस गांव में मुस्लिम की बड़ी आबादी है, वहां पर एक मस्जिद है और वह मस्जिद से मात्र 25 फीट दूरी रह गयी नदी और कटाव की स्थिति यह है आने वाले दिनों में मस्जिद उसमें विलीन हो जायेगा यदि कटावरोधक कार्य नहीं किया गया महोदय तो डगरौल गांव के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी पिछली बार कुछ फंड दिये थे, कुछ काम हुआ था लेकिन इस बार के बाढ़ में उस सारे किये गये काम को ध्वस्त कर दिया है इसलिए माननीय मंत्री जी से हम चाहेंगे कि उसको दिखवा लें और उसको फिर से नये सिरे से करवावें । उसी तरह से उसी बगल में रामपुर गांव हैं, वहीं पर रूपौली है उस सब का स्थिति वही है । मैं महोदय यह बतलाना चाहता हूँ कमला नदी के किनारे एक भूतही बांध है और वह भूतही बांध बहादुर प्रखंड के भिउनी गांव में है, उस भूतही बांध के टूटने से हरेक साल हजारों एकड़ जमीन जल पल्लावित हो जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि वहां एक स्लूईस गेट दें और वहां पर तटबंध को सुदृढ़ करावें जिससे कि उस इलाके के लोगों को पटवन का साधन भी मिल जाये और रक्षात्मक कार्य भी हो जाय । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इन सब बातों पर ध्यान देंगे । धन्यवाद ।

श्री निरंजन कुमार मेहताः माननीय सभापति महोदया, वर्ष 2018-19 के अनुपूरक व्यय विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग के समर्थन पर आपने बोलने का अवसर दिया माननीय सभापति महोदया, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । महोदया, मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने न्याय के साथ विकास के लिए दृढ़संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का । महोदया, मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन श्री ललन बाबू का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ । महोदया, मैं कोसी से आता हूँ, जहां कोसी बाराज से नहर प्रणाली जो निकली है, कोसी कमिश्नरी के सभी जगह वीरपुर भीमनगर बैराज से जल प्रवाहित होता है । महोदया, अब मैं जल संसाधन विभाग के सकारात्मक कार्य का विवरण पेश कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जल संसाधन विभाग राज्य में सिंचाई बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के जन उपयोगी कार्य को सम्पादित करता है । भौगोलिक एवं जलवायु जनित स्थितियों के कारण वर्षाऋतू में जब राज्य की नदियों में एक तरफ भीषण कटाव एवं बाढ़ की परिस्थिति

उत्पन्न होती है तो दूसरी तरफ खेतों में खरीफ फसल के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता होती है । हरेक मौसमी फसल में चाहे रब्बी का हो, खरीफ का हो समयानुसार जल संसाधन विभाग नहर प्रणाली के द्वारा खेत में ससमय पानी पहुंचाया जाता है । महोदया, जल संसाधन विभाग के दो पृथक खंडों सिंचाई सृजन एवं बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण में पुनर्गठित किया गया है । ऐसे में जब अभियंताओं का दल बाढ़ के कटाव से आवश्यक संरचनाओं को सुरक्षित करने में संघर्षरत रहते थे तो दूसरी तरफ खेतों में सिंचाई प्रदान करने हेतु निर्मित नहरों में टूटान की स्थिति में सिंचाई बाधित होने के कारण जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री महोदय ने दोनों कार्य संचालन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विभाग द्वारा अभियंताओं को अलग अलग पुनर्गठित पिछले वर्ष में ही कर दिया है । जो दल बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के कार्य में संलग्न हो, वे सिंचाई से मुक्त रहें और जिनकी जवाबदेही सिंचाई की हो वे पूर्णतः सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में ही संलग्न रहें । महोदया, जल संसाधन विभाग वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित कर खेतों में पानी पहुंचाने एवं बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को पूरा कर बाढ़ से जानमाल को सुरक्षित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। महोदया, जल संसाधन विभाग अपने कार्य क्षेत्र में वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से अधिकतम सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हे0 के लक्ष्य को प्राप्त करने, विकसित सिंचाई क्षमता को सतत् बनाये रखने, सिंचाई क्षेत्र में लगातार वृद्धि करने एवं संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक उपायों से प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने हेतु प्रयासरत है । महोदया, नई योजनाओं का उद्घाटन में वर्ष 2017 विभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, फरवरी, 2017 में लवाईच-रामपुर बराज योजना, बोलहंडा बीयर योजना, पंतित योजना एवं जगन्नाथ बीयर योजना का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया इसके बाद जून, 2017 में उदेरा स्थान बराज योजना, नसरतपुर बीयर योजना एवं कचनामा बीयर योजना का उद्घाटन तथा मंडई पुनर्गठित सिंचाई योजना का कार्यारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ । पुनः दिसम्बर, 2017 में माननीय मंत्री, जल संसाधन तथा योजना एवं विकास के द्वारा शंभूगंज शाखा नहर, रजौन उप वितरणी एवं गौरीपुर उप वितरणी जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन एवं चंदन जलाशय योजना का पुनर्स्थापन, सुखनिया बीयर का पुनर्निर्माण इकाई बीयर का पुनर्स्थापन तथा बदुआ जलाशय योजना का पुनर्स्थापन कार्य का कार्यारंभ किया । उद्घाटित की गयी योजनाओं से कुल 71 हजार 608 हे0 क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है जिससे पटना, औरंगाबाद, अरबल, जहानाबाद, नालंदा, गया तथा बांका जिला लाभान्वित हुए हैं । महोदया, मार्च, 2018 तक सिंचाई क्षमता विकसित करने हेतु लक्ष्य जल संसाधन विभाग वर्षवार एक्शन प्लान तैयार कर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित करने हेतु कार्य कर रहा है । मार्च, 2018 तक उदेरा स्थान बराज योजना, मुंगेर पहाड़ी

से नि:सृत जलश्रोतों पर आधारित सिंचाई योजना, चानकेन सिंचाई योजना, दानवीर झील जल निकासी ढवं सिंचाई योजना, सेंधवा चेक डैम निर्माण कार्य, मोहाने नदी पर छोटी छरियारी गांव के पास सीवान बीयर का निर्माण कार्य, ढ़ाढ़र अवसरण योजना, कुण्डधार जलाशय योजना, दुर्गावती जलाशय योजना, पश्चिमी कोशी नहर योजना, बटेश्वर गंगा पम्प नहर परियोजना, पुनपुन बराज योजना, लखीसराय जिलान्तर्गत भवरिया चेक डैम, महिसौड़ा बीयर योजना, सीसमा बीयर का जीर्णोद्धार एवं गौरा बीयर का निर्माण कार्य, पश्चिमी गंडक नहर विस्तारीकरण फेज-2, पूर्वी गंडक नहर प्रणाली फेज-2 के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 66,048 हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास किया जायेगा ।
(क्रमश:)

टर्न-11/मधुप/08.03.2018

...क्रमश: ...

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदया, मार्च, 2018 तक ह्रासित सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन का लक्ष्य चौसा पम्प नहर, सुअरा बीयर योजना का पुनर्स्थापन, अपर क्यूल जलाशय योजना का पुनर्स्थापन कार्य, पूर्वी कोसी नहर पुनर्स्थापन योजना तथ अन्य बहुतों पुनर्स्थापन योजना, जीर्णोद्धार कार्य आदि से 1,14,161 हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया जाना है ।

महोदया, सिंचाई में रिकॉर्ड उपलब्धि वर्ष 2016-17 के दौरान खरीफ में 19.31 लाख हेक्टेयर, रब्बी में 7.14 लाख हेक्टेयर एवं गरमा में 0.27 लाख हेक्टेयर कुल 26.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई जो कि अब तक का सर्वकालिक रिकॉर्ड उपलब्धि है । इसका प्रतिफल यह रहा है कि राज्य का अन्न भंडार पूर्ण रूप से भरा हुआ है एवं राज्य के किसान केन्द्रीय भंडार में पर्याप्त अन्न दे रहे हैं जिससे उनका आर्थिक विकास भी लगातार हो रहा है ।

महोदया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्सरित शोधित जल से सिंचाई - माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गंगा की अविरलता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु निर्देश दिया गया है कि शहरों में नालों से निकलने वाले गंदे जल को शोधित कर यथासंभव सिंचाई एवं कृषि कार्य में उपयोग किया जाए एवं किसी भी परिस्थित में शोधित जल को नदियों में नहीं गिराया जायेगा ।

महोदया, जल संसाधन विभाग द्वारा इस दिशा में पटना के बेऊर, करमलीचक, सैदपुर, कंकड़बाग एवं पहाड़ी के साथ-साथ दीघा में अवस्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित जल का उपयोग कृषि सिंचाई में करने हेतु परामर्शी का चयन कर योजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है ।

महोदया, बाढ़ 2018 के पूर्व बाढ़ की विभीषिका से बचाव की तैयार – सिंचाई के अतिरिक्त बाढ़ की विभीषिका से राज्य की जनता को सुरक्षा प्रदान करना जल संसाधन विभाग का महत्वपूर्ण दायित्व है । राज्य में कुल 68.80 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र 94.16 लाख हेक्टेयर का 73.06 प्रतिशत है तथा भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 400 लाख हेक्टेयर का 17.20 प्रतिशत है । अब तक कुल 3790 किलोमीटर तटबंध का निर्माण कर 39.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया गया है । अगले पॉच वर्षों में 1676 किलोमीटर अतिरिक्त तटबंध का निर्माण कर 23.16 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है । अतः तटबंधों/स्थलों के सुरक्षार्थ बाढ़ 2018 पूर्व 395 अदद योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

महोदया, इन सभी योजनाओं को बाढ़ पूर्व पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है । इन योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य के एक बड़े भू-भाग को सुरक्षित रखा जा सकेगा ।

बाढ़ प्रबंधन हेतु गैर संरचनात्मक उपाय – इसके लिये बाढ़ प्रबंधन हेतु गैर संरचनात्मक उपाय जल संसाधन विभाग के अधीन बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र के अन्तर्गत किये जा रहे हैं । इसके अन्तर्गत बागमती अधवारा बेसिन के लिए मॉडल आधारित बाढ़ पूर्वानुमान प्रायोगिक तौर पर गत बाढ़ अवधि में FMISC के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया । इसी प्रकार कोसी बेसिन के बाढ़ पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने पर परामर्शी द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

महोदया, इसके अतिरिक्त बिहार कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, बिहार कोसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट एवं साउथ एशिया वाटर इनीसिएटिव ट्रस्ट फण्ड सम्पोषित योजनाओं का कार्य किया जा रहा है जिससे राज्य में बाढ़ प्रबंधन की दिशा में काफी सहयोग प्राप्त होगा ।

महोदया, इसी क्रम में इस संस्था के अन्तर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के अधीन मैथेमेटिकल मॉडलिंग सेन्टर की स्थापना जल संसाधन भवन, अनीसाबाद में किया गया है जिसका उद्घाटन यथाशीघ्र किया जायेगा । साथ-ही, वीरपुर में एक फिजिकल मॉडलिंग सेन्टर की भी स्थापना की जा रही है । इसके निर्माण से राज्य में बाढ़ प्रबंधन कार्य में उतरोत्तर उत्कृष्टता हासिल की जा सकेगी ।

महोदया, बाढ़ अवधि में ये कदम राज्य की जनता एवं जान-माल की सुरक्षा हेतु अत्यंत कारगर सिद्ध होगा ।

महोदया, तो ये उत्कृष्ट कार्य माननीय मुख्यमंत्री के सान्निध्य में जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है । जब-जब बाढ़ आती है,

पिछले वर्ष भी बाढ़ आई थी तो विभाग द्वारा, मंत्री महोदय द्वारा सरकार द्वारा हरेक संसाधन से बाढ़ पीड़ित परिवार को राहत अविलम्ब पहुँचाने का काम किया है ।

महोदया, हमारा तो अभी वैसा क्षेत्रीय कार्य की बात नहीं है, मैं जब भी माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग से प्रश्नकाल के दौरान हो या मिलकर हो, जब-जब मैंने क्षेत्रीय कार्य हेतु अपनी माँग रखी है, चाहे वह कोसी कटाव का सवाल हो, कहीं भी गाँव कट रहा हो तो तुरंत सुनवाई होती है । अभी भी काम हो रहा है और आगे भी होने की पूरी उम्मीद है ।

महोदया, अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का इतने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ तथा जिनके सान्निध्य में जल संसाधन विभाग अच्छे कार्य का नजरिया पेश कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ ।

माननीय सभापति महोदया, आपने भी मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ । इसी के साथ मैं सरकार द्वारा लाये गये बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द । जय बिहार ।

सभापति (डॉ0 रंजु गीता) : धन्यवाद । आपने समय का भी ख्याल रखा ।

माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र यादव ।

श्री रवीन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदया, आज मैं जल संसाधन विभाग विभाग के वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये पेश 3497.38 की माँग के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदया, यह धरती उनलोगों की है जिन्होंने नारी के सम्मान का मैसेज पूरे विश्व में दिया और आज की तिथि पर मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पीठासीन सदस्य के रूप में आज एक महिला हमलोगों का सम्मान बढ़ा रही हैं और अपने अधिकार को प्राप्त कर रही हैं ।

सभापति (डॉ0 रंजु गीता) : मेरी ओर से भी सम्पूर्ण सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रवीन्द्र यादव : महोदया, मैं सदन की सभी महिला सदस्यों को और इस प्रदेश की सभी महिला सदस्यों को, बहनों को महिला दिवस के अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा । यह धरती है दुर्गा की, यह धरती है रानी लक्ष्मीबाई की, यह धरती है रजिया सुल्तान की, यह धरती वैसे लोगों की है जो 9 दिन तक देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, यह धरती उनलोगों की है जिन्होंने नारियों के सम्मान में अनेकों कार्य किये हैं, यह धरती है स्वामी विवेकानन्द की जिन्होंने विदेश में कहा - Brothers & Sisters वहाँ लेडीज एण्ड जेन्टलमेन कहा जाता था, उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया और सारे मुल्कों को भी यह संदेश दिया - Brothers & Sisters का सम्बोधन किया जाय ।

सभापति महोदया, आज मैं बिहार की उन बेटियों को भी महिला दिवस के अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेषकर अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश

कुमार जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण के लिये सात निश्चय में से एक निश्चय उन्होंने बनाया और यह जो कदम है, कोई साधारण व्यक्ति का कदम नहीं है, यह कदम बहुत सोचे-समझे, गहराई और ज्ञान वाले व्यक्ति का प्रतीक है । उसी सन्दर्भ में शराबबंदी का कार्यक्रम लागू किया । माननीय मुख्यमंत्री की सभा में कुछ महिलाओं ने उठाया था कि शराबबंदी किया जाय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से राज्य को..... (व्यवधान) जल संसाधन पर भी बोलेंगे। अभी सुनिये मेरा भाषण, सुनने के लिये सीखिये ।

यह कोई साधारण स्टेप नहीं था, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देना चाहूँगा । ...क्रमशः ...

टर्न-12/आजाद/08.03.2018

...... क्रमशः ....

श्री रविन्द्र यादव : और बिहार के उन बेटियों को, बिहार की बेटी जो बंगलोर में सम्पन्न एथलेटिक अंजू कुमारी को धन्यवाद देना चाहूँगा महिला को, हमारे बिहार के आई0ए0एस0 बेटी भारतीय कश्यप को धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत से ऐसी बेटियां हैं, जिन्होंने बिहार के नाम को ऊँचा किया है ।

अब आईए जल संसाधन विभाग पर । जल संसाधन विभाग में तो वह काम हुआ है, जिससे आपलोगों को सीखना चाहिए और सुनना चाहिए । मैं विशेषकर माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वर्षों से लंबित पड़ी योजना कुकुरझप जो हमारे क्षेत्र में है और उन्होंने उसमें काम शुरू कराने की प्रकिया किया है । एक बड़ी राशि उन्होंने कुकुरझप में दिया था, इसपर मेरा एसेम्बली का क्वेश्चन था । मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ-साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे यहां गये थे, जब हमारे यहां कमीश्नरी में मीटिंग हो रही था हमारे क्षेत्र में तो हमने कुछ योजनाओं के तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया था, जिसपर बड़ी तेजी से काम चल रहा है । सिंचाई विभाग, वृहद सिंचाई और लघु सिंचाई, लघु सिंचाई जो है, माईनर इरीगेशन यह भी एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें हमारा क्षेत्र जो है जमुई, झाझा, झारखंड बनने के बाद बोर्डर पर पड़ता है । जो हमारे डैम हैं, जो हमारे यहां जल स्रोत हैं, उसमें लघु सिंचाई का भी बहुत महत्व है । कुछ वर्षों पहले लिफ्ट इरीगेशन हुआ करता था । स्टेट ट्यूबवेल की भी आवश्यकता है । हमारे यहां जल संसाधन विभाग है, उसके पॉच बड़े-बड़े डैम हैं, जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है । नकटी जलाशय योजना, पानी रखने की क्षमता 1120 एकड़ फीट, यह क्षमता वर्तमान में हमलोगों का नकटी जो है, वह कार्यरत है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि नकटी पर भी विशेष ध्यान दिया जाय । बॉयें टॉप पर पक्का रोड बनाया जाय, मुख्य

शहर और शाखा नहर पर पक्का रोड बनाया जाय । नहर में लाईनिंग कार्य खराब संरचनाओं की मरम्मति, गेटों की मरम्मति एवं वेटों की सफाई । नहर को हमलोग दो भागों में बांट सकते हैं । एक भाग है रिजरवायर का, दूसरा भाग है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का तो कहीं-कहीं नागी में, नकटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह हमारा कमजोर पड़ गया है, उस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा । नागी में, नकटी में अपर बदुआ नाला जलाशय योजना, यह चकाई प्रखंड के 9 गांवों को इससे सिंचाई होती है और बॉध की स्थिति 1985 में नदी का भाग यह जो है, डैमेज है, इसकी भी क्षमता बढ़ी है । वैसे ही बरनार जलाशय योजना, इससे भी पटवन होता है जमुई जिला के सोन्हो हमारा विधान सभा क्षेत्र झाझा, गिद्धोर, खैरा प्रखंड की सिंचाई होती है । इसकी भी सिंचाई क्षमता बहुत अपार है । योजनाओं पर काम 1996 से बन्द है । हमारे यहां कुकुरझप योजना है, नागी-नकटी, बरनार और अपर बदुआ यह भी हमारा डैमेज है, इसपर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा । कुकुरझप, जिसमें आपने अभी जो फंड दिया है, यह फंड हम सबलोग चाहते हैं कि तत्काल इसमें काम शुरू कराया जाय ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हमलोग दे सकें । निश्चित तौर पर कहीं भी अगर इरीगेशन, इरीगेशन किसी भी राज्य की रीढ़ होती है, सिंचाई राज्य की रीढ़ होती है तो इसको हमारी सरकार तत्काल प्रभाव से ज्यादा से ज्यादा सख्ती लगाकर हमलोग इरीगेशन को मजबूत करें ताकि हमारे यहां खेती की प्रबल संभावना है और बिहार का जो जमीन है, यह कोई साधारण उर्वरता नहीं है । आज देखिए बड़हिया का टाल, लखीसराय का जो इलाका है माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में, यदि जल स्रोतों का उपयोग किया जाय तो आप समझ सकते हैं कि उसकी अपार संभावनायें हैं । बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ की विभीषिका आती है, बाढ़ नेपाल की नदियों से आती है और जब यहां बाढ़ आता था तो आश्चर्य की बात है, बिगड़ जायेंगे लोग, अभी हल्ला करने लगेंगे, बाढ़ आता था तो उनके नेता कहते थे कि गंगा माई द्वारा आयी है, अब जरा सोचिये, गरीबों का क्या मजाक उड़ता था । भाषण देते थे.....

(व्यवधान)

वहां नहीं थे, कांग्रेस में थे, आर0जे0डी0 के एम0एल0ए0 कभी नहीं रहे ।

सभापति (डॉ0 रंजूगीता) : माननीय सदस्यगण, कृपया टोका-टोकी नहीं करें ।

श्री रविन्द्र यादव : सुनिये-सुनिये, सुनिये भोला बाबू, जब आप बोलें सुअर चराने वाले, भैंस चराने वाले, कागज चुनने वाले पढ़ना-लिखना सिखो, जवाब आपको देना जरूरी है । जब आप बोलें कि घोंघा पकड़ने वाले, सितुआ पकड़ने वाले तब हमलोग कांग्रेस पार्टी में थे और तब हमलोग वहां झोला-झक्कर फेंक कर आपके यहां गये थे, वहां जब गये तो भाषण सुने खाली कि 100 हाथी का कोई बल लगा दे लेकिन सामाजिक न्याय का सिक्कड़

नहीं टूटे । हुआ क्या, वहां क्या देखें, एक आदमी के यहां गांव में शादी था सभापति महोदया, शादी था तो वह पूछा अपनी पत्नी से ......

सभापति (डॉ0 रंजूगीता) : माननीय सदस्यगण, कृपया टोका-टोकी नहीं करें ।

श्री रविन्द्र यादव : सभापति महोदया, वह पूछा अपनी पत्नी से कि नेवता कहां दें , पत्नी ने कहा कि कहां-कहां नेवता दीजियेगा, बऊआ के नानी घर और हमारे नईहर दे दीजिए और अपना ससुराल में दे दीजिए । (व्यवधान)

सभापति (डॉ0 रंजूगीता) : माननीय सदस्यगण, कृपया शांति रहिए ।

श्री रविन्द्र यादव : महोदया, नेवता जब पड़ने लगा तो बोला कि बऊआ के नानी घर में, हमारे नईहर में और अपना ससुराल में नेवता दे दीजिए और हो गया सामाजिक न्याय । उस समय भाषण देते थे लोग कि 60 हाथी का कोई बल लगा दे, एक-एक नेता को हम जानते हैं। कांग्रेस पार्टी को हमलोग देखें हैं, पहले कांग्रेस में ही थे । दो बार कांग्रेस से एम0एल0ए0 थे । (व्यवधान)

सभापति (डॉ0 रंजूगीता) : माननीय सदस्यगण, कृपया शांत हो जाईए । आप बोलिये, आपका समय भी कम है ।

श्री रविन्द्र यादव : सर, कांग्रेस पार्टी में भी देखें हैं प्रमोद भाई, नेता बोलते थे कि पहले खाया माई को, फिर खाया भाई को और अब खायेगा कांग्रेस-आई0 को । आज कांग्रेस के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि वैसे लोगों के साथ नहीं रहिए .....

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 रंजूगीता) : माननीय सदस्य, आप बोलिये । कृपया माननीय सदस्य सुनिये ।

श्री रविन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदया, यह धरती है अम्बेदकर की, बिहार की धरती, यह धरती जो है त्यागियों की धरती है, यह धरती है राजेन्द्र बाबू की, यह जयप्रकाश नारायण जी की धरती है, यह धरती है क्रांतिकारियों की, यह धरती है वीरकुँवर सिंह की । जरा आप बताईए, अम्बेदकर के पास रात में एक व्यक्ति गया दो बजे, अम्बेदकर जग रहे थे,

.... क्रमशः ....

टर्न-13/अंजनी/दि0 08.03.18

श्री रविन्द्र यादव : क्रमशः..... उन्होंने कहा कि सर आप जग रहे हैं(व्यवधान) सुनिए न । वे बोले कि इसलिए कि हमारे लोग सो रहे हैं । इसलिए हम जग रहे हैं । हमलोग सुबह में जाते हैं चिड़ियाखाना टहलने, ललन बाबू भी जाते हैं सबेरे-सबेरे, हम भी डॉक्टर हैं, एक दिन हमलोग टहल रहे थे, बहुत जोर से तबला-डुग्गी का आवाज आ रहा था,

हमलोग बोले कि क्या हो रहा है भई, बोला कि मुख्यमंत्री के यहां लड़का का नाच हो रहा है । उस दिन का भी मुझे याद है, वह दिन भी मुझे याद है ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है, बैठ जाइए ।

श्री रविन्द्र यादव : ऐसे लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं , जो यादव को बीस साल लड़कवाइन गवां दिये खाली मुरैठा बांधकर लड़कवायन गेलो । अब बाल्टी में दूध पिय और तू जा ह मजा मारे हॉलिकॉप्टर पर और यादव दूध बेचे । चारा तो खा गये, यादव का तो गला काट दिये आप लोग, समाज से कटवा दिये ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : अब आपका समय-सीमा समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री अमित कुमार, आपका समय पांच मिनट है ।

श्री अमित कुमार : सभापति महोदया, मैं आज जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ (व्यवधान)

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : आप शुरू कीजिए अमित कुमार जी ।

श्री अमित कुमार : महोदया, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ । मैं महिला दिवस के अवसर पर सभी अपने महिला साथियों को धन्यवाद करता हूँ और यहां पर सभी सदस्यों को भी धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे बोलने का मौका मिला है, बहुत गर्व की बात है, लोग बता रहे हैं कि बहुत ही सुशासन की सरकार चल रही है, हमलोग देखे अभी बीते दिनों जून-जुलाई में बाढ़ आया और किस तरह से बांध का तट टूटा, किस गांव में कहां-कहां किस तरह से तड़पे, हमलोग वहां थे । लोग कहते हैं कि चूहा बांध काट दिया, यह सोचने की बात है कि चूहा से बांध कैसे कटेगा । क्या कमजोरी थी, उसको याद करना होगा, उसका मंथन करना होगा, उसके जड़ तक जाना पड़ेगा । हमने उस दौरान देखा कि जो कटाव हुआ था, वहां पर लोग बोरा भरकर भी भर रहे थे, जिसका रिपोर्ट हमने माननीय मंत्री जी को डी0एम0 के थ्रू भेजा था। उस पर क्या कार्रवाई हुई (व्यवधान) वे बोल रही है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। ये क्या बोलेंगी, इनसे पूछिए, इनके विधान सभा में जो लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, उनको आज तक पैसा मिला है क्या ? समझने की बात है ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : आप आसन की ओर देखकर बोलें ।

श्री अमित कुमार : यह समझने की बात है । क्या स्थिति हुआ था भागलपुर में ? जिस दिन सी0एम0 को उद्घाटन करना था, एक दिन पहले बांध टूट जाता है । यह सुशासन की सरकार है । यह मंथन करने की चीज है । हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी, बिहार के किसान खुशहाल नहीं होंगे, हमने पढ़ा है । लेकिन मंथन करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने और करने से नहीं होता है।(व्यवधान) नहीं-नहीं, आपको सोचना पड़ेगा मंत्री जी कि हमलोग जिस इलाके से आते हैं, वहां खेती के अलावा कोई उपाय नहीं है । पिछले दस साल से आपलोगों की सरकार है,

वहां सिंचाई की क्या व्यवस्था हुई है, यह आपको मंथन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि लोग कैसे जी रहे हैं । एकमात्र खेती है किसान का ईख का, उसका भी भुगतान आज के डेट में सरकार नहीं करा पा रही है । सौ करोड़ से उपर बाकी है किसान का लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ है। किसान भूखे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उसको भी आपको मंथन करना पड़ेगा कि कैसे जनता जियेगी, जनता कैसे आगे बढ़ेगी । जहां तक माइनर एरिगेशन की बात है, वहां भी देखिए पंप हाउस है, जब आप पूछियेगा कि यह पंप हाउस चालू है तो जवाब आयेगा कि आपके यहां 20 पम्प हाउस है, 20 पम्प हांउस में से 10 पम्प हाउस चालू है तो आप लोग उनसे पूछिए कि उसका कितना रकबा है और कितना रकबा में वे पटाव करते हैं, यह भी जानने की जरूरत है, जितना रकबा उस पंप हाउस को तय किया गया है, उनके खेतों तक पानी पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है लेकिन कहीं ऐसी घटना नहीं है और कहीं पंप हाउस चालू नहीं है । हमारे माननीय मंत्री जी जब पिछले साल गये थे तो मैंने प्रश्न किया था कि हमारे क्षेत्र में दस पम्प हाउस चालू नहीं है तो फिर से हम दोबारा मुख्यमंत्री जी गये तो फिर से हमलोगों को जवाब मिला कि अभी उसपर विचार किया जा रहा है, डी0पी0आर0 एक साल से जब हम अपने मुख्यमंत्री जी के यहां गुहार लगाये, जो सरकार है, उनके नेतृत्व में हमलोग चल रहे हैं, उनके यहां गुहार लगाये, एक साल में एक भी पंप हाउस चालू नहीं हुआ और जवाब मिलता है कि अभी विचाराधीन है और अभी डी0पी0आर0 बन रहा है । तो हमलोग दिशा-निर्देश भी चाहेंगे सरकार से कि क्या दिशा निर्देश है, अभी डी0पी0आर0 बन रहा है । छः महीना, साल भर में डी0पी0आर बनेगा फिर चुनाव आ जायेगा तो क्या जनता को हम जवाब देंगे तो किस प्रणाली से काम कर रहे हैं, कैसे अपने अफसर पर अंकुश लगायेंगे, इनको मंथन करके हमलोगों को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आज जनता देख रही है । मैं धन्यवाद करता हूँ टी0डी0पी0 के लोगों को विशेष राज्य के दर्जा पर उनलोगों ने सरकार से बाहर आने का काम किया । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि जो सौदा इन्होंने सरकार बनाने के लिए बी0जे0पी0 के साथ किया, क्या सौदा किया, क्या सोच रखा, उस समय इन्होंने क्यों नहीं शर्त रखा कि विशेष राज्य की दर्जा दीजियेगा तो हम आपको चोर दरवाजे से सरकार में शामिल करायेंगे, ये भी आपको मंथन करके सोचना चाहिए, यह शर्त भी रखना चाहिए था । बिहार की जनता को आप धोखा दे रहे हैं, जो जनता आपको जीताकर भेजा, उसके साथ आप दगाबाजी किये हैं, अगर दगाबाजी किये तो बिहार की जनता के हित में आपको मंथन करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि आपने सिगनेचर कराया था विशेष राज्य की दर्जा के लिए, जब यू0पी0ए0 की सरकार थी, आज क्या हुआ ? आपने क्यों नहीं उनसे बात की कि आप विशेष राज्य की दर्जा दीजिए ताकि हम जनता को जवाब देंगे कि भई विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, इसलिए हमने चोर दरवाजे से बी0जे0पी0 के

साथ सरकार बनाने का काम किया है । यह सरकार बोलती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं । आप याद कीजिए, जब यू0पी0ए0-वन की सरकार थी, नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आये थे, उस समय यू0पी0ए0 की सरकार ने बिहार में कितना रूपया दिया, सड़क का जाल बिछा, जिस रूपया से नाम नहीं लेते हैं, आज क्या हुआ, आपकी सरकार यहां भी है और आपकी सरकार केन्द्र में भी है, आपको मंथन करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आज वह रूपया क्यों नहीं आ रहा है । आज सड़कें क्यों नहीं बन रही है । मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद जी का, उन्होंने जब सेंटर में कैबिनेट में मिनिस्टर थे और वे कितना रूपया का बौछार किये, 35 हजार करोड़ एक बार में बिहार राज्य को देने का काम किया तो वह सोच था । सरकार किसी को हो लेकिन सोच था, बिहार को आगे बढ़ाने की बात, बिहार के लोगों की सोच की बात थी तो उन्होंने एक बार में 35 हजार करोड़ रूपया फर्स्ट लॉट में रूपया भेजने का काम किया । आज आप पूछिए बी0जे0पी0 वालों से रूपया क्या भेजेंगे जो पहले दस परसेंट था, उसको 40 परसेंट कर दिया गया । क्या हमारे साथ मोदी टैक्स लगेगा, ये कैसे चलेगा, कैसे गुमराह कीजियेगा । घबराइए नहीं, समय आ रहा है, अभी बाई इलेक्सन में आपको पता चल जायेगा कि बिहार की जनता आपको कितना चाहती है । बाई-एलेक्सन में आपको पता चल जायेगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है ? आपको सोचना चाहिए । अभी ये लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, नागालैंड में जीत गये हैं, मिजोरम में जीत गये हैं ,सरकार बनाये हैं, मेघालय में सरकार बनाये हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं लेकिन आप सोचिए कि किस परिस्थिति में आप वहां जीते हैं चूंकि 25 साल से सी0पी0एम0 वहां की, किसी भी सरकार का दस-पन्द्रह साल हो जाता है तो उसका रियेक्सन होता है, उसके रियेक्सन में आप वहां आये हैं ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अमित कुमार : गुजरात में आप सोचिए नाक में दम कर दिया आप लोगों को । मध्यप्रदेश को देखिए, राजस्थान को देखिए कि वहां क्या हुआ है, समय आ रहा है....

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री अमित कुमार : जनता आपको बतायेगी, जनता आपको जवाब देगी । जल संसाधन की बात कर रहे हैं, हम आपको याद. दिलाना चाहते हैं कि हमारे यहां.

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव जी । आपका पांच मिनट है ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदया, मेरा समय पांच मिनट है ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : आपका समय दस मिनट है । माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव।

टर्न-14/शंभु/08.03.18

श्री प्रहलाद यादव : महोदया, आज जल संसाधन, लघु सिंचाई और योजना एवं विकास ये तीन विषय है । इसके कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मंत्री जी नहीं हैं यह भी तो विचारणीय बात है, लघु जल संसाधन मंत्री नहीं है । मंत्री जी दो विभाग के हैं एक विभाग उनके पास है, यह स्थिति है । आज जो विषय यहां पर प्रस्तुत किया गया है, आज के दिन आप कृषि मैप तृतीय बनाये हैं, कृषि मैप भी तृतीय बनाया गया है और जैविक खाद का ज्यादा उत्पादन हो, उससे ज्यादा खेती हो इसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं । सिंचाई विभाग वृहत् और मध्यम में आपका 53.53 लाख हेक्टर को आच्छादित करना है सिंचाई विभाग से और आप अभी तक किये हैं 29.69 इसमें कितना अंतर है । आप जो तृतीय कृषि मैप तैयार किये हैं, जब तक खेत में पानी नहीं जायेगा, पैदा नहीं होगा तो कल्पना कैसे कर सकते हैं ? इस विभाग का कल्पना कैसे कर सकते हैं ? सबसे दुर्भाग्य है कि आप डबल इंजन हैं । अब पहले वाला कोयला वाला इंजन हैं कि इलेक्ट्रीक वाला इंजन हैं यह हम नहीं जानते हैं । इस विभाग को जो पिछला बजट में आवंटन किया गया था उससे आप कम किये हैं तो डबल इंजन का मतलब यही होता है कि डबल इंजन बन जाइये और आधा-आधा आवंटन करते जाइये तो आप कितने दिनों में इसको पूरा कीजिएगा, दुर्भाग्य है । इसको पूरा करने के लिए तो डबल इंजन में डबल पैसा देना चाहिए ताकि जो लक्ष्य है- वृहत् और मध्यम सिंचाई विभाग का जो लक्ष्य है जितने लाख हेक्टर उसको पटवन के लिए, हमको वहां तक पहुंचना है वह तो आप पूरा नहीं कर रहे हैं । दूसरी बात है कि यहां की भौगोलिक स्थिति जो है वह विचित्र है- एक तरफ तो बाढ़ ही रहता है और दूसरी तरफ सुखाड़ ही रहता है । यह चिंता का विषय है । नेपाल आपको जान नहीं छोड़ रहा है, हर वक्त जब ज्यादा पानी होता है, नेपाल आपके तरफ पानी छोड़ देता है । जो भी आपका काम होता है एक साल में, सबको तहस नहस करके बराबर कर देते है । डबल इंजन है- नेपाल का जो पानी है वह पानी अधिक होने पर उसकी व्यवस्था हो ताकि हमलोगों को बाढ़ से बचाया जा सके । नॉर्थ बिहार को इसके लिए तो आप एकदम नीचे और उपर दोनों बराबर हैं तो अब मदद ले सकते हैं । उसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है । लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, चूंकि आपने योजना बनाया था कि जो छोटी-छोटी नदी है जहां भी है, उसको हम इस रूप में लायेंगे सिंचवन में परिवर्तन करेंगे जिससे कि बाढ़ का बहाव कम होगा, लेकिन वह भी हम समझते हैं कि प्लानिंग में चल रहा है, होगा कि नहीं होगा यह कहना मुश्किल है, चूंकि अभी तो आपको मौका था, बहुत अच्छा मौका था कि आप केन्द्र सरकार के मदद से यह काम कर सकते थे । वह भी हमको लगता है कि नहीं होनेवाला है, जो स्थिति बनी हुई है । इधर आपका सुखाड़ ही रहता है उसके लिए जो समतलीय है और भूगर्भ जल है उसके लिए आपको करना चाहिए तो जो पिछली बार जितना पैसा लघु सिंचाई में दिया गया, उससे इस बार कम दिया गया तो डबल इंजन खाली कहने से नहीं चलेगा । डबल का मतलब हुआ कि डबल काम, तेजी से

काम, लेकिन तेजी से काम कहां हो रहा है, यह स्थिति बनी हुई है । निश्चित रूप से यह जो विभाग है, खासकर के कृषि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है । मैं प्रयास करूँगा माननीय मंत्री जी से और सरकार से कि निश्चित रूप से इस तरह का जो महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें लक्ष्य को प्राप्त कीजिए । जब तक आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप जो कृषि मैप बना रहे हैं और जो व्यवस्था कर रहे हैं वह सब आपका फेल्योर हो जायेगा । आप लीजिए इस तरह की योजना लीजिए, अभी मौका है और लेकर इसको पूरा कीजिए । जहां तक सिंचाई विभाग की बात है- माननीय मंत्री जी का प्रयास होता है और इनको जितना पैसा देना चाहिए उतना अगर पैसा देते तो हम समझते हैं कि आपका 53.53 का जो लक्ष्य था वह बहुत जल्दी पूरा होता, लेकिन लगता है कि मंत्री जी को भी कहीं-कहीं आप पीछे छोड़ रहे हैं, जिसके कारण यह काम आगे बढ़ना मुश्किल है । आप शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य विभाग में दिये हैं उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन काम तो करवाइये । जो विभाग में पैसा देने के बाद वह काम टाइम पर हो रहा है, उसको आप पैसा नहीं देते हैं और जो विभाग में लटका कर रखता है सालों भर - एक साल का बजट बनता है और उसको लटका देते हैं जिसके कारण वह काम नहीं होता है और पैसा भी लैप्स हो जाता है । निश्चित रूप से जिस विभाग में जितना ही पैसा आप आवंटित करते हैं तो समय पर उसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन हर विभाग को आप देखिएगा । माननीय मंत्री जी हम समझते हैं कि जितना पैसा मिला हुआ है उसको करीब करीब एक साल में पूरा किये होंगे और अन्य विभाग की यह स्थिति नहीं है । लघु जल संसाधन में क्या है आपका 10 हजार से ज्यादा राजकीयकृत पंप है और आप अभी तक जो रिपोर्ट दिये है मुश्किल से 4 हजार से कुछ ज्यादा होगा, बाकी किस कारण से बंद है, क्या आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं । लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर तरह से प्रयास करना पड़ेगा । लक्ष्य आपका पूरा नहीं हो रहा है आखिर क्या कारण है, क्या कमी है ? इस तरह से ये दोनों विभाग जो है, यह विभाग जिस दिन फेल होगा, आपका कृषि विभाग फेल होगा और जब कृषि विभाग फेल होगा तो आपका जो मैप बनाये हैं वह धरा का धरा रह जायेगा । इसलिए निश्चित रूप से इस तरह का जो बजट है और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में निश्चित रूप से और चुस्त दुरूस्त करने की जरूरत है । यह स्थिति है । सेंटर से आया था गंगा में गाद वाला कहा कि गाद है और गंगा की जो स्थिति है ।

सभापति(डॉ0 रंजु गीता) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री प्रहलाद यादव : मैडम दो मिनट । अपने क्षेत्र की बात भी तो कर लें, कहना तो बहुत था, लेकिन खैर जो समय मिला ठीक है , हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे । हमारे क्षेत्र में एक कुन्दर नहर है । उसमें काम चल रहा है, लाइनिंग का काम चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत क्या है कि काम जिस तरह से होना चाहिए उसमें कमी है । हम बराबर माननीय मंत्री जी से, प्रधान सचिव से, अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता सबसे हमलोग संपर्क करके रहते हैं,

उसको जरा बढ़िया से बना दीजिए । थोड़ा उसमें देखिए दिक्कत हो रहा है । एक मोरवे डैम है, माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वह मोरवे डैम जिस तरह से कुन्दर से लेकर बनौचा बीयर तक लाइनिंग कर रहे हैं उसी तरह से मोरवे डैम से कजरा तक कर दीजिए । एक चीज माननीय मंत्री जी दिक्कत हो रहा है आप मेन को बना रहे हैं लाइनिंग करके बढ़िया से बना रहे हैं, लेकिन उसका शाखा नहर गाद से और घास से भरा हुआ है । जब मेन नहर बन भी जायेगा और शाखा नहर नहीं बनेगा तो फिर बनने न बनने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा । चाहे मोरबे नहर हो, चाहे कुन्दर नहर हो, चाहे बासपुर नहर हो इन सारे की यही स्थिति है । एक लखीसराय जिला का मननपुर बाजार क्या हुआ है कि सी0ओ0 साहब की कृपा से वहां लोग आपका जमीन सिंचाई विभाग का उसकी बंदोबस्ती करवा लिया और मेन नहर जो जाता है, कई एक पंचायत को पटाता है, सैंकड़ों एकड़ जमीन पटेगा उससे और वहां पर मेन बाजार में जाकर उसपर घर बना लिया है ।

क्रमशः

टर्न-15/ज्योति/08-03-2018

क्रमशः

श्री प्रहलाद यादव : घर बना लिए है । अब वह नहर का जो दायरा है, छोटा हो गया है, हम चाहेंगे कि आप पक्कीकरण करके ढक्कन दे दीजिये ।

सभापति (डा0 रंजू गीता): माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री प्रहलाद यादव : मैड्म एक मिनट, हमलोगों के पार्टी का समय बहुत है । हम अपने पार्टी से ले लेंगे 2 मिनट का समय, उसमें क्या दिक्कत है ? कम से कम बोलने तो दीजिये । हम ले लेंगे कोई दिक्कत है ? एक बुढ़वा कोल है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी आश्वासन भी दे चुके हैं ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय, आपका समय 10 मिनट है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सभापति महोदया, जल संसाधन विभाग के बजट पर बोलने के लिए हमको अवसर मिला है । महोदया, बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक दौर से गुजर रहा है । राष्ट्र के विकास में बिहार राज्य की सहभागिता कई गुणा बढ़ी है । विगत कुछ वर्षों से अपने प्रबल मानव संसाधन के बल पर एक अभूतपूर्व मुकाम हासिल किया है । राज्य सरकार के कुशल आर्थिक प्रबंधन और सामाजिक योजनाओं की भूमिका अद्वितीय है । राज्य के आर्थिक विकास की संरचना को समग्रता के साथ मजबूती प्रदान किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है ताकि समाज के हर वर्ग का समानान्तर विकास और प्रगति हो सके । अभी विगत समय में बाढ़ का मुकाबला बिहार सरकार बड़ी मजबूती से की है । जहॉं भी बाढ़ आयी है तो एक मानवीयता और एक सरकार की जो तत्परता हुई, यह पहली बार हुआ है कि बिहार में बाढ़ का मुकाबला बड़ी समर्पण और बड़ी मजबूती से किया गया है । हमको लगता है चाहे कोई भी पंचायत मे विभीषिका आयी थी, चाहे

एस.डी.आर.एफ. का जवान हो , एन.डी.आर.एफ. का जवान हो, तो हरेक तरह से केन्द्र सरकार का भी सहयोग रहा है और बिहार सरकार के सहयोग के चलते बाढ़ की विभीषिका का बड़ी मजबूती से मुकाबला किए हैं । साथ ही बिहार की स्थिति, हमको लगता है कि देश में उसकी प्रतिष्ठा बड़ी तेजी से बढ़ रही है । अभी वर्तमान में भ्रष्टाचार की जो टौलरेंस नीति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जो अभी प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार जो सार्वजनिक जीवन की शूचिता के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दिया गया है, तो यह बड़ी बात है । ये बिहार की गौरव की बात है । बिहार के इतिहास को लगता है जो पौराणिक इतिहास था, उसको मजबूती प्रदान किया जा रहा है । यह व्यक्तिगत जीवन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में यह लगता है पहली बार लग रहा है गांधी जी का सपना था, गांधी जी का जो इस देश में जो चम्पारण का सत्याग्रह आन्दोलन बिहार से शुरु किया था, बड़ी उम्मीद से आज हमारे नीतीश कुमार जी उसको पूरा कर रहे हैं अपनी निष्ठा और समर्पण से । साथ ही, बिहार प्रशासनिक सुधार मीशन सोसायटी जिला पदाधिकारी, बांका को भी सूचना एवं प्राद्यौगिकी के उपयोग का सरकारी विद्यालयों में गुणवतापूर्ण शिक्षा हेतु उन्नयन बांका अभियान के लिए कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस एवार्ड भी प्रदान किया गया है । नालन्दा को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । मक्का उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है । इस आधार पर म्यूजियम में भी अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्डिंग कौरपोरेट कौम्यूनिकेशन श्रेणी में आई0एफ0 डिजाईन एवार्ड के लिए चुना गया है । साथ ही पटना स्थित सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर को सी.आई.डी.सी. द्वारा उत्कृष्ट वस्तु शिल्प के लिए दसवां विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए चुना गया है, इसलिए हमको लगता है कि बिहार की जो स्थिति थी और बिहार का जो पौराणिक इतिहास था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है । याद करिये, जो ये कभी शराब बंदी- एक शराब बंदी से खास कर लगता है जो गांधी, अम्बेदकर, लोहिया, जे.पी., कर्पूरी का जो सपना था, वह पूरा हो रहा है । कहते थे कि सामाजिक समानता के लिए सामाजिक बंधुत्व के लिए और सामाजिक समानता के लिए जितना इतिहास था, हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी उसको पूरा कर रहे हैं । एक शराब बंदी के चलते जो समाज का अंतिम व्यक्ति था, चाहे कमजोर वर्ग हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, आज उनके अंदर में एक तेजी से शिक्षा प्रतिशत और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है । सामाजिक प्रभाव बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में वह आगे बढ़ रहा है । शराब गरीबी का मुख्य कारण था । शराब उनकी नैतिकता को कमजोर कर दिया था । आज शराबबंदी होने के बाद लगता है कि बिहार की दृष्टि, आम लोगों को - जो अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़े हमारे योद्धाओं ने, हमारे महापुरुषों ने लड़ा

था, उसकी भरपाई हमारे नीतीश कुमार जी कर रहे हैं । यह बड़ी बात है, ठीक बात है कि हमारे विपक्षी नेता बड़ी मजबूती से कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है । हम पिछले दिन भी बोले कि आपको नैतिकता मजबूत करनी होगी । जिस चेयर पर अभी आप बैठे हुए हैं , विपक्ष की कुर्सी पर तो कभी कर्पूरी ठाकुर बैठते थे, जो अति पिछड़ा के लिए कमजोर के लिए सारा जीवन समर्पण कर दिए । अपने व्यवहार से उनका अनुशासन अनुकरणीय है । आप कहॉं खड़ा हैं ? आपके विपक्षी दल के नेता मेज की तरफ बढ़ते हैं । आपके खिलाफ में कोई मंत्री जी बोल देते हैं, तो दोनों हाथ फड़काने लगते हैं । कहॉं गया आपका अनुशासन ? आप शराबबंदी की बात करते हैं, तो शराब बंदी में आपकी नैतिकता कहती है कि आगे हो कर आना चाहिए । मजबूती से सुन्दर बिहार बने, इसमें आपको सहयोग देना चाहिए । आज भी विगत में जो भूमिका अपनाये लगता है कि आप चाहते हैं पुनः जंगल राज में जांय । अब जंगल राज नहीं चाहते लोग । अब नीतीश का राज चाहते हैं लोग , अब लोग नीतीश का राज चाहते हैं और सुनिये बिहार जिस रुप में चाहे वह 7 निश्चय हो, शराब बंद हो गया, हो सकता है आपके यहॉं खुला हो । हम बता रहे हैं आपको सभापति महोदया, हमको लगता है कि बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गांधी जी का जो सपना है, चाहे वह अम्बेदकर, कर्पूरी ठाकुर, जे.पी. और लोहिया के सपने को साकार कर रहे हैं । हमको लगता है कि सामाजिक समानता बड़ी तेजी से मजबूत हो रहा है और बिहार का जो भी क्षेत्र है जो भी विभाग हरेक विभाग में प्रगति के रुप में तेजी से बढ़ रहा है । हमको लगता है कि आने वाले समय में चाहे सायंस हो या सांयस टेक्नोलॉजी हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या जल संसाधन हरेक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे हैं । आज ये ठीक कह रहे हैं कि कल आप कृषि पर बोल रहे थे । कृषि को भी एक रुप दिए हैं वह नीतीश कुमार जी हैं । कृषि को भी ये उद्योग रुप देंगे । यह नीतीश जी की देन है, नीतीश कुमार जी की सोच है, आप भी सोच इसलिए बदलिये कि आप कभी घोटाला की बात करते हैं, तो कभी होम डिलीवरी की बात करते हैं । आपको नेचर बदलना होगा । मै विपक्षी भाईयों से कहना चाहता हूॅ वह दबंगगिरी नहीं चलेगी और अब जो विकास की बात करेगा, उसको जनता साथ देगी, यह लठैती वाला जमाना चला गया अब, अब नहीं चलेगा । अब खास कर पिछड़ा और महादलित खास कर अति पिछड़ा और महादलित शिक्षित भी हो रहे हैं और आगे तेजी से अपने को पहचान रहे हैं । समझ रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जैसे मजबूत इरादा वाले निष्ठावान और ईमानदार नेता हमारे साथ हैं । बिहार तेजी से बढ़ रहा है । आपके ऊपर लोग नहीं भरोसा करते । आप याद करिये कि अभी सृजन घोटाला की बात कर रहे थे, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, कह रहे थे कि 20 हजार के जुर्माना की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में कभी आर.सी.पी. टैक्स की बात कर रहे थे । महोदय, दिल्ली से जब आर.सी.पी. टैक्स चलता है, तो उनकी बेटी आई.पी.एस. होती

है, आपने कभी कल्पना और कभी सोचे नहीं और न कभी सोचेंगे, आप कौन कौन बात करते हैं इस सदन में पिछले दिन विपक्षी दल के नेता आर.सी.पी. टैक्स की बात कर रहे थे, तो सृजन की बात कर रहे थे, सृजन तो छोड़िये, तो सृजन में माननीय मुख्यमंत्री ने जॉच का आदेश दिए हैं । मुख्यमंत्री जी ने जॉच का आदेश दिया है । आप कहाॅं हैं ? दूसरी बात और सुनिये । आप सृजन घोटाला करके बिहार को बदनाम कर रहे हैं । आप अपने चेहरा को बदलिये । आप अपना चेहरा नहीं बदलियेगा तो जनता आपके चेहरा को खत्म कर देगी, आपका चेहरा देखने लायक नहीं रहने देगी । अब बिहार को विकसित बिहार कहिये । अब लोग विज्ञान सोचते हैं और विज्ञान को खोजते हैं और अब लोग विज्ञान को खोज रहे हैं । अब सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करना चाहते हैं । आप अपने को बदलिये ।

क्रमशः

टर्न-16/08.3.2018/बिपिन

श्री लक्ष्मेश्वर रायः क्रमशः आप अपने को बदलिये और सुंदर बिहार के लिए नीतीश कुमार महान योद्धा हैं जिनका अपना एक ही दृष्टिकोण है कि बिहार की सेवा करना, मेवा खाना नहीं है भाई, नीतीश कुमारजी सेवा भाव से राजनीति करते हैं । नीतीश कुमार जी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार की गौरव को देश और दुनिया में मजबूत किए हैं । इसलिए हम सबों से चाहेंगे कि बिहार की सहभागिता में सारे लोग का योगदान रहे । साथ ही, यह जल संसाधन..

सभापति (डॉ0 रंजू गीता): अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री लक्ष्मेश्वर रायः आपका जो बजट है, बड़ी मजबूती से और बड़ी तेजी से और बड़ी प्रतिबद्धता से यह विभाग बहुत साहसी है । हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, बहुत साहसी और कर्मठ भी हैं । बिहार का एक आर्थिक और महत्वपूर्ण संपदा है हमारा जल और कृषि आधारित प्रदेश होने के नाते जीविका के साथ-साथ समग्र समृद्धि के लिए एक ओर बेहतर सिंचाई विकसित करने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभिषिका से जानमाल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चुनौती है । बढ़ती आबादी एवं अन्य क्षेत्रों में जल की बढ़ती मांग को लेकर, मांग के कारण इस संपदा पर दबाव बढ़ता जा रहा है । इस परिस्थिति में जल का समुचित संरक्षण एवं संचालन करना बाढ़ के जल प्लावन से सुरक्षा प्रदान करना....

सभापति (डॉ0 रंजू गीता): माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, अब आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्या श्रीमती भागीरथी देवी । आपका समय 11 मिनट है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या श्रीमती भागीरथी देवी ।

श्रीमती भागीरथी देवी : आदरणीय सभापति महोदया, आज विधान सभा में सिंचाई पर चर्चा हो रही है, । माननीय सदस्य लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोले हैं लोग, हम यही कहना चाहते हैं माननीय मंत्री ललन बाबू से कि थोड़ा ध्यान देते हुए माननीय सदस्य के ऊपर ध्यान दिया जाए कि हर क्षेत्र में समस्या है। आज हमारे रामनगर क्षेत्र में, आपलोगों को भी जानकारी होगी, पूरे प्रशासन को जानकारी होगी कि जब खुद हम बाढ़ में बह गए थे तो दहने के बाद हाथ पकड़ कर लोग हमें बाहर निकाले । इतना भीषण बाढ़ था पश्चिमी चम्पारण में कि वहां के गवनाहा प्रखंड में, हालांकि सब कुछ जानकारी है सारे लोगों को, ललन बाबू भी जानते हैं, इतना बड़ा बाढ़ जिन्दगी में किसी ने नहीं देखा होगा । हम खुद भुक्त भोगी हैं, मैं खुद डूब गई थी । आज जो काम वहां पर हुआ है, ललन बाबू को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे बाढ़ आई, माननीय मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी, जहाज से चारो तरफ हेलीकॉप्टर से घूम-घूम कर जहां कहीं भी कुछ कमी थी तो वहां ये लोग गए और इनलोगों ने सामानों को पूरा किया । ललन बाबू भी अगर उसमें कुछ कमी रह गया था, तो हम ललन बाबू मंत्रीजी से जरूर कहूंगी कि आखिर माननीय सदस्य लोग बोल रहे हैं, तकलीफ की वजह से लोग भाषण देना शुरू कर देते हैं, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बोल रही हूं । बात है कि हमारे यहां नदी नहर में चला गया है और नहर चला गया है नदी में । आज हमारे यहां समस्या यह है कि जो नहर से छोटा-छोटा पईन निकलता है तो उस पईन से किसान के खेत में पानी पटता है, हम माननीय मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूंगी कि उस छोटे-छोटे पईन को जो नहर से निकल कर किसानों के खेत में जा रहा है तो वह आज पूरा किसान, वह जो छोटा-छोटा नहर है, वह एकदम खराब हो गया है और बंद हो गया है, इसपर ध्यान देकर माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगे और छोटा-छोटा जो पईन है उसको खोलवाया जाए जिससे किसान के खेत में पटवन हो और किसान उसी से जीता है और उसी से मरता है । हमारे यहां रामनगर में वलवनिया गांव है, वहां उस गांव में नहर, खेत, रोड एकदम बराबर हो गया है, एकदम बराबर हो गई है । बालू फेके हुए है बाढ़ । इसमें किसी का दोष नहीं है । वह तो बाढ़ के ऊपर है । बालू तोप दिया है, किसान के खेत का मुआवजा मिल गया है, बॅटा रहा है । हमारे यहां जितना भी किसान के खेत में बालू का पटवन हो गया है, जितना रब्बी क्षति हुआ है वह सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ ब्लॉक से पैसा सबलोग के हिसाब से मिल रहा है किसान लोग को । इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि माननीय सदस्य जो बोले हैं स्लुइश गेट देने के लिए, ताकि अगर फिर आ जाए कहीं-कहीं तो उसके लिए हम अपने तरफ से आपको धन्यवाद दूंगी कि हमारे किसान का उद्धार हो जाएगा और किसान बढ़िया से अपनी खेती गृहस्थी कर ले । गवनाहा क्षेत्र में दमाट जाने वाला पुल, 10साल हो गया, हमारे हल्ला

करने पर ही बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं, उपमुख्यमंत्रीजी से भी बोली थी, बहुत बड़ा पुल बना लेकिन बाढ़ जो आया है तो दोनों साइड से काटकर पुल को खड़ा कर दिया गया है और बाढ़ दोनों साइड से निकल गया । अब गांव के लोग तबाह हैं कि अगर दोबारा बाढ़ आ जाए, गवनाहा में मेला लगता है, सहोदरा में मेला लगता है, सारे लोग जानते हैं कि सहोदरा माई का मेला चैत में लगता है और रास्ता बंद हो गया है, दो-तीन बार ब्लॉक जाकर हमने कहा कि कम-से-कम रास्ता तो बनवा दिया जाए ताकि जनता को आने-जाने के लिए सुविस्ता हो जाए तो दमाट जाने वाला पुल पर ध्यान देकर ब्लॉक से बोल दिया जाए तो वो लोग भरवा देंगे । अभी तक नहीं भरा गया है । आदमी का आवागमन हो जाएगा । सहोदरा माता का पूजा करने जाने वालों को कठिनाई हो रही है । इसपर ध्यान दिया जाए । नहर को लेकर हमारे रामनगर क्षेत्र में गवनाहा में अगर पुल के कटाव में बोरिया में कसकर बालू से जो भरा जा रहा है, बन रहा है लेकिन बालू कस के रोड जो बन रहा है, वहां दो नंबर का काम हो रहा है, बालू के बंद होने से । माटी सहित मिलाकर जल्दी-जल्दी माफिया ठीकेदार लोग को दे दिया गया है । जाकर देख जाता है, रोका जाता है, पूछा जाता है लेकिन वे लोग डरते नहीं हैं । उसका जांच करवाया जाए कि रोड कैसे बना है गवनाहा में । वह जंगल इलाका है । जंगल इलाका में कोई आफिसर नहीं जाते हैं और वहीं के लोग बहुत ठीकेदारी लेते हैं । जितना भी बड़ा-बड़ा ठीकेदार है, वहीं के हैं । जंगल इलाका के, दौन के, गवनाहा के, तो उस जंगल में कोई नहीं जाता है । इसलिए इसपर ध्यान दिया जाए कम-से-कम अपने थ्रू दिखवा लिया जाए । पैसा बहत जा रहा है, काम भी हो रहा है । धन्यवाद देती हूं ललन बाबू को कि पूरे बिहार पर उनका नजर है और खुशहाल है, ललन बाबू को धन्यवाद दीजिए कि कोई भी आदमी अपना दु:ख लेकर जाता है तो वे सुनते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए । आज इतना जरूर कहूंगी कि आज महिला दिवस है और हमलोग महिला जब खड़ी हुई थी तो उन्होंने भी साथ दिया ...

सभापति (डॉ0 रंजू गीता): माननीय सदस्या आदरणीया भागीरथी देवी, अब आपका समय समाप्त हुआ ।

टर्न-17/ कृष्ण/08.03.2018

श्रीमती भागीरथी देवी : सभापति महोदया, एक मिनट और बोलने दिया जाय । महिला दिवस के बारे में बोलने दिया जाय । हम माननीय मंत्री जी से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि स्लूईस गेट पर ध्यान दिया जाय और स्लूईस गेट बनवा दिया जाय, अनुसूचित जन जाति का क्षेत्र है, वहां कोई देखनेवाला नहीं है । हम कब तक मांग करते रहेंगे । सदन में हमेशा इस बात को उठाते रहते हैं । इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर गौनाहा और रामनगर में बनवा दिया जाय ।

(व्यवधाान)

हम अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं । आपलोगों के यहां बाढ़ नहीं आई थी तो आपलोग नहीं बोलते हैं । जहां बाढ़ नही आयी, वहां भी पैसा जा रहा है और वहां के लोग पैसा लूट रहे हैं । बहुत पैसा जा रहा है । आपलोग इस पर ध्यान दीजिये ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : अब आप समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य श्री आनन्द शंकर । आपका 10 मिनट समय है ।

श्री आनन्द शंकर : सभापति महोदय, लघु जल संसाधन विभाग की मांग के विरूद्ध प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद आपका । महोदया, मैं औरंगाबाद विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । एक ओर जिल के के कुछ प्रखंड सोन उच्च स्तरीय प्रणाली से सिंचित होते हैं तो दूसरी ओर कुटम्बा, औरंगाबाद, देव, नवीनगर, मदनपुर ऐसे प्रखंड हैं, जहां के किसानों को बहुत ही कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है । किसान भगवान की ओर टकटकी लगाये रहते हैं । वर्षा अगर ठीक हो गयी तो खेती अच्छी होगी नहीं तो उनके पास कोई सिंचाई का साधन नहीं है महोदय, उसमें भी वह आग में घी डालने का काम करती है, जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं । हमारे यहां दो-दो परियोजनायें बहुत वर्षों से लंबित पडी हुई है । उत्तर कोयल परियोजना है और हरियाही परियोजना है, विगत 25-30 वर्षों से लंबित पड़ी हैं । महोदया, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर ये परियोजनायें पूर्ण हो जाय तो हमलोगों की सारी कृषि से संबंधित समस्यायें दूर हो जायेगी ।

महोदया, मैं अभी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वाटर शेड, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रीचार्ज, महोदया, यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं औरंगाबाद विधान सभा क्षेत्र की बात मैं करना चाहूंगा । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो चीजें पेपर पर अंकित की गयी हैं उसमें अगर काम 10 परसेंट भी हो गया हो तो वह बहुत बड़ी बात हळ । अहार-पईन अतिक्रमण हो रहा है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है । आहर-पईन को आप बोल रहे हैं कि उससे रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रीचार्ज कराने में आपको मदद मिलती है । मैक्सिमम जगहों पर आहर-पईन को अतिक्रमण कर लिया गया है । लोग उसको खेत बनाकर चाहे जो भी कारण रहें हों ।

महोदय, अभी गर्मी शुरू नहीं हुआ कि पेयजल का संकट आन पड़ा है । औरंगाबाद हो, देव हो, रफीगंज हो, मदनपुर हो, नवीनगर हो, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और आप रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रीचार्ज की बात करते हैं । सिंचाई की आप बात करते हैं । महोदय, पूरे बिहार की कमोबेश सही स्थिति है । तो किस प्रकार से आप लोगों को सिंचाई की व्यवस्था करा पायेंगे यह मेरे समझ में नहीं आता है ।

महोदया, जल संरक्षण विभाग है, है तो लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत ही आता है, लेकिन जल छाजन की व्यवस्था के लिये, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये जगह-जगह छोटे-छोटे पौंड्स बनाने हैं । मैं चार-पांच बार कम्प्लेन कर चुका हूं, उसके बावजूद पता नहीं क्या है, जांच नहीं हो पायी । केवल कागज पर ही पौंड्स बनाये जा रहे हैं । कहां जल संरक्षण हो रहा है, यह पता नहीं चल पा रहा है । मैंने लिखित आ वेदन भी दिया है । उसके बावजूद आजतक कार्रवाई नहीं हुई ।

महोदया, अभी मैंने देखा, इसमें मेंशन किया हुआ है कि औरंगाबाद में 3466 आवेदन पत्र पड़े हैं और 1015 आवेदन अनुशंसा लिया गया है जनप्रतिनियों से चाहे वे जिस स्तर के प्रतिनिधि हों और 1015 योजनायें ही एप्रुव्ड हुये हैं और 612 में इन्होंने अनरुदान का भुगतान किया है । आखिर क्या कारण है कि जितने जनप्रतिनिधियों ने अनुशंसा किया है, केवल उतने ही संख्या में नलकूपों के विरूद्ध अनुदान दिया या अनुदान भुगतान कराने का काम किया । महोदया, यह भी जांच का विषय है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इसकी जांच की जाय तो तो आधे से अधिक फर्जी निकलेंगे । हमलोग उस क्षेत्र में घुमते हैं, कहीं भी हमलोगों को इस तरह की व्यवस्था नहीं दिखती है और अगर व्यवस्था है तो वह पारदर्शी नहीं है । यह तो छलने का काम हो रहा है । केवल यह आंकड़ों का खेल है जो हमलोगों को दिखाया जा रहा है । नेपवा माईनर है, कपसिया माईनर से 25 आर0डी0 तक जमीन अधिग्रहित किया जा चुका है सरकार के द्वारा लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है । वह ऐसा क्षेत्र है, देव का तलहटी क्षेत्र है, जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और देव के नक्सली इलाके हैं घुचिया हो गये, दुलारे हो गये, इन जगहों पर तालाब के निर्माण हेतु जल संग्रहण हेतु जितनी भी योजनायें हैं, उसमें फर्जी तरीके से निकासी की जा रही है या तो विभाग के पदाधिकारी या संलिप्त पदाधिकारी हैं, उनके किसी नजदीकी रिश्तेदार के द्वारा अप्लाई करवा कर निकासी कर लिया जा रहा है । महोदया, यह जल छाजन का मामला है । नक्सली इलाके में अधिकारी भी नहीं जाते हैं जांच करने के लिये, तो ये समस्यायें हैं तो किस तरीके से लघु जल संसाधन विभाग कहता है कि वह किसानों के हित में काम करता है ।
दधपा में बांध टूटा हुआ है, उसकी मरम्मति के लिये कितनी बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन आजतक उसका जिर्णोद्धार नहीं हो पाया हळ । देवसरप बीघा रजवान से ताला पोखर मिड्लि स्कूल होते हुये कुम्हार बिगहा तक छोटी नाली, मैंडम आप जाईयेगा तो देखियेगाकि कहीं कुछ नहीं है, बस चार-चार इंट रखकर बना दिया गया है और जिस साल बनेगा, उसके दूसरे ही साल आप देखेंगे, सारे इंट टूटे हुये हैं, वहीं पर किनारे पर आस-पास फेंका हुआ है । इस तरीके से वहां काम चल रहा है । अगर जांच करवा लिया जाय तो अधिकतर इसमें भी फर्जीवाड़ा हळ । केवल खानापुर्त्ति का काम किया

जा रहा है । केताकी मैं गया था, सूर्यपूर नक्सली इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है । वहां पर राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था किया जायं । खैरा मिर्जा है, चहका का जिर्णोद्धार करवाना है वहां पर लेकिन अभी तक नहीं हो पाया हळ । केसर नदी की सफाई करानी है, सफाई नही होने के कारण किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है जितना पहुंचना चाहिए । पहरमा में चहका मरम्मति का काम है विभाग को हरेक चहका या चेकडैम मैपिंग करके उसका निर्माण करवाना चाहिए लेकिन कोई मैपिंग नहीं है, हमलोग लिख कर भी देते हैं उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है और अपने दलालों के माध्यम से जो आवेदन उनको मिलता है उस पर कार्रवाई करके पैसे को गटकने का काम करते हैं । खुलेआम बंदरबांट है । इसकी भी जांच करवाया जाय ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य आपका समय समाप्ति की ओर है ।

श्री आनन्द शंकर : चतरा मोड़ से कुसी बरकियाहा तक अतिक्रमण हो गया है । उसको अतिक्रमणमुक्त कराया जाय, किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है । बगईया बड़की नहर है, फॉल बना है, लेकिन फाटक नहीं है । फॉल बन जाय और फाटक ही नहीं रहेगा तो किस तरह किसानों को भला हो पायेगा ?

सभापति (डा0रंजू गीता) : अब आप जल्द समाप्त करें ।

श्री आनन्द शंकर : सभापति महोदया, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं नॉर्थ कोयल परियोजना और हरियाही परियोजना को पूर्ण कराने में मदद करें ताकि औरंगाबाद के लोगों को सालोभर खेती के लिये सिंचाई की व्यवस्था हो पाये । जब वे परियोजनायें पूरी हो जायेगी तो हमलोगों को लघु सिंचाई परियोजना की बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी । सभापति महोदय, इसके लिये मैं आग्रह करना चाहूंगा । धन्यवाद ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य डा0 शमीम अहमद । आपका समय 10 मिनट है ।

डा0 शमीम अहमद: माननीय सभापति महोदय, आज जल संसाधन विभाग का जो बजट आया है, उसके विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

महोदया, आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आपलोगों को, बिहारवासियों को सदन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं । सभापति महोदया, आज जो बजट आया है।

क्रमश :

टर्न-18/सत्येन्द्र/8-3-18

श्री शमीम अहमद(क्रमश:) वर्ष 2017-18 में जो बजट आया है 2959.17 का और 2018-19 में जो बजट आया है 2513.98 करोड़ का, जिसमें 445.19 करोड़ का डिफरेंस है, कमी है । महोदया, सबसे दूर्भाग्य की बात है इस बजट में कटौती लाना, चूंकि बिहार राज्य जो

है यहां के 80 प्रतिशत लोग गांव देहात में रहते हैं और ये सरकार इन गांव के लोगों को उपेक्षित कर रही है, उसके बजट को कटौती कर के उसको दोहरी मार के अलावे तिहरी मार दिया जा रहा है । महोदया, हमलोग जब शुरू में जीतकर आते हैं तो किसी विधायकों से मैंने देखा कि अपने अपने क्षेत्र के समस्या को पहले यहां कलेक्शन कराया जाना चाहिए कि कहां क्या समस्या है, किन विधायकों की क्या समस्या है, उनके क्षेत्र में क्या समस्या है लेकिन इसके बगैर कलेक्शन कराये, उनके क्षेत्र के समस्याओं को जाने रोड मैप बन जाता है और उस पर हमारे पदाधिकारी लग कर के कार्रवाई शुरू कर देते हैं । जो विधायक दिन भर चौबीस घंटे अपने जनता के सेवा में लगा रहता है लेकिन उससे उतना भी जानकारी नहीं लिया जाता कि पहले उनकी समस्या को जाना जाय कि किनके क्षेत्र में क्या समस्या है और जो योजना बनायी जाती है उस पर हमारी सरकार पीठ थपथपाते रहती है । हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो नीचे के पदाधिकारी हैं वे अपनी समस्या लिखकर भेजते भी है लेकिन पटना में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं उसे नजरअंदाज कर देते हैं, उपेक्षित करते हैं । दोनों में जबतक तालमेल नहीं होगा तो यह बिहार का विकास कैसे होगा ? इतने 243 विधायक हर पांच साल पर जीतकर आते हैं इसमें इतने पदाधिकारी लगे हुए हैं लेकिन हमलोग एक बिहार को आजतक विकास के राह पर नहीं ले गये और आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं । महोदया, बाढ़ बिहार के कोई नई बात नहीं है और बिहार में दर्जनों नदी ..

श्री दिनकर राम: आप इतना क्यों हांफ रहे हैं, आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा लीजिये। आप स्वस्थ रहेंगे तो..

श्री शमीम अहमद: आज विकास नहीं हो रहा है इसलिए अंदर से मेरी तड़प है कि बिहार में विकास कैसे हो यह अंदर से मेरा तड़प निकल रहा है चूंकि बिहार में मेन मेन नदी जिसमें गंगा, कोसी, लखनदेई, सिकरहना, महानंदा, गंडक, अघवारा, बंगरी तिलावे और बागमती के अलावे भी कई नदियां है, कोई नदी हर साल बनती है और जो नदी पहले से नदी है उसकी भी हम सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं । बिहार कृषि प्रधान राज्य है, आज बजट कटौती कर के पिछला जो 17-18 में जो बजट है वह पैसा भी खर्च नहीं हुआ, उसमें से भी अभी 21 प्रतिशत पैसा लगभग विभाग में पड़ा हुआ है और वह पैसा कब खर्च होगा और हमारे यहां पिछली बार आई भीषण बाढ़ में लगभग सारी नदियां और नहरें उफान पर थी और सारे नहर जिससे कृषि का कार्य लिया जाता था सभी टूटकर के एक दूसरे में मिल गये हैं लेकिन हमारी सरकार पीठ थपथपा रही है कि विकास का कार्य हो रहा है । जबतक हमलोग नहीं लगेंगे, महोदया, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि विरोधी दल को नजरअंदाज इसलिए किया जाता है कि इनके क्षेत्र में कार्य किया जायेगा तो फिर वे जीतकर आ जायेंगे इसलिए नजरअंदाज किया जाता है तो इस तरह ये बिहार का विकास

नहीं हो सकता है । जबतकसभी को मिलाकर के, इनका सहयोग लेकर के आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो इसका विकास नहीं होगा । मैं अपने क्षेत्र नरकटिया विधान सभा के अन्दर लगभग बूढ़ी गंडक नदी है, बंगरी नदी, तिलावे नदी, परसाहा नदी, टियर नदी इतने लगभग नदी है और घोड़ासहन कैनाल भी है लेकिन पटवन नहीं हो पाता है । किसानों के लिए कृषि के कार्य के लिए कोई नया प्रावधान नहीं है, जबतक कृषि के लिए उस पानी का उपयोग नहीं करेंगे, बाढ़ आया और पानी बहकर चला गया और कृषि समाप्त कर गया लेकिन उस पानी को रोक कर के उससे हम कृषि का कार्य ले सकते थे लेकिन हमारे पास विजन नहीं है कि उसको हम रोक कर के उससे कार्य लिया जाय तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जितने भी नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं, सभी के पास जमीन है लेकिन वे घर नहीं बना पाते हैं चूंकि नदी के कटाव के डर से और जब नदी उफान पर होती है तो वह डर से घर नहीं बनाते हैं कि कभी गांव के बीच से बह न जाये , किनारे से बह न जाये, किनका घर डूब जाय, कटाव में चला जाय, इस डर से लोग घर नहीं बनाते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसको प्राथमिकता में लेकर के पूरे बिहार में जहां नदी के सबसे पहले जो गांव अगल बगल में है, वहां मजबूत बेड वाला तटबंध बनाया जाय ताकि गांव को बचाया जा सके और गांव बचाने के अलावा वह सुरक्षित होकर अपना घर मकान बनाकर रहें और इसके साथ-साथ कृषि का कार्य कैसे हम लें इस पानी को रोक कर के कृषि का कार्य हम कैसे लें, इसके लिए सभी विधायकों से अपने क्षेत्र का जो भी समस्या है इकट्ठा किया जाय । हमारी भागीरथी देवी जी बोल रही थीं उन्हीं के बगल में पूर्वी चम्पारण है जो नेपाल से पानी आती है और पूरे फसल को समाप्त कर के चली जाती है।

सभापति (डॉ0 रंजू गीता) :अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री शमीम अहमद: एक मिनट, यह कोई नयी बात नहीं है एक मेरे क्षेत्र की समस्या है । मैंने चार बेड वर्क के लिए दिया था जिसका टेक्निकल, टी0एस0 मिल गया था 27-2-18 को, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसे वे दिखवा कर करवा दें ।

श्री गिरधारी यादव: माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत जल ससांधन विभाग के मांग के समर्थन में एवं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आप सब लोग जानते ही है कि बिहार का विकास माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है वह हो रहा है, यह बात किसी से छूपा हुआ नहीं है । जल संसाधन विभाग के बारे में माननीय मंत्री ललन सिंह जी जब से आये हैं, आपको जानकर ताज्जूब होगा कि जो जल संसाधन विभाग पहले एक ही विभाग था बाढ़ और सिंचाई दोनों के लिए, दोनों एक साथ था । इन्होंने इस विभाग में आकर के अपनी क्षमता का उपयोग कर के बाढ़ को अलग किया और सिंचाई को अलग किया जो कि सिंचाई विभाग में एक मिल का पत्थर साबित होगा और विकास के

मामले में जो गहन अध्ययन इन्होंने किया है वह हम सभी जानते हैं अच्छी तरीके से । हमारे यहां 1995 में बांका जिला में बाढ़ आयी था, पूरे बिहार में बाढ़ आयी थी, हमारे बांका जिला में 3-4 संरचना सुखनिया बीयर, चंदन बीयर का कैनाल, बधुआ का कैनाल ये सब क्षतिग्रस्त हो गया । वर्ष 1995 से लगातार हम एम0एल0ए0 और एम0पी0 रहे हैं, हमने हमेशा प्रयास किया कि वह किसी तरह से बन जाये लेकिन हम नहीं बनवा सकें । (क्रमशः)

टर्न-19/मधुप/08.03.2018

... क्रमशः ...

श्री गिरिधारी यादव : चाहे वह लोक सभा के द्वारा हो या विधान सभा के द्वारा हो, बराबर प्रयास करते रहे लेकिन नहीं बनवा सके । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो इस मुद्दे को मैंने 2010 से भी उठाने का प्रयास किया । चाहे वह भागलपुर में मीटिंग हो, बॉका में मीटिंग हो, हमने हमेशा प्रयास किया और यह बहुत ही मुख्य मुद्दा हमारे जिला का था । सुखनिया बीयर और डकाई बीयर जो 1995 के बाढ़ में वाश-आउट हो गया था, पूरा सिस्टम बीयर का बर्बाद हो गया था, उस बीयर को माननीय मंत्री के नेतृत्व में, जैसे ही हमलोगों ने इस बात को रखा, उसी समय कहा कि यह बीयर बनेगा, यह बहुत ही जरूरी बीयर है और 57 करोड़ रूपया उस बीयर में देने का काम किया और आज हमको लगता है कि 75 प्रतिशत उस बीयर का काम पूर्ण भी हो चुका है ।

चांदन जलाशय योजना - 1995 के बाढ़ में उसका जो कैनाल सिस्टम था, वह ध्वस्त हो चुका था, वह भी नहीं बनवा सके थे । उसके लिये भी अभी हमलोगों ने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, उसमें भी रूपया देकर उसको बनवाने का काम किया गया । इसके साथ-ही-साथ, जो हमारा बधुआ जलाशय योजना है, जो कि बहुत ही पुराना जलाशय इस राज्य का है, उसका भी जो संरचना था, बहुत ही खराब स्थिति में था, उसमें भी काम लग गया है । सारे काम को देखकर लगता है कि वास्तव में विकास की क्या गति है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, और लोग भी इसको जानते हैं । इसके साथ-साथ, जब माननीय मंत्री जी शिलान्यास करने के लिये बॉका गये तो वहीं उसी जगह हमने आम-सभा में मॉग किया कि बेलहरना जलाशय जो कि बहुत मुख्य है उससे तारापुर विधान सभा क्षेत्र, बेलहर और बॉका जिले का जो पटवन होगा उसको करवा दीजिये । वहॉ से वे तत्काल बोले कि ठीक है, आम-सभा में बोला कि गिरिधारी जी, कल सैंक्शन हो जायेगा । दूसरे दिन हेलिकॉप्टर से बॉका से आये और कैबिनेट में 31 करोड़ रूपया उसी दिन उसमें सैंक्शन करने का काम किया और कहा कि जल्द से जल्द यह संरचना पूरी होनी चाहिये और दो साल का टाइम भी फिक्स कर

दिया । यह विकास की गति है । यह विकास की विचारधारा है । सिर्फ ऐसे ही बात करने से नहीं होता है ।

इसके साथ ही साथ, हम बता रहे हैं, हमलोगों ने एक विलासी डैम बनवा दिया, विलासी डैम बनने के बाद नीचे के जितने भी गॉव थे उसका जो नदी के द्वारा जो पटवन होता था वह बंद हो गया । लोगों ने इनको कहा कि हमारा जो विलासी नदी से पटवन होता था, विलासी डैम बनने के कारण हमारा वह पटवन बंद हो चुका है। इतना अध्ययन किया गया, सारे लोगों को कहा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, बोला कि ट्यूबवेल लगाकर होगा और 5 ट्यूबवेल अम्बा गॉव में सैंक्शन करवाने का काम किया है । यह है विकास की गति ।

बाढ़ के क्षेत्र में इस बार जो काम हुआ है, इस साल बहुत ज्यादा वारिश हुआ हमारे राज्य में लेकिन क्षति आप देखियेगा तो अन्य वर्षों की तुलना में कम क्षति है। यह उपलब्धि है । बराबर काम करते रहते हैं, सबलोग लगे रहते हैं । एक और मुख्य जो बिहार की बड़ी योजना है - बरनार जलाशय योजना, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें फौरेस्ट के क्लीयरेंस की जरूरत नहीं थी, लम्बे दिनों से यह योजना चल रही थी और उसमें कफर डैम भी बन गया था । लेकिन ऐसा कानून उसमें लगाया गया कि उसको बंद करा दिया गया और आज तक बरनार जलाशय योजना, जो बिहार की बहुत बड़ी योजना है, वह यों ही पड़ी रह गई ।

बहुत सारी बातें हैं, कितना बताया जाय विकास के मामले में, लेकिन साथ ही साथ, दुर्भाग्यपूर्ण बात बिहार के लिये है कि बिहार में जो बाढ़ आती है, वह बिहार का बाढ़ नहीं है, वह नेपाल का बाढ़ है । इस राज्य की जो विपदा है वह किसी से छिपी हुई नहीं है लेकिन विपदा के साथ-साथ इस राज्य में राजनीतिक मतभिन्नता इतनी है कि लोग एक जगह बैठ नहीं पाते हैं । हम एम0पी0 भी रहे हैं, दूसरे राज्यों के एम0पी0 यदि कोई काम होता है तो सारे दल के भेद को भूलकर एक साथ किसी मंत्री के यहॉ चले जाते हैं । हमलोग बराबर प्रयास करते हैं कि जो बिहार के एम0पी0 हैं, दल का भेद भूलकर एक साथ जाकर किसी मंत्री के यहॉ बैठें और काम करायें । लेकिन एक ऐसा नियम बनाया हुआ है भारत सरकार के द्वारा, चाहे जिसकी भी सरकारें रही हों, उसमें है कि प्राकृतिक सम्पदा का मालिक भारत सरकार होगा और प्राकृतिक विपदा का मालिक बिहार सरकार, राज्य सरकार होगी और प्राकृतिक विपदा दूसरे देशों से आ रही है, यह हमारे देश की भी विपदा नहीं है । इसीलिये हम सारे सदन से चाहेंगे कि हमलोग एकजुट होकर चाहेंगे कि जिस प्रकार प्राकृतिक सम्पदा का मालिक भारत सरकार है, उसी प्रकार प्राकृतिक विपदा का भी मालिक भारत सरकार हो और जितनी प्राकृतिक विपदा के माध्यम से क्षति हो राज्य का, उसकी भरपाई भारत सरकार करे ।

महोदय, गंगा का जो मुद्दा है, गंगा में जो गाद भर गया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमारा फरक्का बराज बना है यह बिहार के लिये अहितकर है, बिहार के लिये हानिकारक है । जबतक फरक्का बराज के विषय में चर्चा नहीं किया जायेगा तबतक हमारे राज्य के बाढ़ की जो समस्या है, उसमें सुधार नहीं हो सकता है । आप सभी जानते हैं कि जब फरक्का बराज बना था, उसमें इंजीनियरों ने कहा भी था कि यह गलत बन रहा है लेकिन उसको पागल घोषित कर दिया, बोला कि यह क्या बोल रहा है । दूसरे देश को पानी देने के लिये हमलोग अपने राज्य का नुकसान कर रहे हैं । बिहार कहाँ जायेगा ? बिहार की तरक्की के लिये जो दल की बात है, यह तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष होगा ही, कभी इसकी सरकार रहेगी, कभी उसकी सरकार रहेगी लेकिन बिहार के विकास के लिये हमलोगों को इसमें दलगत भावना से उपर उठकर एक होकर सोचना चाहिये, एक होकर प्रयास करना चाहिये । जबतक हमलोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, हम छींटाकशी करते रहेंगे, आप छींटाकशी करते रहेंगे तबतक इस राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है । हो सकता है कि कुछ काम आज अच्छी तरह हो जाय, कुछ काम खराब हो जाय लेकिन बिहार के सर्वांगीण विकास के लिये, चाहे वह गंगा नदी का मुद्दा हो, चाहे वह कोसी का मुद्दा हो, चाहे गंडक का मुद्दा हो । आज क्या स्थिति है ? हम अध्ययन कर रहे थे एक बार, नेपाल सरकार से एक एग्रीमेंट होना था बिजली के संबंध में कि कोसी पर नेपाल में एक बराज बनेगा, कांग्रेस की सरकार थी, सारे लोग लगे हुये थे और उसका हमने अध्ययन किया, उसमें हुआ कि भुगतान कैसे होगा, डॉलर में होगा कि रूपया में होगा, इसी में वह बराज नहीं बना और आज क्या स्थिति है ? यदि वह बन गया रहता तो बिजली का भी उत्पादन होता और हमारा जो राज्य बाढ़ से क्षतिग्रस्त होता रहता है, वह भी बच जाता है । इसलिये सबको इन चीजों में लगना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर लगना पड़ेगा ।

बिहार के साथ हमेशा अन्याय हुआ है, आप जानकर ताज्जुब करियेगा कि एक नियम लाया गया माल भाड़ा समानीकरण नीति, कोयला जिस रेट में धनबाद में मिलेगा, उसी रेट में चेन्नई में मिलेगा, उसी रेट में चंडीगढ़ में मिलेगा । सारा हमलोगों का प्राकृतिक सम्पदा उठाकर वहाँ ले गया और हम गरीब के गरीब राज्य ही रह गये, पिछड़ा के पिछड़ा राज्य ही रह गये । इसलिये सबको लगना पड़ेगा, सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा । माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री ललन सिंह जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, वह वास्तव में सराहनीय कार्य है । सिंचाई के क्षेत्र में जो वर्षों से पेंडिंग योजनाएँ थीं, उसपर काम नहीं हो पा रहा था, उसपर आज काम मजबूती से हो रहा है, विकास का काम हो रहा है और मोनिटरिंग की भी व्यवस्था की जा रही है । कहा कि पटना से भी बैठकर सारी चीजों का मोनिटरिंग करेंगे, कोई गलत

काम नहीं करेगा । इसके पहले की सरकारों में आप देखते थे कि हर साल मार्च में सरेन्डर होता था, मार्च में लूट होता था, मार्च में क्या नहीं होता था । आज क्या स्थिति है ? पूरा पैसा जल संसाधन विभाग का खर्च हो जाता है, बचता ही नहीं है, सरेन्डर ही नहीं होता है । यह उपलब्धि है ।

तटबंध के मामले में, बहुत सारे लम्बे तटबंध सरकार बनाने का प्रयास कर रही है और हमको भी खुशी है कि जो हमारा चांदन जलाशय, बधुआ जलाशय बाढ़ में था, उसमें भी सारे तटबंध बन गये । सारा काम जो विकास का हो रहा है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है । इस काम में सरकार लगी हुई है, हम चाहते हैं कि विपक्ष के लोग भी इसमें मदद करें, हम सब मिलकर काम करें । बिहार के विकास की जो स्थिति है, उसको हमलोग आगे ले जायं ।

अभी जो एक समस्या है, जो बालू का उत्खनन हो रहा है हमारे जिले में या और भी जिलों में हो रहा है, बालू के उत्खनन होने से जो नदी का तल है वह नीचे चला जा रहा है, मंत्री महोदय । उससे क्या हो रहा है कि स्वाभाविक रूप से जो प्राकृतिक कैनाल थे जिससे लोग नदी बॉधकर पानी अपने खेत में ले जाते थे, अब वह नहीं हो पा रहा है । इसलिये आप कितना भी सिंचाई का इंतजाम कर रहे हैं लेकिन जो प्राकृतिक हमारे सिंचाई के स्त्रोत थे, वे नदी में बालू के उत्खनन होने से नीचे जा रहा है। आपने बहुत काम किया है, हम चाहेंगे कि आप इस ओर भी गहन अध्ययन करिये, पूरे राज्य का मामला है कि जहॉ-जहॉ यह बात हो रही है, कैसे उस पानी को हम कोई चेक-डैम बनाकर रोकें । जो पुराने कैनाल हैं, उसमें हम पानी को डालने का काम करें, उससे क्या होगा कि जो सिंचाई की क्षमता है, और ज्यादा वृद्धि होगी । सिंचाई की क्षमता के मामले में जो वृद्धि है, उससे किसानों की भी स्थिति सुधरेगी, हमारी खुशहाली आयेगी । हमारे राज्य में सिंचाई मुख्य साधन है, दूसरे राज्यों में आप जाकर देखियेगा कि पानी ही नहीं है । हमारे पास पानी की प्रचुर मात्रा है इसके बावजूद हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । जबतक पानी की पानी की प्रचुर मात्रा का हमलोग दोहन नहीं करेंगे तबतक और विकास नहीं होगा । आप लगे हुये हैं इस काम में और हमलोग चाहते हैं कि आपकी जो सोच है, आपकी जो दिशा है, सरकार की जो दिशा है उसमें हमलोग दिन-रात काम करते रहें ।

अगले पॉच वर्षों में विभाग के द्वारा 1646 कि0मी0 अतिरिक्त तटबंध के निर्माण का लक्ष्य है जिससे 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से निजात मिलेगी और किसानों को सुविधा होगी । सरकार लगी हुई है । 2016-17 के दौरान खरीफ में 19.31 लाख हेक्टेयर, रब्बी में 7.14 लाख हेक्टेयर एवं गरमा में 27 हजार हेक्टेयर, कुल 26.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो अबतक का रेकॉर्ड है । 3790 कि0मी0 लम्बे तटबंध का निर्माण कर 29.94 लाख

हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया गया है । 2018 के पूर्व 417 बाढ़ सुरक्षा तटबंध योजनाओं के क्रियान्वयन का लक्ष्य है ।

सरकार वास्तव में बहुत सारे काम कर रही है और हम चाहते हैं, एक बात और, मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूॅगा कि हमलोगों के यहॉ जो जलाशय है, उसमें जो मछली का डाक होता है, इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है । जितने मछली के ठीकेदार हैं वे ज्यादा कुछ राजस्व आपको देते नहीं हैं, वे मछली मारने के लिये पानी खोल देते हैं जिसके कारण लोगों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती है । आप जानते हैं कि डैम जंगलों में बना हुआ है, वहॉ तो कोई आपका आदमी या इंजीनियर जा नहीं सकता है । इसीलिये हम चाहते हैं कि जो मछली का डाक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा राजस्व है नहीं, उसको यदि आप समाप्त कर दीजियेगा।

...क्रमशः....

टर्न-20/आजाद/08.03.2018

.... क्रमशः ......

श्री गिरिधारी यादव : निश्चित तौर पर जो मछली के ठीकेदार हैं, रात में जाकर जो बड़े-बड़े डैम बने हुए हैं, उसको खोल देते हैं और पानी सुखाकर मछली मार लेते हैं और इससे हमारा जो सिंचाई का क्षमता है, वह घट जाता है । इसको आप यदि अध्ययन कराईयेगा तो निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा, हमलोग बराबर क्षेत्रों में रहते हैं, यह समस्या बराबर आ रही है । जो डैम बने हुए हैं, वे शहर में तो है नहीं, वो गांव में है, वहां कौन जा सकता है, जो मछली के ठीकेदार हैं, उसकी स्थिति बहुत खराब है । मछली मारने के लिए डैम का पानी बहा देते हैं, जिससे पटवन बाधित होता है । आपने जो काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय कार्य है । हम चाहते हैं और भी जो कुछ कार्य हैं हमारे इलाके में, जैसे बरनार जलाशय योजना, एक इतनी बड़ी परियोजना इस राज्य की है, जो फोरेस्ट के क्लीयरेंस के लिए पड़ा हुआ है, जमीन उपलब्ध हो गया है । हम माननीय मंत्री महोदय और माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करेंगे, हम सारे लोगों से अनुरोध करेंगे कि बरनार जलाशय इस राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सन् 1976 से लंबित है और आज तक नहीं बन पाया है । यदि यह बन जायेगा तो जमुई का जो इलाका है, जो नक्सल का इलाका है, वहां यदि सिंचाई होगी तो निश्चित तौर पर लोगों की भलाई होगी । उलाई वियर है, छड़छड़िया है, शारदा है, ये बहुत सारी योजनायें हैं, जो कि जमुई जिला में बनना जरूरी है और इससे लोगों का बहुत विकास होगा । साथ ही साथ जो बांका जिला में है, आपने सारा काम कर दिया है, हमारा जो एक कानीमुह वियर है ......

सभापति(डॉ0 रंजूगीता) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो चला ।

श्री गिरिधारी यादव : महोदया, दो मिनट में खतम करते हैं मैडम । हमारा बॉका जिला में है, आपने सारा काम कर दिया, एक हमारा कानीमुह वियर है और चान्दन जलाशय का उड़ाही है, हमारे यहां दो मुख्य काम है, अभी तक लंबित है, हम चाहते हैं कि यह काम हो । हमारे झाझा विधान सभा क्षेत्र में जहां के हम कभी एम0पी0 भी रहे हैं, नकटी और नागी, ये दोनों सिंचाई परियोजना है, यह काफी उपयोगी परियोजना है, हम चाहेंगे कि इसका पुर्नस्थापन करने की कृपा की जाय । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद और मैं सरकार के बजट का समर्थन करता हूँ ।

सभापति(डॉ0 रंजूगीता) : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, आपका समय 15 मिनट ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदया, आज जल संसाधन विभाग के बजट पर विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज महिला दिवस है, सर्वप्रथम मैं राज्य, देश और दुनिया के मातृशक्ति को अपनी ओर से और अपने कल्याणपुर की महान जनता की ओर से सादर नमस्कार और प्रणाम करता हूँ और मैं बधाई देता हूँ कि सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को जिन्होंने इस सदन में भी मातृशक्ति को आज सदन का जो सर्वोच्च स्थान है, उसपर बैठाने का काम किया है । मैं पुन: एक बार अपनी ओर से और अपनी कल्याणपुर की महान जनता की ओर से बधाई देता हूँ ।

सभापति(डॉ0 रंजूगीता) : आपको भी धन्यवाद ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदया, जल संसाधन विभाग का क्षेत्र काफी विस्तृत है, इसमें जल प्रबंधन और जल संरक्षण दो बड़े काम हैं और जहां तक मेरी जानकारी है 4.6 खरब वर्ष पुराना हमारा यह पृथ्वी है और 4.6 अरब वर्ष पुराना समुद्र का इतिहास है । पृथ्वी पर जितने जल हैं, उसका 97.33 प्रतिशत सिर्फ समुद्र का जल है । हम सब जानते हैं कि हम समुद्र के जल को न सिंचाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं, न उस जल को पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं और बाकी मात्र जो 3 प्रतिशत से भी कम जल है, उसी जल में हमको सिंचाई का स्रोत भी बनाना है और हमको पीने का पानी की भी व्यवस्था करनी है । इसलिए जल ही जीवन है, जल सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, सबसे बड़ा तत्व है जीवन के लिए, चाहे वह पीने के रूप में हो, चाहे सिंचाई के रूप में हो, जल सबसे आवश्यक अवयव है और उसपर आज सदन में बहस हो रहा है । मैं बधाई देता हूँ आदरणीय इस सरकार के मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, जिनके नेतृत्व में बिहार में भी जल संरक्षण और जल प्रबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है । महोदय, जल की आवश्यकता सिंचाई के लिए भी है, पीने के लिए भी है । अपने राज्य में खासकर बिहार राज्य में कई ऐसे परियोजनायें जो शुरूआती दौर में शुरू हुआ था, जब देश आजाद हुआ था, उस समय शुरू हुआ था । 1952 से शुरू हुआ था और सत्ता के गलत

नीतियों के चलते आज भी चाहे कोशी का हो, कमला का हो, जो नहरें बनाने का काम था, यह पेंडिंग पड़ा हुआ था । मैं बधाई देता हूँ इस सरकार के समय में कि इन योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है । हम सब जानते हैं कि हमारा यह बिहार विभिन्न प्रकार की त्रासदियां झेलता रहता है । बिहार की जो जमीन है, यह कभी बाढ़ का दंश झेलता है, एक तरफ सुखाड़ का दंश झेलता है और बाढ़ के कारण बिहार में ऊपज कम होती है, ज्यादे हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्यों के नदियों के चलते हमें बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है । एक समय था, बिहार के नेता जब बिहार में बाढ़ आता था और बिहार के प्रेस वाले पूछते थे कि आपके बिहार में काफी पानी आ गया है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है तो हमारे उस समय के तत्कालीन नेता कहते थे कि इतना पानी बिहार का तो हमारा पाड़ा पी जायेगा और आज वही बिहार है, जिस बिहार में जल प्रबंधन और जल संरक्षण बेहतर तरीके से होता है । एक समय था, जब इसी सदन के नेता जब बाढ़ आता था, उस समय कहते थे कि जब प्रेस वाले भाई पूछते थे कि बिहार में भयंकर बाढ़ है, लोग भूखे मर रहे हैं तो सदन के नेता कहते थे कि पानी आ गया है, जो गरीब लोग है, भूखे मर रहे हैं, मछली पकड़-पकड़ कर खायेंगे । यही आज जब बाढ़ आया है, अभी इसी वर्ष जब बाढ़ आया था तो इस सदन के नेता और देश के नेता बिहार में आये थे, बाढ़ का दौरा किये थे और प्रधानमंत्री ने जनधन के खाते में हर गरीब के घर में 6-6 हजार रू0 पोस्टिंग हो गया था । कुछ मजबूरियां, कुछ परिस्थितियां हम नेताओं के द्वारा कुछ उपज ऐसा कृत्य कि हमलोग कुछ लोगों को लाईन में लगा देते हैं, यदि 10 आदमी को राहत मिलना है तो उसमें 3 आदमी का नाम और जोड़वा देते हैं और ब्लॉक और अंचल पर धरना दिलवाते हैं, हल्ला-गुल्ला करवाते रहते हैं, जिससे कि हमारा नेतागिरी चले । जितने भी लोगों के घरों में बिहार में बाढ़ का पानी आया था, जिनके भी चुल्हा-चौके बन्द थे, उनके खाते में 6-6 हजार रू0 चला गया, ललन बाबू को मैं पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूँ । इसी बिहार में जब इस बार बाढ़ आया था तो सामुदायिक किचेन बनाकर के एक आदमी को भी भूखे नहीं रहने दिया गया था और भारत की सरकार भी उस समय सहयोग कर रही थी, एन0डी0आर0एफ0 की टीम तक पहुँचाकर बिहार में बाढ़ प्रबंधन का और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को कुशलतापूर्वक निकाल रही थी । हमारा जिला चम्पारण भी और पूरा चम्पारण भी बाढ़ का त्रासदी झेल रहा था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ बिहार सरकार को कि एक तटबंध नहीं टूटा मेरे चम्पारण जिला में, यह बड़ा क्षेत्र है, बड़ा भू-भाग जल-जमाव और जल से ग्रसित था लेकिन एक तटबंध नहीं टूटा, एक नहर नहीं टूटा और आज भी हम नहरों से सिंचाई का फायदा उठा रहे हैं । निश्चित रूप से नहरें हमको सिंचाई के रूप में अन्न उत्पादन के लिए सहयोग करते हुए हमको जीवन प्रदान कर रही है । मैं यह नहीं मानता महोदया कि हमारे बिहार में जल का पूरा प्रबंधन हो गया, पूरा संरक्षण हो गया, उसका पूरा

संवर्द्धन हो गया, हमारा बिहार बाढ़ के मामले में, सिंचाई के मामले में पूर्ण हो गया, लेकिन मैं यह मानता हूँ, यह जरूर महसूस कर रहा हूँ कि आज बाढ़ के लिए बिहार में जिस प्रकार से बाढ़ के प्रबंधन के लिए सरकार ने कुशलता दिखलाया है, हमारे मंत्री जी का जो प्रबंधन है, वह बेहतर तरीके से बढ़ रहा है, आगे आने वाला समय होगा, निश्चित रूप से बाढ़ से बिहार मुक्त होगा और बिहार में जो सिंचाई के स्रोत हैं, वह भी आगे बढ़ेंगे । लगभग महोदया, 60हजार हेक्टेयर में बिहार में सिंचाई के सोर्सेस डेवलप करना है, 29हजार हेक्टयर से ज्यादा, 30हजार हेक्टेयर के लगभग में आज हम सिंचाई के सुविधा को प्राप्त किये हैं । नहरों के माध्यम से, आहर के माध्यम से, वियर के माध्यम से, नदी के माध्यम से अन्य कई प्रकार के सिंचाई के श्रोतों के माध्यम से हम सिंचाई के सुविधा प्राप्त कर रहे हैं और नहरों को भी आपको बतौर उदाहरण बताना चाहता हूँ कि पूर्वी तिरहुत नहर है, आज जो 790 आर0डी0 तक बना हुआ था, आज उसको बढ़ाकर 925 आर0डी0 किया जा रहा है । मुजफ्फरपुर के भाई जानते होंगे कि आज तिरहुत पूर्वी नहर को आगे बढ़ाया जा रहा है । महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे लखनदेई नदी हो, आपका रातूर नदी हो, इसपर अभी माननीय सदन के नेता नीतीश कुमार जी ने यहां जाकर शिलान्यास किया था बाढ़ प्रबंधन के लिए और यह बिहार के बाढ़ प्रबंधन के रूप में निश्चित रूप से पूरे देश का एक मॉडल साबित होगा ।

महोदया, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम विपक्ष के साथी हैं, विपक्ष के साथी आज कटौती प्रस्ताव लाये हैं कि 10रू0 और कम कर दिया जाय । भाई क्यों कम कर दिया जाय, ठीक है अगर बजट कम आया है, हम सब लोग चाहते हैं कि जो बजट आया है, खर्च हो, बजट बढ़े भी, लेकिन इसमें कटौती प्रस्ताव की क्या जरूरत है महोदया, इसमें तो और अधिक राशि की जरूरत है ताकि हमारा कुशल प्रबंधन, कुशल बेहतर प्रबंधन करके हमारा बिहार इस मामले में आगे बढ़ता जाय ।

..... क्रमशः .....

टर्न-21/अंजनी/दि0 08.03.2018

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : क्रमशः.... आदरणीय ललन बाबू के नेतृत्व में कई प्रकार के ऐसे काम हो रहे हैं बिहार में जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जायेगा । विभाग के पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कुछ खास विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । जो भूगर्भीय जल है, वह धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। जो आजादी के समय में प्रति व्यक्ति जल का औसत छः हजार लिटर था, आज लगभग साढ़े पन्द्रह सौ लिटर बच गया है । लेकिन आज कुप्रबंधन के चलते लोगों को परेशानियां हो रही है, जैसे अपने यहां यूकिलिप्टस का पेड़ लगता है, आज वह पेड़ लगभग प्रतिदिन 500 लिटर पानी सोखता है । ऐसे विषयों पर भी पदाधिकारी और जो टेकनिकल लोग हैं, उनको

ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जो जल स्त्रोत है, जल की जो आवश्यकता है, वह समय से पहले समाप्त न हो जाय। महोदया, मैं इस विभाग के अलावे आदरणीय ललन बाबू योजना एवं विकास विभाग का भी काम देखते हैं । आदरणीय ललन बाबू, आप उदार दिल के मंत्री हैं और आपके बारे में सब लोग जानते हैं कि आपकी जो इच्छाशक्ति है, वह दृढ़ है, आप बेहतर काम करते हैं । मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुए थे और कई योजनाओं के विषय में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप इसको योजना एवं विकास विभाग को जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, उससे आप कराइए । यथा- कब्रिस्तान की घेराबंदी, मंदिर का चाहरदिवारी, श्मशान की घेराबंदी, जो छोटे-बड़े बाजार हैं, जो शहरों के चौक-चौराहे हैं, वहां सी0सी0टी0वी0 लगाइए । महोदय, इन सारे कामों को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से जोड़ा जा रहा है । मैं आपसे निवेदन करूँगा और सदन के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना को बढ़ाकर कम-से-कम पांच करोड़ रूपया करिए और यह जो काम है, उसको भी कराइए । महोदय, दूसरा मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे काम जब हमलोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको पूरा करने के लिए कोई राशि नहीं दिखायी पड़ती है । हमारा 50 लाख का, 1 करोड़ का पुल बनकर तैयार है लेकिन पुल का एक छोटा-सा रेलिंग टूटा हुआ है, जिसपर लाख-दो लाख रूपये से खर्च होना है, उसको हम राशि के अभाव में ठीक नहीं करा पाते हैं और वह पुल उसी से ध्वस्त दिखायी पड़ता है । हमारा पुस्तकालय, हमारा बड़ा-बड़ा सामुदायिक शौचालय, हमारा बड़ा-बड़ा विवाह गृह जो बना हुआ है, विद्यालय जो बना हुआ है जिस पर लाख -दो लाख-तीन लाख-चार लाख रूपये खर्च होना है लेकिन वह भी राशि कहीं से खर्च नहीं कर पाते हैं और आज के दिन में बिहार में ऐसी कोई योजना नहीं है, जिन योजनाओं से हम लाख, दो लाख, पांच लाख की राशि ऐसे कामों में, कहीं प्लास्टर कराना है, कहीं कोई बीम ढालना है, कहीं कोई स्लैब का निर्माण कराना है, कहीं कोई दीवार खड़ी करनी हो तो उसको हम खड़ा कर सकें, आप योजना एवं विकास विभाग के मंत्री हैं, मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करूँगा कि ऐसे कामों के लिए भी आप योजना एवं विकास विभाग में प्रोवीजन कीजिए और यदि संभव हो तो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में प्रोवीजन कीजिए ताकि जो बड़ी राशि, जो बड़ा पुल बनकर तैयार है, 25-50 हजार रूपया, लाख-दो लाख रूपया के चलते पूरा आप नया पुल बनाते हैं लेकिन उसका आप रेलिंग नहीं खड़ा कर पाते हैं, एक ब्लिडिंग बना देते हैं लेकिन प्लस्टर के अभव में कोई ब्लिडिंग गिर रहा है, उसको आप ठीक नहीं करा पाते हैं, जंगला-चौखट उखड़ जाता है, उसमें 10-25 हजार रूपया खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते पूरा ब्लिडिंग बनाने की बात आती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि चूंकि लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री नहीं है और आप लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री के बदले में बैठे हुए है । महोदय, बिहार

में सिंचाई का एक बहुत बड़ा श्रोत लघु जल संसाधन विभाग है और इसके अंतर्गत बहुत ऐसे टयूबवेल हैं जो बनकर तैयार हैं, न तो बिजली का प्रोबलम है और न नाला का प्रोबलम है, न मशीनें खराब है लेकिन वहां कोई ऑपरेटर नहीं है, जिसके चलते वह नलकूप नहीं चल रहा है । दो साल पहले विभाग ने एक निर्णय लिया कि कृषकों की एक समिति बनायी जायेगी, वही उसमें पैसा खर्च करेगी, उस पैसे की वसूली करेगी जो सिंचाई होगा, पटवन होगा । उस पटवन की राशि भी वही लेंगे और वही उसको ठीक करायेंगे । लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इसमें विकास की आवश्यकता है, इसमें सुधार और सुझाव की आवश्यकता है । सुधार की आवश्यकता है कि कृषकों की टीम ऐक्टिभिटी मुझको लगता है पूरे बिहार में किसी भी नलकूप को ऑपरेट नहीं कर पायी, जिसके चलते हमारा बना बनाया नलकूप जिसमें बिजली भी है, नाला भी है, जिसकी मशीन भी ठीक है लेकिन वह नलकूप नहीं चल रही है । सरकारी स्तर पर इसकी कोई-न-कोई व्यवस्था होनी चाहिए या स्पष्ट रूप से किसी न किसी को ...

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : दो मिनट महोदया । इसमें स्पष्ट रूप से कोई नीति बनानी चाहिए । मैं आदरणीय लालू बाबू से पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि हमारे यहां तिरहुत मुख्य नहर है, जिसके सेवा पथ को पक्कीकरण करने की जरूरत है और उसमें जगह-जगह, कई जगह सिंचाई सुविधा के ीलिए आउटलेट बनाने की आवश्यकता है । तिरहुत मुख्य नहर के 537 आर0डी0 पर एक पुल निर्माण हो रहा है, जो अधूरा है, मैं पुन+ आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उस पुल का निर्माण करा दीजिए । उसी नहर से महिषी वितरणी निकलती है, जिसमें लाईनिंग कार्य की आवश्यकता है । पुनः मैं एक बार आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपके यहां स्थापना में काम करने वाली कर्मचारियों की संख्या कम है, न आपके यहां मेठ है, न आपके यहां राजस्व वसूली करने का कोई कर्मचारी है, जिसके चलते सरकार को और आपके विभाग को राजस्व की हानि हो रही है, आप ऐसे स्थापना के कर्मचारी और पदाधिकारी की संख्या बढ़ाकर विभाग को मजबूत कीजिए। पुनः एक बार मैं अपनी ओर से, अपने कल्याणपुर की महान जनता की ओर से आपको साधुवाद देते हुए माननीय महोदया ने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए सारे सदन को नमस्कार एवं प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद समय का ख्याल रखने के लिए। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, आपका समय दो मिनट है ।

श्री सुदामा प्रसाद : सभापति महोदया, आपका आभार प्रकट करते हुए कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । बिहार के आठ जिलों की लाइफ लाईन सोन नहर कही जाती है लेकिन आज वह जर्जर अवस्था में है । 1973 में जो वाणसागर समझौता हुआ था, मुझे

लगता है कि फिर से उस समझौते की समीक्षा की जरूरत है । उस समय तीनों राज्यों मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आज इन जगहों पर भाजपा की सरकार है तो मैं समझता हूँ कि जो पानी कम मिल रहा है, 1973 में जो बिहार के लिए पानी तय था वह पानी सोन नदी में जल की उपलब्धता को कम बताकर कम दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसकी पुनर्समीक्षा की जरूरत है, बिहार इसके लिए प्रयास करे और सोन नहरों के जो किनारे ढह गये हैं, सिल्ड से भरी हुई है नहरें, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए हमारा आग्रह है जल संसाधन मंत्री जी से कि बरसात के ठीक पहले काम नहीं लगाया जाय नहरों के किनारे को ठीक करने के लिए । नहरों की खुदाई के लिए, इसके लिए कुछ समय लेकर काम शुरू किया जाय ताकि नहरों के निचले छोर तक पानी पहुंचाया जा सके । एक और आग्रह करना चाहेंगे कि रोहतास जिले में मुंजी है और तरारी विधान सभा में सारा है, मुंजी तक नहर है, मुंजी से लेकर सारा तक सरफौरा तक आठ किलोमीटर तक नहर अगर बन जाय तो हजारों एकड़ जमीन का पटवन होगा। जमीन भी उपलब्ध है, जमीन अधिग्रहित नहीं करना होगा । तीसरी बात यह कि लघु सिंचाई के बारे में हमने पढ़ा कि लघु सिंचाई विभाग ने 50 करोड़ रूपया 430 नलकूपों की मरम्मती के लिए दिया है, यानी एक नलकूप की मरम्मती के लिए 11 लाख 62 हजार 791 रूपया तो एक नलकूप कितने का आता है और उसकी मरम्मती के लिए 11 लाख 62 हजार 791 रूपया, मुझे लगता है कि विभाग को इसकी पुनर्समीक्षा करनी चाहिए । बिहार में कितने सरकारी नलकूप हैं, कितने बंद हैं, यह भेग में मामला है । हमारे जिले में 524 नलकूप हैं, जिसमें से सरकार कह रही है कि 194 चालू है और हमलोग कह रहे हैं कि 25 चालू है और हर बार उन्हीं नलकूपों को दिखाया जाता है जो बंद पड़ हुए हैं, उसकी मरम्मती के लिए पैसे का आवंटन होता है, मुझे लगता है कि इसको ठीक करने की जरूरत है और अगर यह ठीक नहीं होगा तो इसमें भारी घपला हो रहा है । तीसरी बात यह कि जो बाढ़ से फसलों की क्षति होती है, पिछले साल हमारे जिले में शाहपुर, बड़हरा और बिहिया में भयानक बाढ़ आयी...

सभापति(डा0 रंजू गीता) : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सुदामा प्रसाद : एक मिनट, महोदया । हजारों एकड़ के फसल की क्षति हुई लेकिन जिन किसानों ने बटाई पर, हमारे यहां खेती बटाईदारी पर 80 परसेंट होती है, बटाईदार किसानों को इसलिए फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला कि उनके पास खेती करने का कोई प्रमाण नहीं है ।

...क्रमश:...

टर्न-22/शंभु/08.03.18

श्री सुदामा प्रसाद : क्रमशः.....जो भूधारी थे या जो माफिया हैं, वही लोग इसका लाभ उठाते हैं। इसलिए हमारा आग्रह होगा कि विभाग जो है, बटाईदार किसानों के फसल क्षति मुआवजा के लिए उनको पहचान पत्र की व्यवस्था करे । एक घपला का मामला आया है शाहपुर प्रखंड का पंचायत है हरिहरपुर और बैसवन - जहां पर 801 किसानों ने आवेदन दिया बाढ़ क्षति फसल मुआवजा के लिए, लेकिन उनका आवेदन यूँ ही पड़ा रहा और उनके नाम पर पैसा निकल गया । कृषि सलाहकार हैं उमाशंकर प्रसाद उनपर दबाव बनाया गया कि आप साइन कीजिए लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया ।

सभापति(डॉ0 रंजु गीता) : माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश प्रारंभ करें । आपका समय 10 मिनट है ।

श्री विजय प्रकाश : महोदया, सदन में आज सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज यह बताना चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के पूर्व में जो बजट लाया गया था, हमलोगों के महागठबंधन की सरकार में उससे लगभग 446 करोड़ रूपया इस साल बजट में कटौती हुआ है । क्या कारण है कि हमारे बड़े भाई ललन जी के साथ यह अन्याय और दुर्दशा वित्तमंत्री जी ने करने का काम किया है, क्या कारण है ? क्या कारण है कि इनके विकास करने का जो पूरे बिहार में चर्चा है कि विकास करने वाले मंत्री हैं, शासन करनेवाले मंत्री हैं, ऐसे मंत्रियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के माध्यम से यानी इनको घेरे में रखा गया है कि ये विकास योग्य मंत्री नहीं है । इसलिए इनके विभाग से वित्तीय कटौती किया जाय । यह तो इसका दुरूपयोग करने में वह कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हमें याद है कि जब माननीय मंत्री जी बोला करते थे कि बाढ़ में चूहा पानी और बांध छेद कर दिया है । तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि चूहा कैसे खाया, कौन सा चूहा खाया, कौन पिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के बातों पर विचार किये नीतीश कुमार जी और वित्त मंत्री जी कि नहीं नहीं, वह सही बात है इसलिए इनके बातों का आदर करते हुए यह कटौती करना चाहिए और आज यह सत्य साबित हुआ कि आज वित्तीय कटौती करके इनको छोटा किया गया है । हमें लगता है कि जो माननीय वित्त मंत्री जी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें गुस्सा है कि उनके गठबंधन के सरकार में माननीय जल संसाधन मंत्री जी थे और बीच में कुछ कारणवश टूटकर यह अलग हो गये थे । नीतीश कुमार जी को छोड़कर अलग हुए थे तो उनको गुस्सा है कि ये समय-समय पर धोखा देते हैं । इसलिए इनके विभाग में कटौती की जाय और वह गुस्सा आज जाहिर हो रहा है । क्योंकि हमें याद है कई मीटिंगों में हमारे बड़े भाई आदरणीय ललन बाबू बोले थे कि आपलोग कोई कुछ नहीं कर पाइयेगा- कांग्रेस पार्टी में जब गये थे कि नीतीश कुमार जी के विरूद्ध आपलोग कितना बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए आपलोगों से कुछ नहीं होनेवाला है। हम जानते हैं कि उनके

पेट में कहां-कहां दांत है और हम एक-एक करके चुन-चुन कर निकालने का काम करेंगे । यह गुस्सा आज हमें पता चल रहा है कि यह गुस्सा बजट के माध्यम से इनको छोटा किया जा रहा है । यह दुर्भाग्य है, हम तो जानते हैं कि विकास करनेवाले हैं, शासन करने वाले हैं । आज हमें यह अहसास भी हुआ है शासन का क्योंकि जितने भी वक्ता सत्ता पक्ष के बोले हैं आज....

सभापति(डॉ0 रंजु गीता) : अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय प्रकाश : हम बोलते हैं जितने भी सत्तापक्ष के बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी के बारे में कोई बड़ाई नहीं किया कि उनके नेतृत्व में सिंचाई विभाग में काम हो रहा है, सिर्फ ललन बाबू के नेतृत्व में काम हो रहा है । यानी यहां पर ये लोग भी डर और भय के साथ ललन बाबू का ही बड़ाई करने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को छोटा करने का काम किया है । यह आज एहसास हुआ सदन में पूरे बिहार में हमलोगों को सुनने के लिए मिलता था कि जो भी सत्ता में जो भी काम होगा विभाग में या सरकार में जब तक ललन बाबू से नहीं मिलियेगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता है । वह बात आज जगजाहिर सत्य हुआ और हमलोगों को पता चला है । इसलिए हमलोग यह बताना चाहते हैं कि जो स्थिति है, हमारा सौभाग्य है, माननीय ललन बाबू का भी सौभाग्य है जहां जाते हैं, जिस विभाग के मंत्री बनते हैं, उसमें इनके साथ प्रधान सचिव अरूण बाबू जाते हैं, बढ़िया संबंध है, मधुर संबंध है । विकास करनेवाले हैं, दोनों जानते हैं कि कैसे बिहार को विकास की ओर धकेला जाय या नीचे किया जाय । इसलिए इन चर्चाओं को करना जरूरी था । आज जो पूरे बिहार की स्थिति है । आज चूहा का तो वही बात है न कि चूहा कैसे बनेगा, चूहा कैसे निकलेगा, इन शब्दों का चर्चा आज होना है । आज हम आपको बताना चाहते हैं जिस पुकुर जलाशय योजना, हम धन्यवाद देते हैं, हम आदर करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम सम्मान करते हैं कि कई बार एक बार नहीं पचास बार जो 18 महीना के गठबंधन की सरकार में, हमने प्रत्येक बार इनको पचासों लेटर लिखने का काम किया और कुकुरझोक डैम में 39 करोड़ रूपया देने का काम किया गया ।

सभापति(डॉ0 रंजु गीता) : अब भी लिखियेगा पत्र ।

श्री विजय प्रकाश : अभी भी लिखते हैं । 89 करोड़ रूपया खड़गपुर में देने काम किया गया, लेकिन क्या कारण है कि आज 39 करोड़ पर कुकुरझोक डेम में पहुंच गया है, 89 करोड़ खड़गपुर में चला गया है । दो बार टेंडर हो चुका है लेकिन दो व्यक्ति, एक व्यक्ति से अधिक टेंडर नहीं डालता है जिसके कारण मेरा काम अधूरा पड़ा हुआ है । क्या कारण है कौन सा ऐसा सत्य है कि वहां कोई व्यक्ति टेंडर डालने के लिए तैयार नहीं होता है । हम कई लोगों से बात किये हैं कि कोई तो टेंडर डालो भाई लेकिन हुआ कि नहीं जब तक प्रधान सचिव से, मंत्री महोदय से और चीफ इंजीनियर का यह शब्द कहना है कि जब तक वहां से आदेश नहीं होगा, दूसरा कोई टेंडर डालियेगा तो उनको ब्लैक लिस्टेड में डाला जायेगा । यह हमको सूचना

मिली है । आज हम इनसे कहना चाहते हैं कि उसमें पारदर्शिता लाइये और टेंडर डलवाइये, खुलेआम खुला छूट दीजिए कि कोई भी टेंडर डाले तो उसमें डर और भय का क्या बात है । जो कैंसिल किया गया हम नागिन नकटी का जीर्णोद्धार का मामला है । हम गिधेसर, गोपाल, खरसारी नगर में जो लूट हो रहा है अपर क्यूल में डोमचांच से इस्टीमेट में है कि डोमचांच से गिट्टी लाना है, लेकिन वह शेखपुरा जिला का गिट्टी लग रहा है । यह जॉच का विषय है माननीय मंत्री जी इसको गहराई से लिया जाय । इसकी जॉच करवाई जाय । यहां पर आपके विभाग के पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं । इसकी जॉच करवायी जाय कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है । बानन जलाशय योजना मुख्य नहर का जीर्णोद्धार आज तक नहीं हुआ है इसको करवाने का काम करें । हम जो हैं कुकुरझव बाया नहर तटवा का शाखा नहर का मामला है, बेलिया में तेल्हारा सिंचाई पक्कीकरण का मामला है, बेलिया कैनाल में चार नंबर से मलयपुर बाराघाट सिंचाई नाला पक्कीकरण का मामला है । अन्य कई मामलों का हम सोच रहे हैं कि कैसे सिंचाई विभाग क्योंकि वह इलाका है पूरे बिहार का है ।

सभापति(डॉ0 रंजु गीता) : आपका समय समाप्त हुआ । अगला सदस्य आप ही के दल के हैं।

श्री विजय प्रकाश : पूरे बिहार का मामला है इसको उठाना चाहिए । जहां तक बांका जिला का चर्चा हुआ । बांका जिला में जब माननीय मंत्री जी उद्घाटन करने के लिए गये थे बतावें माननीय मंत्री जी कि बदुआ जलाशय में बिहार सरकार का कितना पैसा लगा हुआ है कि भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है ? किसके निवेदन पर भारत सरकार से पैसा आया है, लेकिन वहां माननीय मंत्री जी गये और शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया, लेकिन जिनके प्रयास से पैसा आया है, जय प्रकाश नारायण यादव उनका शिलापट्ट पर नाम तक नहीं दिया गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । इस बात को हम जानते हैं । हम कहना चाहते हैं कि मोकामा टाल में पैसा दिया गया ।

टर्न-23/ज्योति/08-03-2018

श्री विजय प्रकाश : लघु सिंचाई में जितने नलकूप है सब बंद पड़े हैं । देखा जाय ।

सभापति (डा0 रंजू गीता): माननीय सदस्य मुद्रिका प्रसाद राय शुरु करें । आपके समय से कटौती शुरु हो जायेगी । आप समाप्त करिये ।

श्री विजय प्रकाश : मुख्यमंत्री विकास योजना का पैसा इसको आप बढ़वाने का काम करिये ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : आप शुरु करिये ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : माननीय सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं महिला दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ । आज जल संसाधन विभाग के बजट के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर मुझे मिला है । सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूँ कि जल संसाधन विभाग ने जो पूरे राज्य में जो ढिंढोरा पीट कर रखा है विकास का, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है । जल संसाधन विभाग द्वारा जो सिंचाई के साधन पूरे राज्य में उपलब्ध कराये गए हैं, उनमें जो त्रुटियॉ हैं, जिनके कारण किसान प्रभावित

हो रहे हैं, मैं उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । पूरे राज्य की जो स्थिति है, मैं सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ और वहाँ की स्थिति के बारे में, मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। महोदया, सारण जिला में दो डिवीजन हैं नहर प्रमंडल के और दोनों में रेस्टोरेशन का काम चल रहा था और इस योजना का मार्च 15 में एग्रीमेंट हुआ था और एक एम.डी.सी. का जो डिवीजन है मरौढ़ा में उसमें 10 परसेंट कार्य होने के बाद ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया ठीकेदार को क्योंकि कार्य पूर्ण नहीं हुआ था और आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है । उसीतरह से सारण नहर प्रमंडल है, उसमें 35 प्रतिशत तक कार्य हुआ है और संवेदक को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, सिंचाई की जो कार्य प्रारम्भ हुआ, उसके शुरु होने से ले करके आज तक उस कैनाल में सिंचाई के लिए जल नहीं छोड़ा गया है और सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि कैनाल का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस सिस्टम में जितने भी उप वितरणी, वितरणी या जो भी सिस्टम में लगे हुए हैं, वे सारे बंद पड़े हुए हैं, ध्वस्त है और सिंचाई का कोई साधन उपलब्ध नहीं है । सबसे जो दुखद स्थिति है, उस कैनाल के दोनों तरफ जो गांव बसे हुए है जैसे बगही, खराटी, शहनवाजपुर, भेलहड़ी, हरिपुर, मझोपुरा, नारायणपुर ये गांव जो हैं, इस आशा में आस लगाए बैठे हुए हैं कि जब रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, तो इन गांवों के लिए पुल और पुलियों का निर्माण होगा और आवागमन का साधन बन पायेगा लेकिन यह भी नहीं हो पाया है, जिससे काफी लोगों में आक्रोश है । यह स्थिति है सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग की लेकिन एक और भी जो विभाग है लघु जल संसाधन विभाग जिससे किसानों के छोटे जो दूर दराज के गांव हैं, जहाँ सिंचाई, जहाँ जल संसाधन विभाग, अपना जल वहाँ तक पहुंचा नहीं पाता है, वहाँ नलकूप की व्यवस्था लघु जल संसाधन विभाग द्वारा की गयी है, ये सब नलकूप बंद पड़े हैं और कहीं भी सिंचाई नहीं हो पा रही है और किसान जो हैं, आस लगाए बैठे हैं कि कब ये मरम्मत होगा या इसका निर्माण होगा या पुनःस्थापना होगी लेकिन यह सरकार द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है । मैं बाढ़ आपदा से संबंधित सवाल जो किसानों के है- इस बार जो बाढ़ आयी थी 2017 में, हमारे क्षेत्र के दो प्रखंड जो हैं जिसके 26 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुए, पूरी तरह से बर्बाद हुए, उन प्रखंडों में.....

सभापति (डा0 रंजू गीता): अब आप समाप्त करेंगे । माननीय सदस्य आपके ही दल के एक और को बोलना है ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : अच्छा दो मिनट समय दिया जाय कुछ और बोल लें ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : आपका समय समाप्त हो चुका है, माननीय सदस्य डा0 रामानुज प्रसाद । क्योंकि अब सरकार का उत्तर भी होना है ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : पानापुर प्रखंड का जो रसौली गांव हैं जहॉं डाबरा नदी के बांध टूट जाने से पूरे गांव की फसल क्षतिग्रस्त हो गयी थी, अभी तक बांध की मरम्मती नहीं हो पायी है । यदि बांध की मरम्मती नहीं होगी, तो आने वाला जो बरसात का सीजन है, उसमें किसान जो खेती करेंगे, बरसात में बर्बाद हो जायेगी, इसलिए सरकार से मांग करते हैं, मंत्री जी इसपर ध्यान दें, बांध की अविलम्ब मरम्मती करा दें, इतना ही कह कर अपनी वाणी को विराम देता हूं । धन्यवाद ।

सभापति (डा0 रंजू गीता): माननीय सदस्य डा0 रामानुज प्रसाद , आपका मात्र 4 मिनट समय है ।

डा0 रामानुज प्रसाद : महोदया, चार मिनट तो ऐसे बहुत है कुछ बोलना लेकिन अपने क्षेत्र की बात कर एक सुझाव माननीय मंत्री गण बैठे हैं, उनको देकर बैठ जाऊंगा । यह गूढ़ विषय है । आज हमारी पार्टी ने कार्य स्थगन भी लाया था हमारे माननीय सदस्य ने। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास की बात करते हैं लेकिन वही है कि इशु चेंज करते रहते हैं । एक इशु पर जो पहले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर टी.डी.पी. ने सरकार छोड़ा है और गठबंधन छोड़ा है और हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं, तो गए हैं, मुख्यमंत्री तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से और हमारे विजेन्द्र बाबू भी कोशी के इलाके से आते हैं, जो जल का त्रासदी इलाका सबसे ज्यादा झेलता है, तो क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जा में वाटर मैनेजमेंट मांग लेते हैं । हमारा बिहार, माननीय मंत्री जी, दोनों आपके महकमा महत्वपूर्ण है । आपको बिहार को बचाना भी है और सिंचाई भी करना है । बाढ़ से भी बचाना है और सिंचाई भी आपके जिम्मे हैं लेकिन जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि वाटर मैनेजमेंट कर दिया जाय । यह मामला जो है भले ही हमारा राष्ट्रीय मामला है, अन्तर्राष्ट्रीय मामला है लेकिन इसको बिहार की सरकार डबल इंजन की सरकार विशेष राज्य को मुद्दा बनाने वाली सरकार, बिहारियों का हस्ताक्षर भेजने वाली सरकार, नाखून-खून कटवाकर भेजने वाली सरकार अगर इसी को मनवा ले केन्द्र से, तो मैं समझता हूँ कि हमारा बिहार देश का सबसे उन्नत राज्य हो जायेगा । माननीय विजेन्द्र बाबू और आप भी, जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं । जो बात किताब में लिखी गयी है :

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

''जिस मद में बाढ़, चक्रवात, बाढ़ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यों का मरम्मत क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ प्रणाली की मरम्मती ।'' पैसे मांगने जा रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि साहेब पैसे खर्च करने का जो तौर तरीका अपनाया है, कितने बाढ़ से बचा पा रहे हैं आप बिहार को ? आज बिहार बह जा रहा है । एक ही अखबार में रहता है बिहार सूख गया, बिहार बह गया, तो बिहार बहता भी है और सूखता भी है । आखिर हमारा यह वंचित बिहार, खंडित बिहार, है क्या हमारे पास ।

सारे हमारे खनिज चले गए, जंगल चले गए सब सम्पदा चला गया । हम तो ऐसे बिहारी बचे हुए हैं, जिसमें बाढ़ और सुखाड़ हमारी नियति है । माननीय मंत्री जी, आपका महकमा बहुत महत्वपूर्ण है । अगर हम इस बिहार को उन्नत करना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम यहॉ बाढ़ और सुखाड़ वाले राज्य को अपने यहॉ रोजगार मुहैय्या करना, अपने किसानों को संपन्न करेंगे बल्कि मैं समझता हूं कि एक और जो मेरी समझ है ...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : एक मिनट मगर अध्यक्ष महोदय अब समाप्त कर रहे है ।

अध्यक्ष : एक मिनट मांग कर आप शुरु ही किए थे ।

डा0 रामानुज प्रसाद : मंत्री जी से अपनी सब मांग छोड़ दिए हैं और सब नहीं कहेंगे लेकिन क्षेत्र की एक मांग है जो मंत्री जी से पहले भी मांगते रहे हैं ।

अध्यक्ष : अपने क्षेत्र की बात को आप अंत में क्यों रखते हैं ?

डा0 रामानुज प्रसाद : अंत में रखते हैं, इसके पहले राज्य की बात रखेंगे न ? हम विधायक हैं बिहार विधान सभा के । मुगल कैनाल, हमने सवाल उठाया था, माननीय मंत्री जी उसका जवाब आया था । इनका इंजीनियर, लोगों ने जवाब भेजा था ।

क्रमशः

टर्न-24/08.3.2018/बिपिन

डा0 रामानुज प्रसाद : क्रमशः मैं आग्रह कर रहा हूं, हमारे यहां यह जो कैनाल है सारण जिला में, हमारे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा पड़ता है । उसकी उड़ाही अगर करा दें तो हम बाढ़ से भी बचेंगे और सिंचाई भी हमारा होगा मगर पालछड़की पर जो काम आपकी कृपा से हो रहा है वह रोड का चौड़ीकरण, ऊँचीकरण, पक्कीकरण, उससे 12-14 गांव पूरा जलमग्न हो जाएगा । उसमें स्लुइश गेट का मांग जनता का बहुत महत्वपूर्ण है । यह मेरा आग्रह होगा कि उसमें स्लुइश गेट करा दिया जाए ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब समाप्त कीजिए ।

डा0 रामानुज प्रसाद : एक दीघवारा का है, मैं मिल कर दूंगा माननीय मंत्री जी को कि जो हमारा मही नदी है, उसके अपस्ट्रीम में आपने सड़के बनवा दी और डाउनस्ट्रीम में आपके इंजीनियर लोगों ने छोड़ दिया । मैं मिलकर आपसे आग्रह किया था, रोज विभाग में संपर्क करता हूं, होता है डी.पी.आर. नहीं आ रहा है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि डी. पी.आर. मंगा कर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नदी है, उसको करवा दें तो जनता को उससे बहुत लाभ होगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने जल संसाधन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा में भाग लिया है और कई माननीय सदस्यों ने बहुत ही

सकारात्मक सुझाव भी दिया है जिसको हमलोगों ने नोट किया है और हमलोग उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमलोग जरूर उस दिशा में कार्रवाई करेंगे जो उनका सुझाव हैं सकारात्मक, उसको हमलोग मूर्त्त रूप देने का काम करेंगे ।

महोदय, जल संसाधन विभाग का काम, आपको भी सौभाग्य रहा है उस विभाग को देखने का, इस विभाग का काम बहुत हौच-पौच था पहले, हॉच-पौच इस मतलब में कहिए कि पहले एक ही इंजीनियर सिंचाई का भी काम देखता था और बाढ़ का भी काम देखता था और बाढ़ के काम होता क्या था, सितम्बर-अक्तूबर तक बाढ़ खतम हुआ और फिर नवम्बर से अगले साल के बाढ़ की तैयारी में लग गया तो सिंचाई का काम देखने का उनको फुर्सत नहीं रहता था । 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला नवम्बर में, तो पहली समीक्षा बैठक में इन्होंने यह कहा कि सिंचाई विभाग का जो मूल उद्देश्य है, वह उद्देश्य है सिंचाई क्षमता को सृजित करना और सिंचाई क्षमता का जो ह्रासित है, उसको पुनर्स्थापित करना दो अलग-अलग विंग में नहीं बांटिएगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा और हमलोगों ने तत्काल कार्रवाई की और 2016 के मई-जून होते-होते तक पूरे विभाग को हमलोगों ने दो भाग में बांट दिया । जो बाढ़ में पदस्थापित अभियंता हैं वो सालो भर बाढ़ का काम देखते हैं और जो सिंचाई में पदस्थापित हैं, वे सालो भर सिंचाई का काम देखते हैं।

इसके साथ-साथ, एक नीतिगत निर्णय हमलोगों ने सिंचाई क्षमता को सृजित करने में यह लिया कि कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे, यहां भी कई माननीय सदस्यों ने कई योजनाओं की चर्चा की जैसे, बरनार जलाशय योजना या कुकुरछप योजना और कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में या तो फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण काम रूका हुआ है, वन विभाग के कारण या नहीं तो फिर भूमि अधिग्रहण के काम के कारण काम रूका हुआ है । खर्च उसमें भी होता रहता था । हमलोगों ने यह फैसला किया, नीतिगत निर्णय लिया कि जहां इस तरह का अड़चन है, वह अड़चन जब तक दूर नहीं होगा, तब तक हमलोग उस योजना पर खर्च करने काम नहीं करेंगे, हम वैसे योजनाओं पर खर्च करेंगे कि जिसपर कोई खर्च अभी नहीं, अड़चन नहीं है ताकि हम योजना को ससमय पूरा कर सकें और इसके लिए हमलोगों ने कार्य योजना बनाया और कार्य योजना बनाकर हमलोगों ने उसपर काम शुरू किया । काम करने के बाद उसका फलाफल यह है कि आज कई सिंचाई योजनाओं को हमलोग पूरा चुके हैं और इस साल भी हमलोग का लक्ष्य है कि कई सिंचाई की योजनाओं को पूरा करें ।

अब महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 2017 के अगस्त में अचानक बिहार का जो पूर्वोत्तर जिला है, अररिया, कटिहार, किशनगंज का इलाका या फिर जो हमारा उत्तरी बिहार का जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, बगहा, सीतामढ़ी, शिवहर, इन सारे जगहों पर अचानक अगस्त के तीसरे सप्ताह में बाढ़ आई ।

अचानक, काफी भयानक रूप से बाढ़ आया और मुख्यमंत्रीजी जब खुद पहली बार पूरे क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि यह फ्लैश फ्लड है, फ्लैश फ्लड उन्होंने कहा, इसलिए कि चार दिन के अंदर मेरे पास जो वर्षापात हुआ, उसका आंकड़ा है मेरे पास । 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में जो हमारे पूर्वोत्तर बिहार के जिले हैं, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार, प्रतिदिन के वर्षापात का हमारे पास डाटा है । इस 10, 11, 12, 13 और 14, ये 10 से 14 तक के बीच में जो कुल वर्षापात हुआ, वह 11हजार 762 मिलीमीटर बारिश हुई इस इलाके में । इसके अलावा, उससे सटा हुआ नेपाल का जो इसका कैचमेंट एरिया है, नदियों का नेपाल के प्रभाव में, वहां के भी जो वर्षापात है उसका भी आंकड़ा हमारे पास है, ओखलाडूंगा, तापेलगंज, धनकूट्टा, विराटनगर, धरान, सोक्टि, ये जो इलाके हैं उसमें भी 10 से 14 अगस्त का जो वर्षापात का डाटा है वह डाटा यह बताता है कि 12,376 मिलीमीटर बारिश हुई । अब अगर अध्यक्ष महोदय, 12,376 और 11,762 यह अगर इतना बारिश अगर हुआ तो कहां जाएगा पानी ? अचानक अररिया में पानी प्रवेश किया और पानी जो प्रवेश किया, वह लगभग लोग बताते हैं कि पांच फीट-छः फीट की ऊँचाई से पानी प्रवेश किया तो जलमग्न हुआ । उसके अलावा, जो उत्तरी बिहार का इलाका है, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, ये **इलाके में जो बारिश** हुई वह सातहजार बीस मिलीमीटर बारिश हुई इस चार दिन में और इससे सटा हुआ जो गंडक का बूढी गंर्डक का और यसइन नदियों का जोजलग्रहण्धा यसक्षेत्र है नेपालके प्रभाव में, वहां सबारिश हुई 10192.10मिली मीटर । अ ब यह आप 18हजारमिली मीटर बारिश यचार यदिन यसमे ंयउस इलाके में हुइर्अ यउत्तरी यबिहार के यइलाके यमें जिसके कारण पूर्वी पश्चिमी चंपाकरण का इलाका बगहा काइलाका सीमढ़ी शिवहर का इलाका पूराजलमग्न हुआ, और नदियों में पानी हुअ ा । हम आपको अ 0म0 यह बताना चाहते हैं कि मुख्यतौर पर जो नदियां है कोसी यसबराज पर कोसी नदी का जो डिस्चार्ज रहा वह ढाई लाख क्यूसेक 6 दिनतक स्टैटिक रहा , 6 यसदिन तक ढाई लाख क्यूसक लगातार रहा हऔर 84 दिनतक कोसी सनदी का पानी खतरे के निसान से उपर बहता था । गंडक बराज पर सवा पाच लाख क्यूसेक 3 से 4 यदिन तक रहा और 24 यसदिनतक गंडक नदी का पानी खतरे के यनिसान से उपर बहता रहा, बूढ़ी गंडक खतरे के यनिशान से 22 दिन तक तक उपर यरहा, बागमी यखतरे के निशान से तीन महीना इक्यानवे दिन तक बागमती नदी खतरे के निशान से उपर रहा कमलाबलान 33दिन तक खतरे के निशान से उपर रहा, महानन्दा 14 दिन रहा और पुनपुन 15 दिन रहा और यह तो हमने जो यडिस्चार्ज बताया चाहे वह बीरपुर बराज का हो या बाल्मीकीनगर बराज का हो, यह तो मैंने बराज का डिस्चार्ज बताया । ययह तो जो नेपाल का पानी था उसका डिस्चार्ज था

औक्र इसके अबितरक्त हमारे राज्य के अंदर जो बारिश हो रही थी वह उस नदी में जो मिल रहा था उसके आधार पर यह हो रहा था ... व्यवधान

मंत्री : अब ये जाएंगे , इनको कोई काम है नही, इसलिए अ0म0 हम यह बताना चाहेंगे यआपको व्यवधाान आप जाइऐ, इसलिएउ कि यसआपको काम में कोई रूचि नहीं है ।

कबहुत अच्छा है चले जाइऐ चले जाइए । व्यवधान ।(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गए ।)

टर्न–25/ कृष्ण/08.03.2018

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कई नदियों ने नया एच0एफ0एल0 कायम किया । कोसी नदी ने बसुआ में उसका 2010 का जो रेकर्ड था एच0एफ0एल0 का 49.17 मीटर, उसको पार करके 49.20 मीटर का इस बार एच0एफ0एल0 कायम किया कोसी नदी ने । गंडक के डुमरिया घाट में 2014 का 63. 30 मीटर इनका एच0एफ0एल0 था, उसको क्रॉस करके 64.10 मीटर का नया एच0एफ0एल0 कायम किया । बागमती ढेंग में 72.34 मीटर रेकर्ड था 2014 में, उसको 72.7 मीटर और ललबकिया नदी गोआबारी में 73.80 का नया एच0एफ0एल0 कायम किया । इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम यह आपको बताना चाहते हैं कि इसके कारण बाढ़ आई । लेकिन इस बाढ़ के कारण कई जगहों पर दबाव भी हुआ । हमारे तटबंधों के कई जगह सीपेज के कारण, उसके ओवर टॉपिंग के कारण कई जगह दबाव हुआ और कई जगह ब्रीच भी हुआ लेकिन उस ब्रीच को फ्लड पीरियड में ही हमलोगों ने मोनिटर करके उसको फ्लड पीरियड में ही रीपेयर कराकर उसको ठीक भी कराया । उसका डिटेल्स है मेरे पास, अभी समय नहीं है, हम इसको सदन के पटल पर रख देंगे । इसको कार्यवाही का भाग बना लिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, यह हम आपसे आग्रह करते हैं । इसके अलावा बागमती और बूढ़ी गंडक का जो उफान था अंत में, जब सभी नदियों का उफान था, तो हमारे विभाग के प्रधान सचिव ने अभियंता प्रमुख को और सारे अभियंताओं को 15 दिनों तक हमलोगों ने मुफ्फरपुर और सीतामढ़ी में कैम्प कराया और उस कैम्प का परिणाम था कि बेगुसराय, समस्तीपुर और रोसड़ा के इलाके को हमलोग बाढ़ से इस बार बचा सके और बाढ़ वहां नहीं जा पायी । हमारे प्रधान सचिव लगातार दो–दो बजे रात तक, तीन–तीन बजे रात तक हमारे इन्जीनियर्स घुमते रहे और पूरे बाढ़ पीरियड में हमलोगों ने एक–एक सेंसिटीव प्वाइंट था उसका मोनिटरिंग किया । कई जगह इन्जीनियरों के स्तर पर लापरवाही भी हुई और इन्जीनियरों के स्तर पर जब लापरवाही हुई, हमलोगों ने जब मोनिटरिंग में पाया कि इन्जीनियर साईट पर नहीं है तो 19 अभियंताओं को हमलोगों ने ससपेंड किया, उसमें मुख्य अभियंता तक के अधिकारी

हैं और बिना विलंब किये हमलोगों ने उन्हें ससपेंड किया, महोदय, सबों पर विभागीय कार्यवाही चल रही है और उसका जो फलाफल होगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आनेवाले समय में मेसेज जाय कि बाढ़ के साथ अगर कोई समझौता, लापरवाही होगी तो विभाग उसको किसी भी कीमत पर बर्दास्त करने के लिये तैयार नहीं है । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस बार 2018 के लिये भी हमलोगों ने तैयारी शुरू कर दी है । 421 स्थानों को चिन्हित करके हमलोगों ने योजना स्वीकृत की है । राज्य योजना से 342, नाबार्ड से 12, एफ0एफ0पी0 से 8 आपदा प्रबंध से प्राप्त राशि से 44 और आर0एम0ए0डब्ल्यू0बी0ए0 से 15 योजनाओं को किया है । इसका भी डिटेल्स हम अध्यक्ष महोदय सदन के पटल पर रख देंगे, उसका पार्ट बना लिया जाय । क्योंकि इसमें समय कुछ ज्यादा लगेगा । लेकिन 421 योजनायें जो हमलोगों ने बनायी है उन योजनाओं में हमलोगों ने जो तय किया है चैनल का सक्रियकरण, गेजिंग का काम जहां गाद जमा है, उसको गेज करके उसकी गहराई बढ़ाना, सीपेज एवं पाईपिंग वाले स्थान पर विशेष ध्यान और जी0आई0 जो मशीन निर्मित है, मशीन निर्मित जी0आई कैरेट, वायर कैरेट उसका हमलोग उपयोग कर रहे हैं और उसके साथ-साथ हमलोगों ने निर्णय लिया है कि पुराना बोरा का इस्तेमाल नहीं करके इस बार नये बोरे का इस्तेमाल करेंगे । तो हमने यह आपको बताया अध्यक्ष महोदय, किये सब हमलोग 2018 की तैयारी के लिये कर रहे हैं और 2018 की तैयारी में हमलोगों ने एक बात अपने अभियंताओं को कहा है क्योंकि कटाव निरोधक जो काम होता है वह 15 मई तक खत्म करना होता है । नियम यही कहता है, कई बार जून तक काम होता था, पर हमलोगों ने कहा है कि 15 मई का मतलब है 15 मई और 30 नहीं, 5 जून तक मुख्यालय को सभी कार्यपालक अभियंताओं को रिपोर्ट देना है कि मेरे डिवीजन के अंदर जितना काम चल रहा था, वह पूर्ण हो गया है, ताकि 5 जून के बाद फ्लाईंग स्क्वाड की टीम से उसके गुणवत्ता की जांच करायेंगे और जहां गुणवत्ता में लापरवाही पायी जायेगी, वहां संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी । तो इसलिए हमलोगों ने दिया है 5 जून तक कम से कम पूरा जून महीना 25 दिन हमको भी जांच कराने का मौका मिले और उसके लिये फ्लाईंग स्क्वाड की टीम तैयार है । इसके अलावे सिताब-दियारा बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वे लोग चले गये, सिताब-दियारा के बारे में हम बता दें, भोला बाबू तो इस बात को उठा तो दिये, उसके बाद घिसक लिये क्योंकि उनको तो सुनना रहता नहीं है । तो सिताब-दियारा में हमलोगों ने 90.97 करोड ़की लागत से जो उसके कटाव निरोधक कार्य हैं, सिताब-दियारा लोक नायक जय प्रकाश जी की जन्मस्थली है, उनका गांव है । हमलोगों ने उस पर ध्यान दिया । 90.97 करोड़ की लागत से हमलोगों ने योजना स्वीकृत कर दी है । लेकिन वह योजना तबतक कारगर नहीं होगा जबतक उससे सटा हुआ यू0पी0 का जो भाग है नदी का, वह योजना स्वीकृत नहीं करेगा, हालांकि अभी यू0पी0 में काम चल रहा है, उसकी

तैयारी चल रही है, वे लोग डी0पी0आर0 बना रहे हैं और वह जब बनेगा तब उस काम को ये लोग आगे बढ़ा सकेंगे । महोदय, इसके अलावे हम आपको बताना चाहते हैं कि बागमती का जो फेज-3 (ए) का जो काम है, पहले वह एच0ए0सी0एल0 को काम दिया गया था, एच0ए0सी0एल0 राष्ट्रपति शासन के दौरान यहां एच0ए0सी0एल0 के साथ एकरारनामा करके उसको काम दे दिया गया था, वह काम कर नहीं रहा था, एच0ए0सी0एल0 के साथ फुलप्रोस करके हमलोगों ने फ्रेश टेंडर करके उसकी स्वीकृति कर दी, टेंडर डिसाईड कर दिया और अभी हमलोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि बागमती फेज-3 (ए) के पूरे का तटबंध निर्माण की योजना है, उसका शिलान्यास वह चल कर कर दें, उनसे हमलोगों ने आग्रह किया है, तत्काल हमलोग बागमती फेज-3 (ए) का शिलान्यास करा देंगे, उससे बेगुसराय, खगड़िया से लेकर समूचा समस्तीपुर और दरभंगा तक का इलाका सुरक्षित हो जायेगा ।

इसके अलावा हमलोग महानन्दा नदी की भी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, महानन्दा के काम को भी कर रहे हैं । इसके अलावा महोदय हम बताना चाहते हैं कि बाढ़ प्रबंधन की दिशा में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का एक कंसेप्ट था, विश्व बैंक की सहायता से, जो कंसेप्ट था, मैथेमेटिकल मोडल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनिसाबाद में कर दिया है । उसके फिजिकल मॉडलिंग का काम वीरपुर में होना है, उसके लिये हमने नवंबर, 2018 का समय निर्धारित कर दिया है । 2018 नवंबर तक हमलोग उस काम को पूरा करेंगे, उसकी जितनी तैयारी हो सकती है, वह सारी तैयारी हमलोगों ने पूरी कर ली है और फिजिकल मोडलिंग का काम नवंबर में लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं । इसलिये महोदय हमने आपको बाढ़ से संबंधित चीजों को बताया। अब सिंचाई के बारे में 5-7 मिनट में बताकर कुछ योजना विकास के बारे में भी बताना चाहते हैं ।

माननीय सदस्य भोला बाबू चले गये, बहुत लंबा-लंबा भाषण दे रहे थे, सीतामढ़ी जिला में तीन योजनायें जो सीतामढ़ी पूरे इलाके के लिये सबसे पोपुलर डिमांड था, एक मनुसमारा जल निस्सरण योजना और दूसरा, जो रातो नदी में नोमेन्स लैंड तटबंध और तीसरा लखनदेई नदी के धार को पुनर्स्थापित करना, यह बरसों-बरसों से सीतामढ़ी के लोगों की मांग थी और इन तीनों योजनाओं की स्वीकृति कराकर, इसका टेंडर डिसाईड कराकर और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उपमुख्यमंत्री दोनों गये थे और इनलोगों के साथ जा करके हमलोगों ने शिलान्यास करके इसका कार्य प्रारंभ कर दिया और इसका काम भी शुरू हो गया । इसके अलावा 2018 में कई योजनाओं का हमने लक्ष्य रखा है । उसकी भी सूची हम सदन के पटल पर रख देंगे । उससे हम 21.9 हजार हेक्टेअर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित कर पायेंगे, 2017-18 में । अभी माननीय सदस्य बटेश्वर स्थान की चर्चा कर रहे थे । अब समय तो नही है । लेकिन

बटेश्वर स्थान के बारे में बता दें कि बटेश्वर स्थान का जो पाप है, वह पाप अगर है तो इनके माथे का पाप है । महोदय, 1977 में यह योजना शुरू हुई और 2005 मार्च तक नहर की मिट्टी का काम इनके समय में पूरा हुआ, सिर्फ पम्प हाउस का काम फेज-1 और फेज-2 जो पम्प हैं, पम्प हाउस-1 और पम्प हाउस-2 का काम इनलोगों ने छोड़ दिया । क्योंकि इनलोगों को उस समय मिट्टी के काम में रूचि होगी । कांट्रैक्टर जो भी रहा होगा, मिट्टी का काम इनलोगों ने कर दिया, अब उद्घाटन के पहले जब हमलोगों ने सोचा कि टेस्ट तो करा लें चूंकि नहर तो बना है बीस साल पहले, 18 साल पहले तो जब हमलोगों ने टेस्ट कराया तो मालूम हुआ कि एक जगह अन्डरपास एन0टी0पी0सी0 ने बनाया था, एन0टी0पी0सी0 ने विभाग को लिख कर दिया है कि हमसे चूक हो गयी।

क्रमशः

टर्न-26/सत्येन्द्र/8-3-18

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री (क्रमशः): और वह अपने खर्चे पर एन0टी0पी0सी0 ने अंडरपास का निर्माण कराया और उस अंडरपास के निर्माण कराने के बाद फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने जाकर विधिवत उसका उद्घाटन कर दिया और ये काम हुआ । वह पाप तो आपका है, किसके मत्थे मढ़ रहे हैं अपना पाप, अपने पाप को भी तो कम से कम अपने माथे स्वीकार करने का साहस रखिये तो वह भी साहस उनको नहीं है लेकिन खैर, इसके अलावा 2018-19 में भी अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने कई योजनाओं का लक्ष्य रखा है जिसकी भी सूची है जिसमें बिहुल नदी है, गरौल बीयर है, बघेला घाट है, टिकमा सिंचाई योजना है, ये सब सूची में है, वटाने जलाशय योजना है, कुन्दन जलाशय बराज योजना है, कुण्ड घाट है, ये कई योजनाएं हैं जिसकी सूची भी हम सदन के पटल पर रख देंगे और हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको इसका पार्ट बना लें । इसके अलावा हमलोगों ने इस बार ह्रासित क्षमता जो है उसका भी लक्ष्य रखा है 2017-18 में, हमलोगों ने 43571 हे0 में जो ह्रासित क्षमता थी, उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया है और 2018-19 में हमलोगों ने 2 लाख 74 हजार 257 हेक्टेयर पुनर्स्थापन का लक्ष्य रखा है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो 2 लाख 74 हजार 257 हेक्टेयर का लक्ष्य हमलोगों ने रखा है, इस लक्ष्य को हमलोग प्राप्त करेंगे और 2 लाख 74 हजार 257 हेक्टेयर में जो ह्रासित क्षमता है, उसका पुनर्स्थापन हमलोग करेंगे । इसके अलावे कई योजनाएं हमलोगों ने टाल के लिए भी स्वीकृत की है, तो वह समय अब है नहीं, इन्द्रपूरी की योजना है, आरा मुख्य कैनाल जो है सोन का, पूरे सिस्टम के लिए हमलोगों ने किया है, ए0डी0बी0 के साथ सहमति/

स्वीकृति मिल गयी है, ए0डी0बी0 के सहयोग से, लोन से हमलोग उसको बनायेंगे । इसके अलावे एक-एक योजना हम बतला रहे थे । अब हम मोरहर टाल पर आ रहे हैं।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को हम तिलैया ढ़ाढ़र ले गये थे और तिलैया ढ़ाढर बिहार का महत्वपूर्ण, मध्य बिहार का है और माननीय मंत्री जी देखे हैं, उस पर भी माननीय मंत्री जी को बोलना चाहिए ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: सुन लीजिये न, मैंने जो कहा कि सिंचाई क्षमता जो सृजित करने की सूची है, सूची तो हम पढ़े नहीं, हमने कहा कि सदन के पटल पर रख देंगे, उसमें आपका तिलैया ढ़ाढ़र भी है और जो आपका मोरा टाल है, उसके लिए न हम आपको बैठाये हुए हैं । महोदय, मोरा टाल एक सिंचाई योजना है । मोरा टाल इन्होंने दिखाया और वह गजब एक सिस्टम था, जो स्थानीय किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर 30 साल से उससे सिंचाई कर रहे हैं, हमलोगों ने उसको देखा और हमलोगों ने यह माना और विभाग के अपने अभियंताओं को कहा कि भाई किसान और गांव के लोग अपनी मेहनत से इसको कर रहे हैं और आप इसको एडौप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस योजना को हमलोगों ने एडौप्ट कर लिया, उसकी स्वीकृति दे दी और उसकी स्वीकृति दे करके, अब हमलोग टेंडर देकर उसका काम करेंगे, तो इसके लिए हम अवधेश बाबू को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने मोरा टाल को दिखाया । अब अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हम आपको कुछ योजना विकास विभाग के बारे में बता देना चाहते हैं कि जो मार्गदर्शिका माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कब्रिस्तान के घेराबंदी के संबंध में, जो लिखा हुआ है, वह पहले से है प्रोविजन है, मंदिर के बारे में लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि जिला स्तर पर समिति जो है, वह प्राथमिकता सूची जो है, उसमें से हमलोग प्राथमिकता शब्द को डिलीट कर रहे हैं, जिला स्तर से डी0एम0 और एस0पी0 की अध्यक्षता में जो समिति ने चिन्हित कर के कब्रिस्तान और मंदिर का जो सूची तैयार किया हुआ है, उस सूची में से अगर कोई माननीय सदस्य कोई भी प्राथमिकता तय करना चाहते हैं, तो अपनी राशि से वे प्राथमिकता तय करके उसका घेराबंदी वे करा सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, उसके अलावे स्वयं सहायता भत्ता के बारे में हम आपको बतलाना चाहते हैं कि 5-3-18 तक जो मान्य सात निश्चय की योजना है, 1 लाख 96 हजार 483 आवेदन स्वीकृत हुए, 108.74 करोड़ रू0 इसमें रिलीज किये गये और 1 हजार पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य अब तक योजना एवं विकास विभाग ने पूरा कर लिया है, 180 पंचायत सरकार भवन का कार्य प्रगति पर है और वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी 340 करोड़ रू0 का प्रावधान है, हमलोग इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे । योजना एवं विकास विभाग पंचायत सरकार भवन के निर्माण में प्राथमिकता दे रही है । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हम एक बात कहना चाहते हैं, जो माननीय सदस्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से संबंधित है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में हमने

समीक्षा में यह पाया है कि कई योजनाएं माननीय सदस्य अनुशंसा कर देते हैं, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल यह योजना प्रशासनिक स्वीकृति में लंबित रहता है, हो नहीं पाता है, हमने विभाग को कहा है और विभाग के समीक्षा के बाद हमने निर्देश दिया है कि विभाग के सचिव और बेलट्रॉन के अधिकारी इस पर अध्ययन कर रहे हैं । हमने कहा है कि जिस दिन माननीय सदस्य अनुशंसा करेंगे, उसको ऑनलाईन कर दीजिये और उसको पूरे सिस्टम को कम्प्यूटराईज्ड कर दीजिये, वह ऑनलाईन हो जायेगा, तो कितने दिनों के अन्दर जिला योजना पदाधिकारी ने प्रशासनिक स्वीकृति दी, उसको भी उस पर डाल दीजिये, तुरंत नहीं मिला, तो नहीं मिलने का क्या कारण है और अभियुक्ति में उसको भी दर्ज कीजिये कि कब तक योजना को पूर्ण होना है और योजना अगर पूर्ण नहीं हो रहा है, तो किन कारणों से पूर्ण नहीं हो रहा है । मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के सारे सिस्टम को हमने ऑनलाईन कर देने के लिए कहा है ताकि कोई भी व्यक्ति उसको देख सके, कोई भी माननीय सदस्य अपनी योजनाओं की स्थिति की जानकारी ले सकें और उसकी मोनेटरिंग हो सके, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये बात है और अब हम आपको लघु सिंचाई के बारे में बतला दें, राजकीय नलकूप अन्तर्गत कुल नलकूप बिहार में 9192 हैं, जिसमें चालू नलकूप है 4859, दरभंगा जिला के नलकूप जो है पुराना नलकूप, कुल चालू कितनी है, उसकी भी सूची उपलब्ध है । हम सदन के पटल पर रख देते हैं । सीतामढ़ी के बारे में पूरा लिस्ट यहां उपलब्ध है, हम उसको भी रख देते हैं । ये सारी स्थिति के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो नलकूप के बारे में जो पूर्ण स्थिति है, उन सारी स्थिति को हम आपके सामने दर्ज किया लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, आज जो योजना विभाग में जितना भी काम हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है पैसा, वह सारा पैसा अब हमलोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कर रहे हैं और इसका जो लाभ है, वह पूरा लाभार्थियों तक सीधे उसके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, जो हमलोग आर0टी0जी0एस0 करते हैं, उसके माध्यम से वहां पहुंच जाता है । मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के बारे में भी हमलोग बतला दें कि अब तक 72153 योजना का कार्य पूर्ण हो गया है और 12345 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । ये सब हमने आपको बतलाया इसलिए हमने अध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त में ये सारी बातें आपके समक्ष रखी है और इसके साथ-साथ हम आग्रह करेंगे कि हमारा ये जो सूची है और जो अन्य है, इसको इस बजट के भाषण का पार्ट बना दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ हम सदन से अपील करेंगे कि जल संसाधन विभाग के अनुदान मांग पर सहमति देने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंहः   अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्षः   आप अध्यक्ष महोदय की बात सुन कहां रहे हैं । सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । माननीय मंत्री जी ने जो लिखित दस्तावेज अपने वक्तव्य के रूप में दिया है, वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-27/मधुप/08.03.2017

अध्यक्ष :   प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मॉंग 10 रूपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष :   अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि

''जल संसाधन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 34,97,38,14,000/- (चौंतीस अरब संतानवे करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मॉंग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष :   माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-08 मार्च, 2018 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 16 (सोलह) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई ।)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

....

परिशिष्ट

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के बजट भाषण हेतु सामग्री

(वर्ष 2018–2019)

विभाग का कार्यकलाप (Function of the Department)

जल संसाधन विभाग के मुख्य कार्य के अर्न्तगत राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन एवं ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करना है।

राज्य के चहुँमुखी विकास हेतु यदि किसी एक क्षेत्र का विकास किया जाना अति आवश्यक है तो वह सिंचाई प्रक्षेत्र का विकास किया जाना है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अर्न्तगत राज्य में Ultmimate Irrigation Potential 53.53 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्व अबतक 29.91 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 में 43.571 हजार हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन भी किया गया है।

सिंचाई के अतिरिक्त बाढ़ एवं जल निस्सरण का कार्य विभाग का मुख्य दायित्व है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर है। अबतक 3805 किलोमीटर तटबंध का निर्माण कर कुल 40.19 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की जा सकी है। इसी प्रकार राज्य में लगभग 9.41 लाख हेक्टेयर जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें से 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त करना आर्थिक दृष्टि कोण से लाभप्रद नहीं है। अबतक 1.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया जा चुका है। वर्ष 2018–19 में 62.00 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त करने का कार्यक्रम है।

बाढ़ 2017

- बाढ़ 2017 में 11 अगस्त से 14 अगस्त की अवधि में नेपाल भाग के 7 रेन गेज स्टेशनों पर 10 बार Heavy Rainfall (144 से 244 mm तक वर्षापात्) एवं 2 बार Extremely Heavy Rainfall (244 mm से ज्यादा वर्षापात्) तथा 10 अगस्त से 14 अगस्त की अवधि में उत्तर पूर्वी एवं उत्तर बिहार में अवस्थित 61 रेन गेज स्टेशनों पर 58 बार

Heavy Rainfall एवं 18 बार Extremely Heavy Rainfall हुआ। नेपाल भाग में 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त एवं 14 अगस्त को क्रमशः 511 एम.एम., 585 एम.एम., 1252 एम.एम एवं 148 एम.एम. Cumulative Rainfall हुआ। उत्तर पूर्वी एवं उत्तर बिहार में 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त एवं 14 अगस्त को क्रमशः 1462 एम.एम., 3321 एम.एम., 5834 एम.एम, 11635 एम.एम. एवं 867 एम.एम. Cumulative Rainfall हुआ। सीमित अवधि में अत्यधिक वर्षापात् के कारण नेपाल से बिहार आने वाली सभी नदियों यथा मेची, कनकई, परमान, महानन्दा, डॉक, सौरा, नून, गंडक, कोशी, भूतही बलान, कमला बलान, बागमती, बूढ़ी गंडक एवं अधवारा समूह इत्यादि नदियों में एक ही साथ अप्रत्याशित जलश्राव प्रवाहित हुआ। फलस्वरूप नेपाल से बिहार आने वाली कई नदियों मुख्यतः गंडक नदी में दिनांक–13.08.2017 को अधिकतम जलश्राव 5,24,500 क्यूसेक, कोशी नदी में दिनांक–12.08.2017 को अधिकतम जलश्राव 2,80,225 क्यूसेक प्रवाहित हुआ।

- प्रमुख नदियों में से **गंडक** नदी में 2.00 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 07 दिनों तक, 1.50 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 16 दिनों तक एवं 1.0 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 45 दिनों तक तथा **कोशी** नदी में 2.00 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 10 दिनों तक, 1.50 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 37 दिनों तक एवं 1.0 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 85 दिनों तक प्रवाहित हुआ है। इस वर्ष सोन नदी में दिनांक–27.07. 2017 को अधिकतम जलश्राव 3,65,195 क्यूसेक प्रवाहित हुआ।
- गौरतलब है कि इस वर्ष वैसी नदियों में भी काफी जलश्राव आया, जिन नदियों में विगत 25 वर्षों में काफी कम जलश्राव प्रवाहित हुआ। दिनांक–11.08.2017 से दिनांक–14. 08.2017 तक नेपाल भाग में अत्यधिक वर्षापात के कारण कोशी एवं अन्य सहायक नदियों यथा महुली, तिलयुगा, पाँची, बिहुल, भूतही बलान इत्यादि नदियों में अप्रत्याशित जलश्राव आया। उल्लेखनीय है कि दिनांक–11.08.2017 से दिनांक–14.08.2017 तक लगातार 2.50 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव कोशी नदी पर वीरपुर स्थित बराज से प्रवाहित हुआ। इस बराज के डाउन–स्ट्रीम में कोशी नदी की अन्य सहायक नदियाँ यथा तिलयुगा, पाँची, बिहुल, भुतही बलान इत्यादि मिलती है। इन सहायक नदियों में भी अप्रत्याशित जलश्राव आया। कोशी नदी की उक्त सहायक नदियों में आये अत्यधिक जलश्राव के परिप्रेक्ष्य में

अनुमान है कि कोशी नदी में 5–6 दिनों तक लगभग 3.50 से 4.00 लाख क्यूसेक जलश्राव प्रवाहित हुआ, जिस कारण तटबंधों पर अत्यधिक दबाव रहा। कुछ स्थलों पर Seepage की स्थिति भी थी। आवश्यक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर तटबंधों/स्थलों को सुरक्षित रखा गया

- बाढ़ 2017 में नेपाल के साथ–साथ बिहार में कई स्थलों पर यथा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं पश्चिमी चम्पारण जिलों में हुई अत्यधिक बारिश के कारण कनकई, परमान, डॉक, सौरा, नून, भूतही बलान, कमला बलान, लालबेकिया, बागमती, बूढ़ी गंडक एवं अधवारा समूह की नदियों के जलश्राव में और वृद्धि हुई।

- सीमित अवधि में नेपाल एवं बिहार भाग में अत्यधिक वर्षापात के कारण कोशी नदी के बसुआ स्थल पर दिनांक–13.08.2017 को वर्ष 2010 का एच.एफ.एल. 49.17 मीटर को पार कर 49.20 मीटर, गंडक नदी के डुमरिया घाट स्थल पर दिनांक–17.08.2017 को वर्ष 2014 का एच.एफ.एल. 63.60 मीटर को पार कर 64.10 मीटर, बागमती नदी के ढ़ेंग स्थल पर दिनांक–14.08.2017 को वर्ष 2014 का एच.एफ.एल. 72.34 मीटर को पार कर 72.60 मीटर, लालबेकिया नदी के गोआबारी स्थल पर दिनांक–13.08.2017 को वर्ष 1992 का एच.एफ.एल. 72.84 मीटर को पार कर 73.80 मीटर तथा महानन्दा नदी के डेंगराघाट स्थल पर दिनांक–14.08.2017 को वर्ष 1968 का एच.एफ.एल. 38.09 मीटर को पार कर 38.16 मीटर एवं एवं झावा स्थल पर वर्ष 1987 का एच.एफ.एल. 33.51 मीटर को पार कर 33.90 मीटर का नया एच.एफ.एल. दर्ज हुआ।

- बाढ़ 2017 में 11 अगस्त से 14 अगस्त की अवधि में नेपाल भाग में तथा 10 अगस्त से 14 अगस्त की अवधि में उत्तर पूर्वी एवं उत्तर बिहार में अचानक अत्यधिक वर्षापात् के फलस्वरूप कई नदियों में आये अत्यधिक जलश्राव के कारण तटबंध कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ।

- मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, बेगूसराय एवं खगड़िया में स्थित बूढ़ी गंडक नदी पर निर्मित तटबंधों के विभिन्न स्थलों पर लगातार रिसाव (सीपेज) की समस्या उत्पन्न हुई, जिसे आवश्यक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर तटबंध को सुरक्षित रखा गया।

महानन्दा नदी पर निर्मित बेलगाछी–झौआ महानन्दा दायाँ तटबंध, झौआ–लाभा महानन्दा दायाँ तटबंध, बागडोब–झौआ महानन्दा बायाँ तटबंध, झौआ–दिल्ली दिवानगंज तटबंध एवं गाछपाडा मौजाबारी बाँध कतिपय बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त हुआ। पश्चिमी कनकई नदी पर अवस्थित अररिया जिला के प्रखंड जोकीहाट अन्तर्गत मजकुरी जहानपुर तटबंध एवं पूर्णिया जिला के जलालगढ़ प्रखंड अन्तर्गत परमान नदी पर निर्मित खाताहाट तटबंध कतिपय बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त स्थलों पर युद्ध स्तर पर अहर्निश बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर मरम्मति कर ली गई है एवं इसके पुनर्स्थापन का कार्य बाढ़ 2018 पूर्व 15 मई 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

गंडक नदी में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत भितहा प्रखंड में स्थित पी0पी0 तटबंध के अन्तर्गत चन्द्रपुर रिटायर लाईन, गोपालगंज जिलान्तर्गत सलेमपुर छरकी, सारण तटबंध, बन्धौली–शीतलपुर–फैजुलापुर जमींदारी बाँध एवं बैकुण्ठपुर रिटायर लाईन कुछ बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त हुआ। अहर्निश बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर तटबंध के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति बाढ़ अवधि में कर ली गई है एवं इसके पुनर्स्थापन का कार्य बाढ़ 2018 पूर्व 15 मई 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

गंडक नदी के बायें किनारे प्रखंड बगहा–1 में मिर्जाटोली के पास नदी के अत्यधिक दबाव के कारण दिवा–रात्रि अहर्निश बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया।

लालबेकिया नदी पर निर्मित पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढ़ाका प्रखंड के बलुआ ग्राम के निकट, दायाँ मार्जिनल बाँध, दायाँ एफलक्स बाँध फुलवरिया ग्राम एवं ग्राम सपही के निकट तथा बैरगेनीया रिंग बाँध मसहा नरोत्तम एवं बलुआ ग्राम के निकट क्षतिग्रस्त हुआ। उक्त क्षतिग्रस्त स्थलों की मरम्मति बाढ़ अवधि में करा ली गई एवं इसके पुनर्स्थापन का कार्य बाढ़ 2018 पूर्व 15 मई 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

बागमती नदी के बायाँ तटबंध कतिपय बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त हुआ। उक्त क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति बाढ़ अवधि में करा ली गई एवं इसके पुनर्स्थापन का कार्य बाढ़ 2018 पूर्व 15 मई 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

अधवारा नदी पर निर्माणाधीन बायें तटबंध एवं दायें तटबंध में क्रमशः 210 मीटर एवं 295 मीटर की लम्बाई में तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ। उक्त दोनों क्षतिग्रस्त स्थलों की मरम्मति

बाढ़ अवधि में करा ली गई एवं इसके पुनर्स्थापन का कार्य बाढ़ 2018 पूर्व 15 मई 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

दरभंगा जिलान्तर्गत कमला बलान दॉया तटबंध घनश्यामपुर प्रखंड तथा तारडीह प्रखंड में क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त बाँध की मरम्मति बाढ़ अवधि में करा ली गई एवं इसके पुनर्स्थापन का कार्य बाढ़ 2018 पूर्व 15 मई 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

- तटबंधों के सुरक्षार्थ विभाग द्वारा तटबंधों के प्रत्येक किलोमीटर पर होमगार्ड की तैनाती की जाती है। इसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं कही पर नदी पर निर्मित तटबंधों एवं इसके संरचनाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। बाढ़ 2017 में बूढ़ी गंडक नदी के दायें तटबंध के कि.मी. 8.00 से 9.00 के बीच ग्राम रजवाड़ा प्रखंड–मुशहरी, जिला–मुजफ्फरपुर में निर्मित एन्टी फ्लड स्लूईस को असामाजिक तत्वों द्वारा कन्ट्री साईड में स्थित तालाबों, मनो में पानी भरने हेतु एन्टी फ्लड स्लूईस के गेटों को खोल दिया गया जिस कारण दिनांक–20.08.2017 को उक्त एन्टी फ्लड ध्वस्त हो गया तथा तटबंध भी 60 मीटर की लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त स्थल की मरम्मति बाढ़ अवधि में ही कर ली गई एवं इसके पुनर्स्थापन का कार्य बाढ़ 2018 पूर्व करा ली जायगी।

- अत्यधिक जलश्राव प्रवाहित होने, कई नदियों में उच्चतम जलस्तर दर्ज होने के बावजूद बाढ़ पूर्व विभाग की अच्छी तैयारी मुख्यालय स्तर पर सघन प्रबोधन विभागीय अभियंताओं की मुस्तैदी एवं तत्परता के कारण कुछ ही स्थलों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ। अधिकतर तटबंध सुरक्षित रहा।

- **समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा स्वयं लगातार दो सप्ताह तक कैंप कर उत्पन्न स्थिति का जायजा लेकर बचाव के उपायों का सघन प्रबोधन दिवा–रात्रि किया गया, फलस्वरूप समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी पर निर्मित लगभग 400 किलोमीटर तथा बागमती नदी पर निर्मित लगभग 200 किलोमीटर तटबंध को सुरक्षित रखा जा सका।**

- दिवा–रात्रि अहर्निश बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर आई बाढ़ से अतिसंवेदनशील कई शहरों यथा पूर्णिया, बगहा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, रोसड़ा, गोपालगंज इत्यादि को बाढ़ से सुरक्षित रखा गया है।

- पूरी बाढ़ अवधि में मुख्यालय द्वारा बाढ़ में संलग्न अभियंताओं के कर्तव्य निर्वहन की सघन मोनिटरिंग की जा रही थी। जिस क्रम में पाया गया कि कुछ अभियंताओं के द्वारा बाढ़ अवधि मे कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई। बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के लिए सभी सुविधाएँ यथा प्रयाप्त मात्रा में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों इत्यादि की उपलब्धता रहने के बावजूद कतिपय अभियंताओं के स्तर से लापरवाही बरतने एवं उनके स्तर से चूक के कारण तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ। वैसे अभियंताओं को चिन्हित कर विभाग के द्वारा उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की गई है ताकि कार्य–अनुशासन का माहौल कायम रहे तथा आगे कर्तव्यों के प्रति लापरवाही की घटना न हो। इस क्रम में जिम्मेवार मुख्य अभियंता से कनीय अभियंता तक कुल 19 अदद अभियंताओं को निलंबित किया गया है तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

<u>बाढ़ 2018 के पूर्व की तैयारी</u>

- बाढ़ 2017 में नदियों के व्यवहार, आक्राम्यता के आलोक में संवेदनशील स्थलों की पहचान कर तथा क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षात्मक संरचनाओं के पुनर्स्थापन हेतु रू0 1562.28 करोड़ की लागत से 421 अदद बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई है। उक्त 421 अदद योजनाओं के अंतर्गत रू0 605.03 करोड़ की लागत से 342 अदद राज्य योजना के अंतर्गत, रू0 168.72 करोड़ की लागत से 12 अदद नाबार्ड सम्पोषित योजना, रू0 471.91 करोड़ की लागत से 8 अदद बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम योजना, 258.62 करोड़ की लागत से 44 अदद आपदा प्रबंधन से प्राप्त निधि के अंतर्गत योजना तथा रू0 58.00 करोड़ की लागत से 15 अदद आर.एम.ए.डब्लू.बी.ए. के तहत योजना सम्मिलित है।

- उक्त 421 अदद योजनाओं में से 41 अदद योजनाओं का गंगा नदी पर, 37 अदद योजनाओं का गंडक नदी पर, 7 अदद योजनाओं का घाघरा नदी पर, 52 अदद योजनाओं का बूढ़ी गंडक नदी पर, 29 अदद योजनाओं का बागमती नदी पर, 2 अदद योजनाओं का लालबेकिया नदी पर, 26 अदद योजनाओं का महानन्दा नदी पर, 83 अदद योजनाओं का कोशी नदी पर, 20 अदद योजनाओं का कमला बलान नदी पर, 7 अदद योजनाओं का भूतही बलान नदी पर, 6 अदद योजनाओं का सोन नदी पर, 13 अदद योजनाओं का पुनपुन नदी पर, 14 अदद योजनाओं का सिकरहना नदी पर, 3 अदद योजनाओं का

परमान नदी पर एवं 81 अदद योजनाओं का अन्य नदियों पर कार्यान्वयन कराया जा रहा है।

- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम योजनाओं को छोड़कर शेष 413 अदद योजनाओं को बाढ़ 2018 पूर्व 15 मई 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है :–
  - ➢ अतिआक्राम्य स्थलों पर नदी के दबाव को कम करने के उद्देश्य से नदी के केन्द्रीय बहाव को सुनिश्चित करने निमित चैनल का सक्रियण एवं ड्रेजिंग कार्य।
  - ➢ पाईपिंग की संभावना वालें स्थल पर विशेष ध्यान।
  - ➢ मशीन निर्मित जी.आई. वायर क्रेट एवं नये सिमेंट बैग का उपयोग।
- **चूहे आदि जानवरों से तटबंधों को हो रहे नुकसान से बचाव**

बाढ़ 2017 अवधि में तटबन्धों में व्यापक रूप से चूहों, लोमड़ियों, शाहिल आदि जानवरों द्वारा सुराख बनायें जाने के कारण आये खतरे से विभाग द्वारा अथक प्रयास कर तटबंधों को सुरक्षित रखा गया ।

इसी क्रम में विभाग द्वारा यह महसूस किया गया कि वर्ष दर वर्ष इन जानवरों द्वारा मिट्टी से बने तटबन्धों में सुराख किये जाने पर किस प्रकार प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके, इस पर मंथन किया जाना आवश्यक है । इस विषय को गम्भीरता से समझने की जरूरत है। इस समस्या को प्रायः छोटा समझा जाता है एवं भ्रम की स्थिति में अफवाह का रूप ले लेता है जबकि वास्तविकता बिल्कुल विपरीत होती है।

इस संबंध में भारत मानक संस्थान (Bureau of Indian Standard) के नदी तटबंध के निर्माण एवं सम्पोषण पर मार्गदर्शी सिद्धांत से संदर्भित वर्ष 1995 के कोड–11532 की कंडिका–3.1.1.4 के अवलोकन से इस समस्या की वास्तविकता पता चल जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि "Rodents and other animals make holes, cavities and tunnels through and under embankments. These are sources of danger causing leakage and excessive seepages which may give rise to serious breaches during flood period. Such holes should be

carefully located, examined, provided with an inverted filter, filled with earth and rammed. Alternatively such holes should be filled with well rammed stiff clay. "

संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलाराडो राज्य के डैम सेफ्टी मैनुअल में भी "Repairing Rodent Damage" शीर्ष से एक विस्तृत दिशा निर्देश कृंतको द्वारा किये गये क्षति निवारण हेतु उल्लेख है। इससे इस समस्या की विकरालता स्पष्ट होती है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखकर हाल ही में विभाग द्वारा पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग तथा कृषि विभाग के विशेषज्ञों के साथ चूहों, लोमड़ियाँ, शाहिलों जैसे कृतंको (Rodents) से तटबंधों की सुरक्षा करने की दिशा में सार्थक पहल के उद्देश्य से बैठक की गयी। विशेषज्ञों द्वारा सुझाव दिया गया कि

- सबसे पहले, तटबंधों के उन स्थानों को चिन्हित किया जाय जहाँ तटबंध पर या इसके नजदीक बसावट हो तथा कृतकों द्वारा छेद बनाया गया हो।
- इन चिन्हित स्थानों पर अकवन तथा धाभी घास लगाया जाए जो कृतकों (Rodents) के प्रतिकर्षक के रूप में कार्य करेगें।
- साथ ही चिन्हित स्थानों पर चूहों के बिलों में अल्यूमिनियम फॉस्फाईड के टिकियों एवं फॉरेट 10जी. का उपयोग किया जाय।

उपर्युक्त उपायों पर विभाग द्वारा बाढ़ 2018 अवधि के पूर्व आवश्यक कार्रवाई कर लिये जाने का कार्यक्रम है।

- **सीतामढ़ी में तीन योजनाओं के शिलान्यास**

सीतामढ़ी जिला में स्थित निवासियों के चिरप्रतीक्षित योजनाएँ, जो काफी लाभप्रद, जनोपयोगी एवं विकासोन्मुखी है, यथा **लखनदेई नदी की पुरानी धार का पुर्नस्थापन कार्य, मनुषमारा जल निस्सरण योजना** तथा रातो नदी पर **नो– मेन्स लैंड से निशा रोड तक तटबंध निर्माण कार्य** योजनाओं का शिलान्यास दिनांक 15 फरवरी, 2018 को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलो से किया गया ।

यह राज्य की कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में सिंचित भूमि में बृद्धि तथा बाढ़ प्रवण और जल जमाव वाले क्षेत्रों के जन मानस को राहत दिलाने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग द्वारा निरंतर प्रयास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु

उपर्युक्त तीनों योजनाओं का शिलान्यास कर समय सीमा के अन्दर इन्हे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस दिशा में **रातो नदी पर नो मेन्स लौंड से निशा रोड तक तटबंध निर्माण कार्य** प्रस्तावित है, जिसमें रातो नदी बायां तटबंध, रातो नदी दांया तटबंध कार्य के साथ ही तटबंधों के उपर ब्रीक सोलिंग कार्य, 8 अदद एण्टी फ्लड स्लूइस निर्माण कार्य तथा 6 अदद ढ़ाला निर्माण कार्य किया जाना है। इसे **31 मार्च, 2019 तक** पूर्ण किया जाना है। इस योजना से 6000 हे० क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान के साथ ही सीतामढ़ी जिले के सुरसंड, चोरौत एवं पुपरी प्रखंडों के लगभग 50000 की आबादी लाभान्वित होगी।

इसी प्रकार **लखनदेई नदी की पुरानी धार का पुर्नस्थापन** कार्य भी प्रस्तावित है, जिसमें लिंक चैनल, अवरोधक कार्य, रि–सेक्सनिंग कार्य तथा 2 अदद द्विपथीय सेतु निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसका निर्माण **31 मार्च, 2019 तक** पूर्ण कर लिया जाना है। इस योजना से सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा, बथनाहा, सीतामढ़ी एवं रून्नीसैदपुर प्रखंडों के 2540 हे० क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान कर लगभग 10000 आबादी को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया जाना संभव हो सकेगा।

उसी प्रकार **मनुषमारा जल निस्सरण योजना** के द्वारा सीतामढ़ी जिले के बेलसंड एवं रून्नीसैदपुर प्रखंडों में 1600 हे० भू–भाग को जल जमाव से मुक्त करने के साथ 18.05 कि०मी० लम्बी जल निकास चैनल के नवीकरण कार्य, एक अदद एन्टी फ्लड स्लूईस, 13.27 कि०मी० प्राकृतिक स्पील चैनल का रिसेक्सनिंग कार्य, पुराने स्पील चैनल के 4.787 कि०मी० रिसेक्सनिंग कार्य तथा 2 अदद द्विपथीय सेतु निर्माण कार्य किया जाना है। इसकी योजना लागत राशि **रु० 1425.53 लाख रूपये** तथा कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि **15 मई, 2018** है।

हायाघाट से करांचीन–
करांचीन से बदलाघाट
बदलाघाट से नगरपाड़ा तक–
[illegible]

- **बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–III(a)**

बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–III(a) के तहत बागमती दायाँ तटबंध के कि.मी. 123.52 से कि.मी. 165.52 (हायाघाट–करार्चीन तटबंध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 42. 00) एवं बागमती दायाँ तटबंध के कि.मी. 198.52 से कि.मी. 264.02 (करार्चीन–बदलाघाट तटबंध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 47.50 एवं बदलाघाट–नगरपाड़ा तटबंध के कि.मी. 0.00

से कि.मी. 18.00) के बीच उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य तथा 17 अदद् स्लूईस, 98 अदद् ढाला एवं 107 अदद् टर्निंग प्लेटफॉर्म के निर्माण कार्य प्रस्तावित है। कार्य की प्राक्कलित राशि ₹ 94357.50 लाख है।

बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के अधीन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के उपक्रम एच.एस.सी.एल. के साथ किये गये एम.ओ.यू. को सीमित करते हुए बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–III(a) का कार्य प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित कर कराये जाने हेतु सरकार के निर्णय के उपरान्त उक्त कार्य हेतु आमंत्रित निविदा का निष्पादन करते हुए कार्य आवंटित किया जा चुका है। वर्त्तमान में कार्य का कार्यान्वयन प्रारंभ होने की स्थिति में है। उक्त कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि– 31 मार्च 2019 है।

इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् दरभंगा, समस्तीपुर एवं खगड़िया जिलों के 3.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा 12.00 लाख की आबादी को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

- **महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना**

  - महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना का सैद्धान्तिक तकनीकी अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार से रू0 603.88 करोड़ के लिये प्राप्त है जिसमें महानन्दा एवं महानन्दा बेसिन की नदियों तथा मेची, कनकई, बकरा एवं परमान पर कुल 1195.871 कि0मी0 नये तटबंध का निर्माण एवं 95.20 कि0मी0 पुराने तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना है । उक्त सभी कार्यों को 5 चरणों में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
  - महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–I के अन्तर्गत महानन्दा नदी पर कुल 95. 40 कि0मी0 की लम्बाई में तटबंध का सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
  - महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II के तहत् महानन्दा बेसिन के अन्तर्गत कुल 199.95 कि0मी0 लम्बाई में नये तटबंध का निर्माण किये जाने का कार्यक्रम है।

    उक्त योजना का तकनीकी एप्रेजल गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार से प्राप्त है तथा टेक्नो–इकोनोमिक क्लीयरेंस हेतु जल संसाधन

मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को योजना समर्पित है। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से टेक्नो–इकोनोमिक क्लीयरेंस प्राप्त होने के उपरान्त इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

➢ महानन्दा बाढ़ प्रबंध योजना फेज–III, फेज–IV एवं फेज–V का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

- **बाढ़ प्रबंधन के गैर–संरचनात्मक उपाय**

➢ जल प्रबंधन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक यथा रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मैथेमेटिकल मॉडलिंग, तटबंध परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली आदि का उपयोग विभाग के द्वारा किया जा रहा है एवं इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

➢ **सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस** के तहत **गणितीय प्रतिमान केन्द्र** (Mathematical Modelling Center) का कार्य पूरा कर इसका उद्घाटन 10 फरवरी, 2018 को माननीय मुख्य मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगें–

क) गणितीय प्रतिमान केन्द्र जल संसाधन क्षेत्र से संबंधित Modeling Software का बेहतर एवं वैज्ञानिक तरीके के उपयोग से योजनाओं के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन हेतु सुझाव देगी।

ख) यह केन्द्र बाढ़ एवं सिंचाई प्रबंधन के निमित्त विभाग को परामर्श देगा ताकि निर्णय लेने में आसानी हो।

ग) बिहार के नदियों से संबंधित Real Time Data Acquisition तथा इसका उपयोग बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली तथा सेटेलाइट इमेजरी के आधार पर नदियों के Braiding & Meandering वर्त्ताव की जानकारी प्राप्त करते हुए आक्राम्य स्थल की सूचना मुख्यालय/क्षेत्रीय पदाधिकारी को इस केन्द्र द्वारा दिया जाएगा। इससे बाढ़ पूर्व, कटाव निरोधक कार्य के चयन में प्राथमिकता तय किये जाने में सहायता मिलेगी।

- **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** के तहत वीरपुर वीरपुर (सुपौल) में **भौतिक प्रतिमान केन्द्र** (Physical Modelling Center) का स्थापन प्रस्तावित है। जिसका विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर) तैयार हो चुका है। इसकी लागत राशि रूपये 10893.00 लाख है। इस केन्द्र के लिए प्रस्तावित जमीन चिन्हित कर ली गयी है एवं इसके लिए सी०डब्लू०पी०आर०एस०, पुणे के सेवा निवृत्त विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। इस केन्द्र का उद्घाटन नवम्बर 2018 में करने का लक्ष्य है।

  कोशी नदी के बराज के अपस्ट्रीम में बराहक्षेत्र तथा डाउनस्ट्रीम में कोपड़िया तक बराज मॉडल तथा चार अदद आक्रम्य स्थलों का भौतिक मॉडलिंग हेतु मॉडल ट्रे का प्रावधान विस्तृत योजना प्रतिवेदन में है।

- **नेशनल हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट** के तहत वर्ष 2018–19 में पाँच बेसीनों (गंडक, महानन्दा, सोन, पुनपुन एवं किउल–हरोहर) तथा अठारह जलाशयों (चंदन, बदुआ, फुलवरिया, अपर किउल, दुर्गावती, खड़गपुर झील, कोहिरा, नागी, अमृती, श्रीखंडी, कोल महादेव, मोरवे, कैलाश घाटी, नकटी, बेलहरना, आंजन, ओढ़नी एवं विलासी) में Hydromet instruments का आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन का कार्य, गंडक बेसीन का तटबंध परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का कार्य, जल ज्ञान केन्द्र निर्माण का कार्य आदि पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत जल प्रबंधन एवं जलाशय प्रबंधन के लिए डाटा संग्रह एवं इसके बेहतर उपयोग हेतु क्षमता एवं साधन का सृजन करना है।

- **गंगा की अविरलता**

बिहार राज्य में बाढ़ का मुख्य कारण गंगा एवं अन्य नदियों में अधिक सिल्ट का जमाव होना है। वास्तव में गंगा नदी की धारा की अविरलता समाप्त हो गयी है। अविरलता के बिना निर्मलता की कल्पना अधूरा है। इस अविरलता के न रहने का मुख्य कारण ऊपरी सहघाटी राज्यों द्वारा गंगा जल के अंधाधून जल दोहन रहा है। स्थिति इतनी दयनीय है कि चौसा, जहाँ गंगा बिहार राज्य में प्रवेश करता है वहाँ गंगाजल लगभग विलुप्त हो गया है। आज गंगा नदी में बक्सर के नीचे जो

बहाव देखी जा रही है वह बिहार राज्य की गंगा की सहायक नदियो यथा गंडक, सोन, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, महानंदा आदि नदियों का जल है। गंगा नदी की जल की अविरलता के न रहने का दुष्प्रभाव गाद की समस्या के रूप में प्रतिफलित हो रही है, जिसका जीवन्त उदाहरण प्रतिवर्ष गंगा नदी के भिन्न–भिन्न स्थानों पर बन रहे नए–नए HFL से स्पष्ट हो रहा है।

फरक्का बराज के दुष्परिणाम के रूप में गंगा नदी के तल में पटना तक उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। बांगलादेश को जल देने का भारत सरकार का एकरारनामा का अनुपालन बिहार राज्य के गंगा नदी के सहायक नदियों में उपलब्ध जल से किया जा रहा है परन्तु फरक्का बराज के दुष्परिणाम का खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है। समय आ गया है कि फरक्का बराज के उपयोगिता का पुनर्मूल्यांकण हो एवं इस बराज के नकारात्मक प्रतिफल से बिहार राज्य मुक्त हो सके।

गंगा नदी की अविरलता को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से 25–26 फरवरी 2017 को पटना में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं इसी कड़ी में पुनः दिनांक 18–19 मई 2017 को नयी दिल्ली में "गंगा की अविरलता में बाधक गाद–समस्या एवं समाधान" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। सम्मेलन में इस विषय के विद्वजनों, विशेषज्ञों एवं जन प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया तथा गंगा की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुये इसके पुनर्स्थापन एवं फरक्का बराज के पुनर्मूल्यांकण हेतु शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता बताई गयी।

सिंचाई क्षमता का सृजन

- वृहद एवं मध्यम सिंचाई के माध्यम से राज्य में Ultmimate Irrigation Potential 53.53 लाख हेक्टेयर है। इसके विरूद्ध अब तक 29.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकी है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुंगेर जिला अन्तर्गत पहाड़ियों से निःसृत झरनों पर आधारित सिंचाई योजना, जहानाबाद जिला अन्तर्गत छरियारी वीयर योजना, चानकेन सिंचाई योजना, दनवार झील सिंचाई योजना, पूर्वी गंडक नहर प्रणाली फेज–II–ई0आर0एम0, प0 कोसी नहर परियोजना आदि के क्रियान्वयन से कुल 21.90 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।
- वर्ष 2017–18 में कुल 4 अदद् योजनाओं यथा उदेरास्थान बराज योजना, नसरतपुर वीयर योजना, कचनामा वीयर योजना एवं बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना को पूर्ण कर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित किया गया। इन योजनाओं से पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, औरंगाबाद, गया और भागलपुर जिले के किसानों को कुल 70,743 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है।
- वर्ष 2018–19 में बिहुल नदी पर वीयर योजना, दरभंगा जिला में गरौल वीयर योजना, बघेला घाट सिंचाई योजना, टिकमा सिंचाई योजना, पूवी गंडक नहर प्रणाली फेज–II–ई0आर0एम0, प0 गंडक नहर प्रणाली–ई0आर0एम0, उत्तर कोयल जलाशय योजना, बटाने जलाशय योजना, कुन्दर बराज योजना, कुण्डघाट जलाशय योजना, सैंधवा चेक डैम, ढाढर डाईवर्सन योजना, बटेश्वरस्थान पम्प नहर योजना, दुर्गावती जलाशय योजना, बलवा बराज योजना, मंडई वीयर योजना आदि के क्रियान्वयन से 188.128 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है।

ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में सोन नहर प्रणाली के अन्तर्गत अमरा वितरणी, सैदपुर उप वितरणी, पटना मुख्य नहर के विभिन्न वितरणियों, अपर किउल रिवर वैली सिंचाई योजना, उदेरास्थान बराज योजना, अपर मोरहर सिंचाई योजना, चौसा गंगा पम्प नहर योजना, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली–ई0आर0एम0 आदि के क्रियान्वयन से 43.571 हजार हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया गया है।
- बाँका जिला के बदुआ जलाशय योजना के अन्तर्गत शंभुगंज शाखा नहर, रजौल उपवितरणी एवं गौरीपुर उपवितरणी के पुनर्स्थापन कार्य को पूरा कर इसका भी उदघाटन किया गया जिससे बेलहर एवं फूलीडुमर प्रखण्ड के किसानों को सिंचाई की सुविधा पुनः बहाल हो गई है।
- वर्ष 2018–19 में कुल 274.257 हजार हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अन्तर्गत चन्दन जलाशय योजना, बदुआ जलाशय योजना, अपर मोरहर सिंचाई योजना, दरियापुर वीयर योजना, बटाने जलाशय योजना एवं गत वर्ष अप्रत्याशित वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली तथा पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य किया जाना है।

- **वर्ष 2017 में रिकार्ड खरीफ सिंचाई उपलब्धि**

नई योजनाओं के निर्माण के साथ–साथ नहरों के संचालन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाकर अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सके। वर्ष 2016–17 में कुल 26.72 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो सकी थी जिसमें खरीफ में 19.31, रब्बी में 7.13 एवं गरमा में 0.28 लाख हेक्टेयर था। वर्ष 2017–18 में 19. 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई की उपलब्धि प्राप्त की गई है, जो गतवर्ष से अधिक है। इस वर्ष रब्बी की सिंचाई अभी जारी है। उम्मीद है कि वर्ष 2017–18 के अन्त तक कुल 27.00 लाख हेक्टेयर से अधिक की रिकार्ड सिंचाई की उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी।

सिंचाई की महत्वपूर्ण योजनाएँ

- **कुंडघाट जलाशय योजना :–**

इस योजना में जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखंड स्थित बहुवार नदी पर लछुवार गांव में कुंडघाट के नजदीक लगभग 40 मी0 ऊँचाई तथा स्पीलवे के साथ लगभग 354 मी0 की लंबाई में मिट्टी बांध का निर्माण किया जा रहा है जिससे 4030 एकड़ खरीफ तथा 1000 एकड़ रबी सिंचाई करना प्रस्तावित है। इसकी द्वितीय प्रशासनिक स्वीकृति कुल रुपए 55.7152 करोड़ का प्राप्त है। इसका निर्माण पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में 2014 से बंद था जो वर्ष 2015 में प्राप्त होने के पश्चात् डैम का कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन रुपया 185.21 करोड़ का फेज–I के लिए तैयार किया गया है। इसके सफल कार्यान्वयन के पश्चात् Spillway Gate, वितरण प्रणाली एवं अन्य अव्ययों के लिए अलग से प्रावधान किया जायेगा। फेज–I के प्राक्कलन में बढ़ोतरी का मुख्य कारण रूपांकण में परिवर्तन, करटेन ग्राउटिंग, इन्सट्रूमेंटेशन, विद्युतीकरण इत्यादि कार्य हो रहा है।

- **बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर परियोजना :–**

यह वर्ष 1977 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है, जो समयान्तराल में उचित ध्यान न दिये जाने के कारण लंबित रह गया था।

उल्लेखनीय है कि इस योजना पर कार्य मद में मार्च, 2005 तक रु० 21.32 करोड़ की राशि व्यय किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः नहर का कार्य सम्मिलित है। वर्ष 2005 मार्च से अबतक इस येाजना पर कुल रु० 358.53 करोड़ की राशि खर्च किया गया है, जिसमें मुख्यतः फेज–I एवं II के पम्प हाउस के असैनिक तथा यांत्रिक कार्य सम्मिलित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2005 के पूर्व कराए गए मुख्य नहर के निर्माण के लिए वर्त्तमान व्यवस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

दिनांक 19.09.2017 को ट्रायल रन के दौरान सभी पम्पों को चलाकर परीक्षण किया गया एवं नहर में जलश्राव प्रवाहित किया गया। इस परीक्षण के दौरान 5.35 आर०डी० पर एन०टी०पी०सी० द्वारा निर्मित अंडरपास के ऊपर नहर का बायां बैंक क्षतिग्रस्त हो गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्य नहर का निर्माण वर्ष 1985 में हुआ है। इसके 5.35 आर०डी० पर एन०टी०पी०सी० द्वारा आवागमन हेतु अंडरपास निर्मित है। इस अंडरपास के निर्माण हेतु 1987 में मुख्य अभियंता, भागलपुर से एन०टी०पी०सी० द्वारा तैयार किए गए नक्शे पर अनुमोदन लिया गया है। मुख्य अभियंता, भागलपुर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन में कतिपय शर्ते रखी गई थी। इस अंडरपास का निर्माण एन०टी०पी०सी० द्वारा 1990–92 तक की अवधि में कराया गया, परन्तु दिए गए शर्त का अनुपालन नहीं किया गया, जिसपर तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शिवनारायणपुर द्वारा पत्रांक 521 दिनांक 03.05.2005 से आपत्ति दर्ज किया गया था।

एन०टी०पी०सी० ने लिखित तौर पर अंडरपास निर्माण में की गई अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अनुमोदित नक्शे के अनुसार मरम्मति का कार्य अपने व्यय पर करा दिया गया है।

15 फरवरी, 2018 को माननीय मुख्य मंत्री के कर कमलों द्वारा इस पम्प नहर योजना का उद्घाटन किया गया।

- **इन्द्रपुरी जलाशय योजना**

सोन नदी पर स्थित इन्द्रपुरी बराज से निःसृत सोन नहर प्रणाली में ससमय जल उपलब्ध कराने के साथ–साथ लगभग 400 मेगावॉट जल विद्युत उत्पादन हेतु इन्द्रपुरी जलाशय योजना का निर्माण प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि सोन नदी पर स्थित इन्द्रपुरी बराज से लगभग 80 कि0मी0 अपस्ट्रीम में मटिऑव (रोहतास) ग्राम के पास प्रस्तावित डैम का डूब क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में पड़ता है।

173 मी० एफ.आर.एल. पर आधारित जलाश्य योजना का डी.पी.आर. एवं योजना वर्ष 1987 से 2004 तक केन्द्रीय जल आयोग में उत्तर प्रदेश से सहमती नहीं मिलने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित रही है। अत्तोगतवा राज्य सरकार के अनुरोध पर इस योजना की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग में दिनांक 10 मई, 2005 एवं दिनांक 09 अगस्त, 2007 को बैठक सम्पन्न हुई। उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सर्वे ऑफ इंडिया से जल स्तर 173 मी0 से 169 मी0 के बीच 1 मी० के अंतराल पर सर्वे ऑफ

इंडिया से कंटूर सर्वे तथा उत्तर प्रदेश स्थित ओबरा जल विद्युत गृह के टेल रेस का सत्यापन कार्य रु० 130.12 लाख के व्यय से सम्पादित कराया गया।

फरवरी, 2015 में सर्वे ऑफ इंडिया से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसके आधार पर इंद्रपुरी जलाशय योजना आधार पर नये सिरे से प्रस्ताव तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग में दिनांक 05.02.2016 को सम्मपन्न बैठक में विचार किया गया है। इस अन्तर्राज्यीय बैठक में इन्द्रपुरी जलाशय का पूर्ण भंडारण स्तर 169.0 मी0 एवं अधिकतम जलस्तर 171.0 मी0 पर विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने पर सहमति बनी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश एवं झारखंड के भी प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इन्द्रपुरी जलाशय योजना के डी0पी0आर0 तैयारी का कार्य रॅडिक कन्सल्टेंट को सौंपा गया है, जिसकी लागत रु0 18.40 करोड़ है। डी0पी0आर0 प्राप्त होने की निर्धारित अवधि फरवरी, 2019 है। तत्पश्चात् इसे स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग को समर्पित किया जाएगा।

- **एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए0 डी0 बी0) से आरा मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली के पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य हेतु स्वीकृति की कार्रवाई**

लगभग 140 वर्ष पूर्व निर्मित सोन नहर प्रणाली के अन्तर्गत आरा मुख्य नहर एवं इसके वितरण प्रणाली में किसानों को अंतिम छोर तक ससमय एवं यथेष्ठ मात्रा में जल उपलब्ध कराने हेतु पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग का कार्य कराने के लिए लगभग 2995 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गयी है।

इस योजना का कार्यान्वयन वाह्य सहायता के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए0 डी0 बी0) से ऋण प्राप्त कर किये जाने का प्रस्ताव है।

इस योजना के समीक्षा हेतु ए0डी0बी0 के श्री अरनॉड कौशियस, प्रधान जल संसाधन विशेषज्ञ के नेतृत्व में Consultation Mission द्वारा दिनांकः 13 – 16 फरवरी 2018 के बीच बिहार का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान उनके द्वारा जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों, जल उपभोक्ता संगठन के अधिकारी एवं कृषकों के साथ

विचार विमर्श के अतिरिक्त सोन बराज, आरा मुख्य नहर एवं कोईलवर वितरणी का स्थल निरीक्षण किया गया । Mission द्वारा योजना को सराहा गया।

इस योजना में आधुनिकीकरण प्रस्ताव समावेश करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के परामर्शी की देख–रेख में योजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। इसके अंतर्गत ADB के द्वारा 28 मार्च से 6 अप्रैल के बीच Field Reconnaissance Mission का भ्रमण प्रस्तावित है।

➢ तत्पश्चात् ए0डी0बी0 द्वारा ऋण स्वीकृति की कार्रवाई होना प्रस्तावित है।

- **टाल विकास योजना**

टाल योजना के जल के बेहतर आर्थिक उपयोग एवं प्रबंधन के लिए विभाग दृढ़संकल्प है। इसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य अवयव 05 अदद Anti Flood Sluice का निर्माण, उत्तरी एवं दक्षिण छोर पर 02 अदद तटबंध का निर्माण, जमींदारी बांधों का उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण, भू–गर्भ जल के साथ सतही जल का सर्वोत्तम आर्थिक उपयोग के साथ 215 प्रतिशत cropping intensity प्राप्त करना, टाल क्षेत्र में उपस्थित जलाशयों को गहरा कर इसमें मछली तथा जलीय उत्पाद को विकसित करना तथा अवस्थित पईनों का डिसिल्टिंग कर ड्रेनेज व्यवस्था को कारगर बनाना है।

बलगुदर घाट तथा खनुआ सोता, डोमना सोता, गायघाट सोता एवं लंगड़ी पईन पर कुल 5 अदद् एण्टी फ्लड स्लूईस (Anti Flood Sluice) के निर्माण हेतु कार्य आवंटित है।

इस योजना के तहत् 4 अदद् बराज, 171 अदद् चेक डैम/वीयर के निर्माण का प्रस्ताव है। उत्तरी छोर पर 54 कि0मी0 की लम्बाई में बलगुदर घाट से बाढ़–सरमेरा रोड तक तटबंध निर्माण तथा दक्षिणी छोर पर अशोक धाम से फतुहा तक 95 कि0मी0 लम्बाई में तटबंध निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अलावे सिंचाई सुविधा बहाल करने हेतु सम्पूर्ण

टाल क्षेत्र में लगभग 20,000 ट्यूबवेल (Tubewell) गाड़ने का भी प्रस्ताव है। साथ ही 52 अदद् टाल क्षेत्र के जलाशयों को गहरा कर मछली पालन किया जाएगा।

पूरे टाल क्षेत्र की विकास की योजना का एक प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष दिनांक 09.11.2017 को दिया गया। उन्होंने निदेश दिया कि इस योजना के संबंध में हितधारकों से परामर्श कर लिया जाय ताकि योजना का लाभ शत–प्रतिशत प्राप्त किया जा सके।

जन मानस का सुझाव/टिप्पणी प्राप्त करने हेतु परामर्शी से प्राप्त विस्तृत योजना प्रतिवेदन को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर एक विशिष्ट ई–मेल आईडी/फेसबुक/वाट्सअप (सोसल मिडिया) सृजित किया जाना है। इसका प्रचार–प्रसार समाचार पत्र के माध्यम से करते हुए Request for Response (RFR) आमंत्रित किया जाना है। इस कार्य हेतु मुख्य अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं योजना आयोजन को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है तथा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन बिहारशरीफ तथा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के प्रमंडलों को सम्बद्ध किया गया है। यह कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

तदोपरांत इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1893 करोड़ की सहायता के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

- **मोराटाल पईन सिंचाई योजना**

मोहाने नदी हजारीबाग जिला के चतरा से निकलकर गया जिले में प्रवेश करते हुए फलगू नदी में मिलती है। मोहाने नदी में फलगू नदी में मिलने के पूर्व बतसपुर ग्राम के निकट से मोराटाल पईन निकला हुआ है, जिससे मोराटाल आहर में पानी जमा किया जाता है तथा इस पानी से पईन के द्वारा उक्त ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाता है। वर्त्तमान में इस बिन्दु पर नदी में किसी तरह का डायभर्जन नहीं होने के कारण किसानों द्वारा नदी में बालू का मेड़ बनाकर पईन से पानी लेकर मोराटाल आहर में किसानों के द्वारा भर लिया जाता है तथा इससे सिंचाई किया जाता है। वर्त्तमान में मोराटाल पईन तथा इससे निःसृत छोटे–छोटे पईन तथा इसमें निर्मित पुल–पुलिया इत्यादि

जीर्ण–शीर्ण आवस्था में है, जिसके कारण किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण बोध गया प्रखंड में बतसपुर ग्राम के निकट मोहाने नदी पर वीयर का निर्माण, वीयर के अपस्ट्रीम में हेड रेगूलेटर का निर्माण तथा उससे निःसृत मोराटाल पईन एवं इसके वितरण प्रणालियों को पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण कार्य करने का निर्णय लिया गया है, कार्य की प्राक्कलित राशि रु० 4387.29 लाख है।

योजना के कार्यान्वयन से गया जिला के बोधगया, मानपुर, टनकुप्पा तथा खिजरसराय प्रखंड में कुल 99 अदद गाँव में सिंचाई सुविधा में बढ़ोत्तरी होगी। वर्त्तमन में लगभग 5900 हे० क्षेत्र में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाती है। इस योजना के कार्यान्वयन से 2550 हे० क्षेत्र में अतिरिक्त खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी फलस्वरूप कुल 8450 हे० क्षेत्र में खरीफ फसल हेतु सुनिश्चित् सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पायेगी।

इस योजना के अंतर्गत वीयर का निर्माण कार्य, 34 अदद शीर्ष नियामक का निर्माण तथा 16 अदद शीर्ष नियामक का पुनर्स्थापन कार्य, 10 अदद फॉल, 40 अदद पुल का निर्माण कार्य, 24 अदद क्रॉस ड्रेनेज का पुनर्स्थापन कार्य, बतसपुर ग्राम से बदाहपुर ग्राम तक 28.50 कि०मी० में मोराटाल पईन का पुनर्स्थापन कार्य तथा 6.50 कि०मी० में पईन का बढ़ोत्तरी कार्य, मोराटाल पईन से निःसृत 30 अदद शाखा पईनों का पुनर्स्थापन कार्य, मोराटाल पईन के 0.00 कि०मी० से 0.50 कि०मी० तक लाईनिंग कार्य, आंशिक भू–अर्जन कार्य, वीयर के अपस्ट्रीम में गाईड बांध के साथ सुरक्षात्मक कार्य का प्रावधान है। इस योजना को मार्च, 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- <u>नदी जोड योजना</u> :–

विभाग राज्य की नदियों को आपस में जोड़कर नई योजनाओं के सृजन एवं कार्यान्वयन पर गंभीरता से कार्य कर रहा है। इन योजनाओं में सिंचाई के साथ बाढ़ प्रबंधन की अपार संभावनाएँ हैं। इस क्रम में कोशी बेसीन से पूर्व महानन्दा बेसीन में बीच की नदियों को जोड़कर जलान्तरण करने की एक महत्वाकांक्षी योजना – कोशी–मेची–लिंक योजना है। इसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्राप्त हुई है कि इस पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। योजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन एवं आवश्यक

प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य परामर्शी द्वारा पूरा कर लिया गया है एवं पब्लिक हियरिंग का कार्य अररिया, सहरसा, सुपौल एवं किशनगंज जिला में पूर्ण कर लिया गया है। पूर्णिया जिला में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रारंभ नहीं हो सका है। इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज एवं पूर्णिया जिले के 2,11,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

कोसी मेची लिंक योजना के अतिरिक्त एक अन्य योजना सकरी नदी पर बकसोती बराज से नहर निकालकर अहर–पईन को इंटीग्रेट करते हुए नाटा नदी में जलअंतरण की योजना का योजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इस योजना में सकरी नदी पर बकसोती बराज का निर्माण कर 20000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ वर्ष 1958 से कार्यरत पौरा (सकरी नदी) वीयर योजना में जल का उपलब्धता बढ़ाने के साथ–साथ 31,370 हेक्टेयर सी0सी0ए0 में सिंचाई सुविधा को पुनर्स्थापित किया जाना है। उसी प्रकार नाटा नदी पर निर्मित वीयर को बराज में उन्नयन कर 17,438 हेक्टेयर सी0सी0ए0 में सिंचाई सुविधा पुनर्स्थापित किया जाना है। इस योजना से कुल 68,808 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी जिसका लाभान्वित क्षेत्र नवादा, नालंदा, शेखपुरा एवं जमुई जिला होगा। इस योजना पर केन्द्रीय जल आयोग के निदेशानुसार झारखण्ड सरकार से अंतर्राज्यीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्रीय जल आयोग में यह योजना की स्वीकृति की लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है एवं स्वीकृति के अंतिम चरण में है।

- **सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट से निःसृत शोधित जल का सिंचाई में उपयोग**

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गंगा की अविरलता एवं निर्मलता बनाये रखने हेतु निदेश दिया गया कि शहरो में निर्मित होने वाले Sewerage तथा Storm Water Drainage के जल को शोधित कर यथा संभव सिंचाई कार्य में उपयोग किया जाये एवं किसी भी परिस्थति में शोधित जल को नदियों में नही गिराया जायेगा।

उपर्युक्त निदेश के क्रम मे निर्णय लिया गया की पटना में नगर एवं आवास विभाग द्वारा निर्मित होने वाले 100 एम0एल0डी0 से अधिक क्षमता के सभी Sewerage Treatment

Plant (एस0टी0पी0) के effluent का सिंचाई में व्यवहार करने के संबंध में डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जायेगा।

जल संसाधन विभाग द्वारा इस दिशा में पटना के बेऊर, करमलीचक, सैदपुर, कंकड़बाग एवं पहाड़ी में अवस्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के शोधित जल का उपयोग सिंचाई में करने हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य परामर्शी M/s. Samarth Infra Tech. Services Pvt. Ltd., Pune को सौंपा गया है। साथ ही पटना के दीघा स्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के शोधित जल का उपयोग सिंचाई में करने का डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु परामर्शी के चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- **केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रॉश की राशि**

PMKSY/AIBP अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं में वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा रू 857.901 करोड़ की अनुशंसा की गयी थी। इसके विरूद्ध अब तक रू 87.833 करोड़ प्राप्त किया जा सका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005–06 से 2011–12 तक कुल स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता राशि रू 737 करोड़ भी बकाया है।

AIBP अंतर्गत FMP योजनाओ में विगत 6 वर्षो में कुल 248.96 करोड़ केन्द्रांश राशि बकाया है।

AIBP योजनाओ अंतर्गत केन्द्रांश की राशि प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष विहित प्रपत्र में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है। केन्द्रीय सहायता राशि प्राप्त करने की दिशा में विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है।